बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 28

विश्वास का कारोबार

बीते एक पखवाड़े में जो कुछ इंडसइंड बैंक में घटित हुआ उसने आंतरिक प्रबंधन और नियामकीय निगरानी से जुड़े कई सवाल खड़े किए हैं। पहला, बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) सुमंत कठपालिया को केवल एक साल के लिए दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बैंक के बोर्ड ने तीन साल के लिए मंजूरी दी थी। यह पहला मौका नहीं है, जब नियामक ने बोर्ड की फरमाइश से कम समय के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। पहले भी बोर्ड ने तीन साल के लिए नियुक्ति मांगी थी मगर रिजर्व बैंक ने केवल दो साल की इजाजत दी। लेकिन यह तो शुरुआत थी। बाद में बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को डेरिवेटिव्स के लेखा में गड़बड़ी की सूचना दी। उसने बताया कि आंतरिक समीक्षा के मुताबिक उसकी शुद्ध संपत्ति के 2.35 फीसदी के बराबर गड़बड़ी है। अब बैंक को करीब 1,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी।

इस तरह की जानकारी बाजार के लिए कभी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब स्टॉक एक्सचेंजों पर बैंक की कीमत एक ही दिन में एक चौथाई से ज्यादा घट गई। बैंकिंग भरोसे का कारोबार है और खराब आंतरिक नियंत्रण तथा प्रबंधन दर्शाने वाली ऐसी घटनाएं हमेशा हितधारकों के भरोसे पर चोट कर सकती हैं। निवेशकों ने अपनी घबराहट और बेचैनी शेयर बेचकर जाहिर की। जमाकर्ता भी अगर ऐसा ही करते तो मामले और भी पेचीदा हो जाता। शायद इसी से डरकर रिजर्व बैंक ने होली वाले सप्ताहांत पर बयान जारी किया कि बैंक स्थिर है और जमा करने वालों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के प्रवर्तकों ने जरूरत पड़ने पर और पूंजी डालने की बात भी कही है। चूंकि जमा की सुरक्षा के बारे में कोई फौरी चिंता नहीं है, इसलिए लोग दो बड़े मसलों पर चर्चा कर रहे हैं।

बैंक ने समस्याओं की समीक्षा बाहरी एजेंसी को सौंपी है मगर खबरों से लगता है कि बैंक ने विदेशी मुद्रा में अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए जो डेरिवेटिव पोजिशन लीं, उन्हीं से गड़बड़ी उत्पन्न हुई। समस्या इसलिए हुई क्योंकि परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन तथा ट्रेजरी डेस्क ने जोखिम से बचने के अलग-अलग तरीके अपनाए। खजाने की पोजिशन का मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से जोड़ दिया गया मगर दोनों के बीच आंतरिक अनुबंध में ऐसा नहीं किया गया, जिससे गड़बड़ हुई। कठपालिया ने कहा है कि रिजर्व बैंक के सितंबर 2023 के सकुर्लर के बाद बैंक ने अपने बही खातों का जायजा लेना शुरू किया और गड़बड़ पता चली। सर्कुलर के अनुसार ऐसे आंतरिक सौदों को 1 अप्रैल 2024 से समाप्त होना था। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई और बैंक के ऑडिटरों तथा नियामकों को इसका पता था या नहीं। ये पहलू स्पष्ट किए जाने चाहिए।

दूसरा बड़ा मुद्दा बैंकों में एमडी और सीईओ की नियुक्ति का है। अगर नियुक्ति की शर्तों पर नियामक और बैंक बोर्ड में मतभेद है तो बाजार को बताया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 3 साल के लिए दोबारा नियुक्ति के लायक नहीं है तो वह 2 साल या 1 साल के लिए लायक कैसे होगा? ऐसे निर्णय बैंक के प्रबंधन में भरोसा कम कर सकते हैं, जिसका बुरा असर हो सकता है। विनियमित संस्थाओं से निश्चित ढर्रे में काम करने की उम्मीद की जाती है और समय के साथ खुलासों का स्तर भी बढ़ा है मगर अब वक्त आ गया है कि नियामक अपने निर्णयों के पीछे काम करने वाले तर्क भी बताएं। इससे खुलासों और निर्णय प्रक्रिया का स्तर सुधरेगा।

(डिस्क्लेमरः कोटक समूह के नियंत्रण वाली इकाइयों की बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी है)

अजय मोहंती

पर्यावरण के अनुकूल और अधिक स्वीकार्य जीएसटी

जीएसटी दरों को व्यावहारिक बनाने, उनका विस्तार करने का काम मात्र सरलीकरण के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने और पर्यावरण के लक्ष्य हासिल करने के लिए भी होना चाहिए। बता रहे हैं वीएस कृष्णन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के करीब 8 साल बाद हम गर्व कर सकते हैं इससे पूरे देश में एक जैसा कर लग रहा है और माल की आवाजाही में आंतरिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। साथ ही तीन कारोबारी कवायदों - पंजीकरण, कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करना - को ऑनलाइन अंजाम देने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। ये बड़ी उपलब्धियां हैं मगर अब जीएसटी दरों का ढांचा सरल बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क दरें सही करने की जरूरत है, जो जीएसटी के पहले के 14.8 फीसदी से घटकर 12 फीसदी रह गई हैं। दरें दुरुस्त करने के इस मौके का इस्तेमाल रोजगार बढ़ाने और पर्यावरण प्रदूषण घटाने जैसे दूसरे आर्तिक लक्ष्य हासिल करने के लिए भी होना चाहिए। आज रोजगार सृजन नीति निर्माताओं के लिए बड़ी समस्या है। इस बात पर भी काफी हद तक सहमति है कि रोजगार बढ़ाना है तो श्रम के ज्यादा इस्तेमाल वाले चार विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि जरूरी है। ये क्षेत्र हैं टेक्सटाइल्स (धागे से लेकर कपास और कृत्रिम कपड़े तक), चमड़ा और जूते-चप्पल, खाद्य प्रसंस्करण और खिलौने। इसलिए दरें सही करनी हैं तो पहले इन चारों उत्पाद श्रेणियों को 5 फीसदी जीएसटी दर में लाना होगा और उसे बढ़ाकर कम से कम 8 फीसदी करना होगा ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना किसी दिक्कत के मिलता रहे। इसके साथ ही इन चारों में एकबारगी इस्तेमाल वाली सभी सामग्री और मध्यवर्ती सामग्री पर शून्य कर लगना चाहिए। आयात शुल्क की यह व्यवस्था सर्वाधिक पसंदीदा देशों की श्रेणी में आने वाले सभी देशों से हो रहे आयात पर लागू हो। इससे श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले इन उद्योगों को ताकत मिलेगी और इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आएगा, जिसका अभी तक इंतजार ही हो रहा है।

जीएसटी की 12 फीसदी दर को 18 फीसदी की मानक दर में मिलाना होगा मगर ऐसा करने के पहले वस्त्र एवं औषधि क्षेत्र को 8 फीसदी दर में लाना होगा। रियायतें भी खत्म करनी होंगी ताकि जीएसटी श्रृंखला में क्रेडिट बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि जीएसटी से छूट उन्हीं को और उतनी ही मिले, जिन्हें और जितनी पहले मूल्यवर्द्धित कर (वैट) से मिलती थी। यह सुझाव 2015 में एक समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट में दिया गया था जिसका गठन दोहरे नियंत्रण, पूंजी सीमा और व्यय के लिए किया गया था। सभी उपकर हटाने और 28 फीसदी दर को बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। सरलीकरण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। इसके लिए जरूरी है कि सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जाए (जिससे काफी राजस्व हानि होगी)। दोपहिया और वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर तथा एयर कंडीशनर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर अभी 28 फीसदी कर लगता है, जो ठीक नहीं है। सीमेंट पर कर घटाने से निर्माण कार्य भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे।

जीएसटी दरों को दुरुस्त करते समय उन्हें पर्यावरण के अनुकूल भी बना देना चाहिए। इसके लिए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 28 फीसदी के बजाय 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। मगर ऐसे में शुल्क की दरें वाहन की क्षमता और आकार देखकर तय नहीं की जाएंगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एकबारगी इस्तेमाल होने वाली सभी पूंजीगत वस्तुओं और घटकों पर केवल 8 फीसदी कर लगना चाहिए। 28 फीसदी कर श्रेणी से वस्तुएं हटाने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर बगैर उपकर के 45 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए।

राजस्व क्षति से निपटने के लिए सोने और चांदी के उत्पादों पर कर की दर 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने का सुझाव है। 2015 में पेश जीएसटी रिपोर्ट में एनसीएआर के एक अध्ययन का जिक्र है, जिसके अनुसार सोने, चांदी के 90 फीसदी से ज्यादा सौदे आय के लिहाज से ऊपर की दो श्रेणियों में होते हैं।

इस हिसाब से कर व्यवस्था में उन वस्तुओं को कर छूट मिलेगी, जिन्हें वैट व्यवस्था में भी छूट थी। इसके अलावा 8 फीसदी, 18 फीसदी और 45 फीसदी की जीएसटी दरें होंगी। मगर जरूरी है कि सरकार एक ही उत्पाद श्रेणी पर मूल्य के हिसाब से दो तरह की कर दरें नहीं थोपे। इससे पेचीदगी बढ़ती है और अधिकारी लोगों को परेशान करने का मौका ढूंढ लेते हैं।

जीएसटी के दायरे में वस्तुएं बढ़ानी हैं तो राज्यों के बीच सहमति के साथ चरणबद्ध तरीके से यह काम किया जाए। पहले चरण में विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को ही जीएसटी के दायरे में लाया जाए क्योंकि उनका इस्तेमाल आम तौर पर मध्यवर्ती के रूप में होता है और कंपनियां आपस में ही इनका कारोबार कर लेती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को जीएसटी में लाने के लिए राज्यों से मशविरा किया जा सकता है। इससे क्षेत्र को मदद मिलेगी क्योंकि इसमें पूंजी बहुत लगती है और परिचालन लागत बहुत कम होती है। इन्हें जीएसटी में लाने से ये उपकरण बनाने वाली कंपनियों को बिजली उत्पादन के अंतिम चरण तक जीएसटी क्रेडिट लेने में मदद मिलेगी।

जीएसटी दरें व्यावहारिक बनाने के इन सुझावों से आम आदमी द्वारा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे दवा, कपड़े, जूते-चप्पत और किफायती मकान पर कम कर लगेगा। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी और मध्य वर्ग को आसानी से मिल सकेंगी। औसत शुल्क दर में भी इजाफा होगा और वह वर्तमान 12.2 फीसदी से बढ़कर 13 फीसदी हो जाएगी। इससे राजस्व बढ़ेगा मगर कर का बोझ समाज के समृद्ध वर्ग पर ही पड़ेगा।

अंत में जीएसटी दरों को व्यावहारिक बनाने और उनका दायरा बढ़ाने का काम ऐसे हो कि प्रणाली सरल बनने के साथ ही रोजगार तथा पर्यावरण के लक्ष्य भी हासिल किए जा सकें। इससे लोगों में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और यह धारणा बढ़ेगी कि जीएसटी आजाद भारत का सबसे अहम आर्थिक सुधार है।

(लेखक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं)

ट्रंप के शुल्कों से ध्वस्त होती वैश्विक व्यवस्था

कोई नहीं बता सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे या कहेंगे। मगर दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनसे कट्टर नीति निर्माता, कारोबारी, व्यापारी, निवेशक, राजनेता और अफसरशाह हैरत में पड़ गए हैं। अभी तो उन्हें व्हाइट हाउस में 46 महीने और रहना है। जो कुछ हो रहा है उसका अंदेशा मुझे पहले से ही था। पिछले साल अक्टूबर के अंत और नवंबर के शुरू में अपने तीन आलेखों में मैंने भारत में आर्थिक सुस्ती होने और शेयर बाजार में कमजोरी आने का साफ संकेत दिया था। नवंबर मध्य में मैंने चौथा आलेख 'शेयर बाजार में आशंका के गहराते घने बादल' भी लिखा था। ट्रंप तब चुनाव जीत चुके थे और मैंने कहा था, 'यह मानना आत्मघाती होगा कि ट्रंप के वादे सियासत में फंस जाएंगे या वाशिंगटन में बैठी लॉबियों तथा डीप स्टेट के सामने बौने साबित हो जाएंगे। ट्रंप ने जितनी बातें (ट्रंपोनॉमिक्स) कही हैं उनका एक हिस्सा भी लागू हो गया तो दुनिया में भारी उथल-पुथल मच जाएगी और कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था इससे बच नहीं पाएगी।' अब तक तो ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा, मेक्सिको और चीन पर शुल्क थोप चुके ट्रंप के निशाने पर अब यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और भारत हैं।

लगता तो यही है कि ट्रंप की नीति आक्रामक, सीधी, अस्थिर, देश के हित साधने वाली और पहले से अलग है। जिस देश का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है वह ट्रंप की नजर में 'अमेरिका को धोखा दे रहा है'। उनका कहना है कि ऐसे देशों को अमेरिकी बाजार में माल बेचने के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। उसके बाद बराबरी के शुल्क हैं - अमेरिकी निर्यातकों से जिस सामान पर कोई देश जितना शुल्क लेता है, उसके निर्यातकों से भी उस सामान पर उतना ही शुल्क वसूला जाएगा। अनुमान है कि इससे 23 लाख वस्तुओं और सामान पर शुल्क की सूची तैयार हो जाएगी। ट्रंप की धमकी कितनी गंभीर है और हम पर कितना असर डाल सकती है? ट्रंप की इन हरकतों की वजह आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया स्टीफन मिरान हैं। पिछले साल नवंबर में एक शोध पत्र में उन्होंने सलाह दी थी कि ट्रंप प्रशासन निर्यात बढ़ाने के लिए डॉलर को कमजोर होने दे, देसी विनिर्माण बढ़ाने के लिए ऊंचे शुल्क लगाए और दूसरे देशों से अमेरिकी बॉन्ड के लिए भुगतान कराए या उन्हें 100 साल के बॉन्ड के बजाय छोटी अवधि के बॉन्ड लेने के लिए कहे।

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

ट्रंप विश्व व्यापार को तहस-नहस करने में लगे हैं, जिसके असर बहुत घातक होंगे। वैश्वीकरण, वृद्धि एवं विकास में माहिर अर्थशास्त्री डानी रॉड्रिक ने लिखा, 'दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि आई है। इसकी बराबरी न तो औद्योगिक क्रांति कर सकती है और न ही 19वीं सदी में शुरू हुआ वैश्वीकरण।' यह शानदार वृद्धि एशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते विश्व व्यापार तथा यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार के कारण आई, जिसे सौदों की कम लागत और कम शुल्क ने मुमकिन किया। पूर्वी एशिया के देश जैसे जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर कम लागत का फायदा उठाने में जुटे तो विकसित देशों को उनका निर्यात बढ़ता गया। निर्यातक देशों की इस टोली में चीन 1990 के दशक के अंत में शामिल हुआ मगर 2001 में विश्व व्यापार संगठन में जाने के बाद वह पूरी दुनिया का कारखाना ही बन गया। इसके बाद निर्यातकों ने उनके बाजारों के निकट (चीन ने अमेरिकी बाजार के लिए मेक्सिको में) अपने केंद्र स्थापित किए। कम लागत का फायदा उठाने के लिए भी उन्होंने (चीन ने वियतनाम या थाईलैंड में, दक्षिण कोरिया और जापान ने मलेशिया में) कोई कसर नहीं छोड़ी।

विश्व व्यापार में तेजी आई और उसी समय युद्ध के बाद के काल में अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बनता गया। दुनिया में लगभग आधा व्यापार डॉलर में होता है। चूंकि ज्यादातर एशियाई निर्यात अमेरिका को ही जाता था, इसलिए वहां से हुए फायदे या व्यापार अधिशेष को ये देश अमेरिकी सरकारी बॉन्डों में ही निवेश कर देते थे। इससे अमेरिका और बॉन्ड जारी करता रहा तथा विनिमय दर बिगाड़े बगैर इन देशों से आयात के लिए रकम जुटती गई। इसीलिए ट्रंप यदि विश्व व्यापार की कड़ियां खत्म करेंगे तो डॉलर में बहुत उठापटक होगी। शुल्क उसे ऊपर ले जाएंगे और उन शुल्कों की वजह से धीमी पड़ी वृद्धि उसे नीचे गिराएगी। इसके अलावा कई और वजहों से भी उठेगा या गिरेगा। उठापटक इसलिए भी होगी क्योंकि ट्रंप अमेरिका के लगभग सभी सहयोगियों के साथ झगड़ रहे हैं। डॉलर दुनिया की आरक्षित संपत्ति है, जिससे अमेरिका को अपनी ताकत जाहिर करने में मदद मिलती है। दुनिया भर में उसके सैन्य ठिकाने और अड़ियल सरकारों पर सख्त वित्तीय प्रतिबंध लगाने की उसकी क्षमता इसका सबूत है। ट्रंप ने जापान से यूरोप तक के देशों को अमेरिकी सुरक्षा खत्म कर दी है और खुल्लमखुल्ला रूस के साथ खड़े हो गए हैं, जो चीन, उत्तर कोरिया और ईरान वाली धुरी का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप वैश्विक व्यापार, वैश्विक निवेश, डॉलर और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को एक साथ उलट देना चाहते हैं।

इसके नतीजे बरबादी से कम नहीं होंगे। भारत जैसे कमजोर और छोटे देशों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगी। तमाम विकासशील देशों की तरह भारत के लिए भी अमेरिका सबसे महत्त्वपूर्ण बाजार है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की 9 फीसदी हिस्सेदारी है वस्तु निर्यात में 18 फीसदी। ट्रंप की नई व्यापार नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी जुड़ा है। वह कई जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और दवा भी इनमें से एक है। भारत ने 2023 में अमेरिका को 10 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की दवा निर्यात की थीं। भारत ने 2023 में अमेरिका को 23 अरब डॉलर मूल्य की सॉफ्टवेयर सेवा भी निर्यात की थीं। हालांकि ट्रंप की टीम में मौजूद तकनीकी लोग एच1बी वीजा (जिसके जरिये भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में काम करते हैं) के हिमायती हैं मगर आव्रजन विरोधी ट्रंप समर्थक इसके सख्त खिलाफ हैं। ये दोनों भारत के लिए सबसे ज्यादा रोजगार तैयार करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत की सबसे अच्छी कंपनियों में ज्यादातर अमेरिका को निर्यात करती हैं। उन सभी को खतरा होगा। जब तक कुछ बदलता नहीं तब तक ट्रंप बड़ा खतरा हैं, जिसका अंदाजा शायद अभी हमें पूरी तरह लगा नहीं है।

(लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक एवं मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं)

आपका पक्ष

जलवायु परिवर्तन के प्रति सभी देश हों गंभीर

रिकॉर्ड गर्मी और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने विश्व के समक्ष एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से आगे बढ़ते इस जलस्तर ने समुद्र किनारे बसे शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। पिछले 40 वर्षों में समुद्र का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है जो कि एक खतरनाक संकेत है। इस बढ़ते जलस्तर के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इस बढ़ते जल स्तर के कारण समुद्र किनारे बसे शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। यदि यह जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा, तो समुद्र किनारे बसे शहरों में बाढ़ और तूफान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विभिन्न देशों ने समझौते किए हैं, जिनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण है पेरिस समझौता। इस समझौते के तहत विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अपने उत्सर्जन को कम करने का वचन दिया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग करने का फैसला किया है। यह फैसला जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। यह आवश्यक है कि हम जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एकजुट हों।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 40 वर्षों में समुद्र का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है जो एक खतरनाक संकेत है

वन हैं तो हम हैं, एक पेड़ जरूर लगाएं

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 28 नवंबर, 2012 को हर वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, तब से हर वर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाया जाता आ रहा है। वन हैं तो हम हैं, जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, वे भी बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह ऑक्सीजन देते हैं। देश में बहुत पहले से ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ किए गए थे। वर्ष 1950 में वनों को बचाने के लिए 'वन महोत्सव' की शुरुआत हुई थी। वहीं वर्ष 1970 के दशक में गढ़वाल के लोगों ने चिपको आंदोलन आरंभ किया था। आज विकास के नाम पर वृक्षों को काटा जा रहा है। अगर देश में इसी तेजी से वनों की कटाई होती रही तो जंगल खत्म हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने घर पर तुलसी, एलोवीरा, पुदीना, धनिया या फिर अन्य फूलों के पौधे लगाएं तो भी देश में हरियाली बढ़ सकती। इसके अलावा लोगों को अपने फैक्टरी, स्कूल, अस्पताल या अन्य स्थालों पर फल, फूल, नीम आदि के पौधे लगाकर प्रकृति को हराभरा बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। अगर देश के हर शहर के लोग अपनी घर के छत पर किसी भी तरह का छोटा-सा पौधा लगाए और उसकी देखभाल की जाए, तो देश में पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर और बोलीविया की विदेश मंत्री सेलिंडा सोसा ने गुरुवार को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। बैठक में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल में ही ला पाज में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया था।

चिंतन

परिसीमन पर डीएमके का वितंडा निरर्थक

परिसीमन और हिन्दी भाषा पर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके का विवाद खड़ा करना राज्य के विकास से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक या डीएमके) के सदस्य बृहस्पतिवार को प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर संसद के दोनों सदनों में पहुंच गए, जिस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। परिसीमन के मुद्दे पर सदन को बाधित करना कहीं से भी उचित नहीं है, अभी परिसीमन प्रारंभ भी नहीं हुआ है, वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उन प्रदेशों को लोकसभा सीटों के संदर्भ में नुकसान होगा, जिन्होंने प्रभावी ढंग से जनसंख्या नियंत्रण किया है। पिछले सप्ताह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन दिया था कि यदि परिसीमन किया जाता है, तो उन्हें एक भी संसदीय सीट नहीं खोनी पड़ेगी। तमिलनाडु को केंद्र पर भरोसा करना होगा। राजनीति के लिए केंद्र से टकराव संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आगे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, तो डीएमके प्रमुख व सीएम एमके स्टालिन की कवायद तमिल स्मिता को भड़का कर फिर से सत्ता पाने की है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला है, इसलिए तमिल को कोई खतरा नहीं है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर नई शिक्षा नीति में हिन्दी नहीं थोप रही है। संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में हिंदी भी है और तमिल भी। तमिल संस्कृत की तरह प्राचीन भाषा है। डीएमके करुणानिधि के वक्त से ही फ्रीबिज और तमिल अस्मिता की राजनीति करती रही है, जिसमें तमिल हिंदी व हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगैंडा शामिल है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एमके स्टालिन के हिंदी विरोध को खारिज किया है और हिंदी की व्यापकता से किसी भी राज्यीय व अन्य भारतीय भाषा को खतरा नहीं होने की बात कही है। कला क्षेत्र से बात निकली है कि अगर हिंदी विरोध इतना सशक्त है तो तमिल फिल्मों का हिंदी डब क्यों होता है, जो बड़ा बाजार है। तमिल भाषा की रक्षा का दायित्व डीएमके का नहीं है, यह समस्त तमिल भाषी लोगों का है। इसके ठेकेदार बनने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जब डीएमके नहीं बनी थी, तब भी तमिल भाषा थी। परिसीमन पर वितंडा खड़ा कर राजनीति करना डीएमके को ही नुकसान पहुंचाएगा। तमिलनाडु केवल डीएमके नहीं है। समृद्ध तमिलनाडु की एसजीडीपी में सतत कमी के लिए डीएमके और अन्ना डीएमके पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। परिसीमन व हिन्दी के नाम पर तमिलनाडु के विकास व रोजगार के प्रश्न को नहीं ढंका जा सकता है। लोकसभा सीटों का वर्तमान वितरण 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1976 में, आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसने 2001 की जनगणना तक 25 वर्षों के लिए संसदीय सीटों के संशोधन को रोक दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के जरिए इस प्रतिबंध को 2026 तक बढ़ा दिया था। दोनों संशोधनों के पीछे तर्क जनसंख्या नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना था। तमिलनाडु समेत सभी चिंतित राज्यों को वर्ष 2026 का इंतजार करना चाहिए। तब तक डीएमके के हायतौबा का कोई अर्थ नहीं है।

मानवयुक्त गगनयान

प्रमोद भार्गव

क्रायोजेनिक तकनीक में देश की छलांग

इस प्रौद्योगिकी के निर्माण में भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। यही वह इंजन है, जो मानव रेटेड एलवीएम-3 प्रक्षेपण वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ये सब तैयारियां भेजे गए इंसान को सुरक्षित रूप में वापस लाने के लिए की जा रही हैं। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक विपरीत परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। एक समय ऐसा भी था, जब अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। प्रक्षेपण यान का यही इंजन वह अश्व-शक्ति है, जो भारी वजन वाले उपग्रहों, अन्य उपकरणों और मानवों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. वी नारायण ने कहा है कि भारत उन छह देशों में से एक हैं, जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। अन्य पांच देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान हैं। आईआईटी मद्रास में नए शोध केंद्र के शुभारंभ पर नारायण ने आगे कहा कि इसरो के सीई-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटिंग हासिल कर ली है। मानव रेटिंग प्रक्रिया तय करती है कि मनुष्य को अंतरिक्षयान में लेकर उड़ान भरने वाली यह प्रणाली सुरक्षित है। यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है।

नारायण ने बताया कि एक समय क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भारत को अन्य देशों ने नहीं दी थी। परंतु आज हमारे पास तीन ऐसे इंजन हैं, जिनमें से तीसरा मानव रेटेट है। हमने इस प्रौद्योगिकी में तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इस अभियान को तीसरे प्रयास में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया गया था। इंजन के परीक्षण से लेकर उड़ान भरने तक यह अभियान 28 महीनों में पूरा किया, जबकि अन्य देशों को इसमें 42 महीनों से लेकर 18 वर्ष तक का समय लगा। परीक्षण में भी हमें मात्र 34 दिन लगे, जबकि अन्य देशों को परीक्षण पूरा करने में ही पांच से छह माह तक लगे हैं। अतएव इस प्रौद्योगिकी के निर्माण में भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। यही वह इंजन है, जो मानव रेटेड एलवीएम-3 प्रक्षेपण वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ये सब तैयारियां भेजे गए इंसान को सुरक्षित रूप में वापस लाने के लिए की जा रही हैं। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक विपरीत परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अन्यथा एक समय ऐसा भी था, जब अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। असल में किसी भी प्रक्षेपण यान का यही इंजन वह अश्व-शक्ति है, जो भारी वजन वाले उपग्रहों, अन्य उपकरणों और मानवों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करते हैं। भारत ने शुरुआत में रूस से इंजन खरीदने का अनुबंध किया था, लेकिन 1990 के दशक के आरंभ में अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का हवाला देते हुए इसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी। इसका असर यह हुआ कि रूस ने तकनीक तो नहीं दी लेकिन छह क्रायोजेनिक इंजन जरूर भारत को शुल्क लेकर भेज दिए। कालांतर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद से भारत को एमटीसीआर क्लब की सदस्यता भी मिल गई, लेकिन इसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों के कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते स्वदेशी तकनीक के बूते चरणबद्ध रूपों में इंजन को विकसित कर लिया गया।

मानव मिशन की इस उड़ान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण इसरो पहले ही कर चुका है। देश के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान से जुड़े पैलोड के साथ उड़ान भरने वाले परीक्षण यान के असफल होने की स्थिति में क्रू मॉड्यूल अर्थात जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे, को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद वापस सुरक्षित लाने के लिए 'क्रू एस्केप सिस्टम' यानी चालक दल बचाव प्रणाली (सीईएस) का सफल परीक्षण कर इसरो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इस बचाव प्रणाली की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि यान के असफल होने पर कई वैज्ञानिक प्राण गंवा चुके हैं। गगनयान परियोजना के तहत इसरो मानव चालक दल को 400 किमी ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। बाद में सुरक्षित पृथ्वी पर वापस समुद्र में उनकी लैंडिग कराई जाएगी। अतएव भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में उनके लिए लक्ष्य भी तय कर दिए हैं कि 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो तथा 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम पड़ जाएं। अब तक भारतीय या भारतीय मूल के तीन वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष जा चुकी हैं। हालांकि पूर्व में भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की घोषणा की थी। लेकिन इस पर समय रहते क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में मानवरहित और मानवचालित दोनों तरह के यान भेजे जाएंगे। पहले चरण में योजना की सफलता को परखने के लिए अलग-अलग समय में दो मानव-विहीन यान अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। इनकी कामयाबी के बाद मानव-युक्त यान अपनी मंजिल का सफर तय करेगा। यह सावधानी इसलिए बरती जा रही है, क्योंकि अमेरिकी मानव मिशन की असफलता के चलते भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं।

मानव युक्त गगनयान की कामयाबी के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि इन्हीं देशों ने अब तक अंतरिक्ष में अपने मानवयुक्त यान भेजने में सफलता पाई है। भारत ने अब अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की पहल कर दी है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले गगनयान का भार 7 टन, ऊंचाई 7 मीटर और करीब 4 मीटर व्यास की गोलाई होगी। 'गगनयान' जीएसएलवी (एमके-3) रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद 16 मिनट में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसे धरती की सतह से 400 किमी की दूरी वाली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। सात दिन तक कक्षा में रहने के बाद गगनयान को अरब-सागर, बंगाल की खाड़ी अथवा जमीन पर उतारा जाएगा। इस संबंध में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेष शर्मा से भी मदद ली जा रही है। भारत पहले दो गगनयान-अभियान मानवरहित भेजेगा। दरसअल अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों पर यानों को भेजने की प्रक्रिया बेहद जटिल और शंकाओं से भरी होती है। यदि अवरोह का कोण जरा भी डिग जाए या फिर गति का संतुलन थोड़ा सा ही लड़खड़ा जाए तो कोई भी अंतरिक्ष-अभियान ध्वस्त हो जाता है या अंतरिक्ष में कहीं भटक जाता है। भारत ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की दृष्टि से श्रीहरिकोटा में जीएसएलवी मार्क-3 को स्थापित करने की तैयारी शुरू की हुई है। इसरो ने परीक्षण के तौर पर क्रू एस्केप मॉड्यूल का पहला पड़ाव पार कर लिया है और अब मानव रेटेट क्रायोजेनिक इंजन भी तैयार भी हो गया है। बहरहाल, अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के सफल होने के बाद ही चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने का रास्ता खुलेगा। इन पर बस्तियां बसाए जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन के भी बढ़ने की उम्मीद है। इसरो की यह सफलता अंतरिक्ष पर्यटन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। यह अभियान देश में अंतरिक्ष शोधकार्यों को बढ़ावा देगा। साथ ही भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रोद्यौगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का तो यहां तक दावा है कि दवा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन तथा पानी एवं खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में भी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे।

(लेखक साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विश्व जल दिवस

पंकज चतुर्वेदी

भविष्य के लिए पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी

जाम्बा, करनाल से कैथल जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक संपन्न गांव है। कोई 1250 की आबादी वाले पूरे गांव में 242 घर हैं और सभी पक्के हैं। यहां 'हर घर जल की सरकारी योजना के तहत प्रत्येक घर तक पानी की लाइन है। गांव में ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा ने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। एक कर्मचारी सुबह-शाम एक-एक घंटा इसे चला कर घरों तक पानी पहुंचाता है। पानी को क्लोरिन से शुद्ध किया जाता है। सरकार इसके लिए महज चालीस रुपये महीना लेती है और वह भी कई ग्रामीण चुकाते नहीं। गांव वालों की शिकायत है कि पानी कम आता है। हकीकत तो यह है कि दिन में दो घंटे मोटर चलने से एक आठ लोगों के परिवार के पीने, रसोई, नहाने का पानी पर्याप्त पहुंच जाता है। असल में हर घर में मवेशी पले हैं और अब ग्रामीण चाहते हैं कि ढोर के नहलाने का पानी भी नल से ही आए। यह पूरी सरकारी योजना जिस भूजल पर टिकी है, असल में वह किसी भी दिन धोखा दे सकती है। जाम्बा को ही क्यों कोसें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को इस बात के लिए गर्व से प्रचारित किया जाता है कि वहां घरों में गंगा-वाटर आता है। ऐसे इलाकों में फ्लेट के दाम इस कारण अधिक होते हैं। जिस गंगा जल को घरों में एक बोतल में पवित्र निशानी की तरह रखा जाता है, वह गंगा जल लाखों घरों में शौचालय से लेकर कपड़े धोने तक में इस्तेमाल होता है। कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक ताजा शोध बताता है कि सन 2030 तक हमारे धरती के तापमान में 0.5 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि अवश्यंभावी है। साल-दर-साल बढ़ते तापमान का प्रभाव सन 2050 में 0.80 से 3.16 और सन 2080 तक 1.56 से 5.44 डिग्री हो सकता है। जान लें कि तापमान में एक डिग्री बढ़ोतरी का अर्थ है कि खेत में 360 किलो फसल प्रति हैक्टेयर की कमी आ जाना। इस तरह जलवायु परिवर्तन के चलते खेती के लिहाज से 310 जिलों को संवेदनशील माना गया है। सामने दिख रहा है कि संकट अकेले पानी का ही नहीं है, अलग-अलग किस्म का पानी, अलग-अलग इस्तेमाल के लिए कैसे छांटा जाए, इस बारे में तंत्र विकसित करना और सबसे बड़ी बात इसके लिए जागरुकता फैलाना अनिवार्य है। भारत में जिस साल अल्प वर्षा होती है, उस साल भी इतनी कृपा बरसती है कि सारे देश की जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन हमारी असली समस्या बरसात की हर बूंद को रोक रखने के लिए हमारे पुरखों द्वारा बनाए तालाब-बावड़ी या नदियों की दुर्गति करना है। हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति जीवनदायी संपदा यानी पानी हमें एक चक्र के रूप में प्रदान करती है और इस चक्र को गतिमान रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति के खजाने से हम जितना पानी लेते हैं उसे वापस भी हमें ही लौटाना होता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइनों के वॉल्व की खराबी के कारण 17 से 44 प्रतिशत पानी प्रतिदिन बेकार बह जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रतिदिन 2.16 घन मीटर पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। भारत में हर वर्ष बाढ़ के कारण करीब हजारों मौतें व अरबों का नुकसान होता है। इजरायल में औसत बारिश 10 सेंटीमीटर है, इसके बावजूद वह इतना अनाज पैदा कर लेता है कि वह उसका निर्यात करता है। दूसरी ओर भारत में औसतन 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होने के बावजूद सिंचाई के लिए जरूरी जल की कमी बनी रहती है। यह भी कड़वा सच है कि हमारे देश में औरतें पीने के पानी के जुगाड़ के लिए हर रोज ही औसतन चार मील पैदल चलती हैं। पानीजन्य रोगों से विश्व में हर वर्ष 22 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पूरी पृथ्वी पर एक अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5 प्रतिशत पानी समुद्र में है जोकि खारा है, शेष 1.5 प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। बचा एक प्रतिशत पानी नदी, सरोवर, कुआं, झरना और झीलों में है। इस एक प्रतिशत पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योगों में खपत होता है। बाकी का 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने आदि में खर्च करते हैं। यदि ब्रश करते समय नल खुला रह गया है तो पांच मिनट में करीब 30 लीटर पानी बर्बाद होता है। यदि अभी पानी को सहेजने और किफायती इस्तेमाल पर काम नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार की हर घर नल जैसी योजनाएं जल-स्रोत ना होने के कारण रीती दिखेंगी। जान लें, पानी की कमी, मांग में वृद्धि तो साल-दर-साल ऐसी ही रहेगी। अब मानव को ही बरसात की हर बूंद को सहेजने और उसे किफायत से खर्च करने पर विचार करना होगा। इसमें अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा मसला है। जितना अन्न बर्बाद होता है, उतना ही पानी जाया होता है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

निंदा का परित्याग

संकलित

दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं दूसरे को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है, जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन-प्रतिदिन इसके पाश में जकड़ता चला जाता है। मनीषियों ने निंदा को दुर्व्यसन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि 'वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता।' आचार्य बोले, 'तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं।' इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, 'वह कैसे?' आचार्य बोले, 'क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर, दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो।'

दान की बड़ी महिमा

संकलित

प्रेरणा

एक बार राजा भोज एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। साथ में उनके राजकवि पंडित धनपाल भी थे। रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ में मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता लगा था। जो शहद के भार से गिरने ही वाला था। राजा भोज ने ध्यान से देखा तो पाया कि मधुमक्खियां उस छत्ते से अपने हाथ पैर घिस रही हैं। उन्होंने राजकवि से इसका कारण पूछा। राजकवि बोले- महाराज ! दान की बड़ी महिमा है। शिवि, दधीचि, कर्ण, बलि आदि अनेक दानियों का नाम उनके न रहने के बाद भी चल रहा है। दधीचि ने तो वज्र बनाने के लिए इंद्र को अपना कंकाल तक दान कर दिया था। कर्ण को आज सभी सबसे बड़े दानी के रूप में जानते हैं। जबकि केवल संचय करने और दान न करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं का आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। इन मधुमक्खियों ने भी आजीवन केवल संचय ही किया है, कभी दान नहीं किया। इसलिए आज अपनी संपत्ति को नष्ट होते देखकर इन्हें दुःख हो रहा है। इसीलिए ये अपने हाथ पैर घिस रही हैं। अतः आवश्यकता से अधिक संचय हमेशा दुःख का कारण होता है। संचय किए हुए धन पर हमेशा राज दूसरे ही करते हैं, अतः कहा गया है की आप जितनी कमाई करते है उसका कुछ भाग अवश्य दान करे।

अंतर्मन

आज की पाती

वैश्विक होती दुनिया में पेड़

वैश्विक फलक पर सबसे अहम गणना, जनगणना मानी जाती है। हालांकि पालतू-पशु, वन्य जीव और वृक्षों की गिनती भी होती रही है, लेकिन इन्हें जनगणना के मुकाबले अहमियत नहीं दी जाती। यही वजह रही कि विश्व स्तर पर वृक्षों की, की गई गिनती के निष्कर्षों को समाचार माध्यमों ने उतना महत्व नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था, जबकि पेड़ों की अस्मिता पर ही मनुष्य व अन्य प्राणियों का जीवन टिका हुआ है। गोया, पेड़ एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है, जिसका यदि विनाश होता है तो मनुष्य का सुखद जीवन भी संभव नहीं है। जब से मानव सभ्यता के विकास का क्रम शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक वृक्षों की संख्या में 46 प्रतिशत की कमी आई है। आकलन है कि विश्व में तीन लाख करोड़ वृक्ष हैं। वन दिवस पर हमें पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। - मोहन कश्यप, सरायपाली

करंट अफेयर

टेक्सास की संसद ने पारित किया होली का प्रस्ताव

टेक्सास की संसद ने प्रमुख हिंदू त्योहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई है। इस कदम के साथ जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला टेक्सास, तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। यह प्रस्ताव सांसद सारा एकहार्ट ने पेश किया जिसे 14 मार्च को होली के ठीक पहले पारित किया गया। इस प्रस्ताव में होली के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रस्ताव में कहा गया है, 'इस उल्लासमय त्योहार की शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी। इस त्योहार को दुनिया में हर पृष्ठभूमि वाले वे लोग मनाते और मान्यता देते हैं जो इसे प्रेम, ऊर्जा और प्रगति का पर्व मानते हैं।' ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्यदूत मंजूनाथ ने बताया, ''यह टेक्सास के लिए गर्व और ऐतिहासिक क्षण है। राज्य सीनेट द्वारा होली को मान्यता देना विविधता, एकता, मित्रता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हम सीनेटर सारा एकहार्ट और उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को संभव बनाया...।' 'हिन्दू अमेरिकन फाउंडेशन' ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

ऑफ बीट

उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सबमें समान नहीं

आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे, जो अपनी वास्तविक उम्र से छोटा दिखाई देता होगा। इसी तरह आप ऐसे लोगों के भी संपर्क में आए होंगे, जो अपनी उम्र से काफी बड़े नजर आते हैं। क्या कारण है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हर व्यक्ति में समान नहीं होती? मैंने अपने पूरे करियर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया (एजिंग) पर अध्ययन किया है। मैं मिशिगन विश्वविद्यालय में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित कोशिकीय एवं आणविक विज्ञान का प्रोफेसर हूं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े अनुसंधान में ऐसा समाधान नहीं तलाशा जाता, जो ढलती उम्र में आपको होने वाली हर बीमारी से निजात दिला सके। बल्कि, पिछले एक या दो दशक में हुए शोध इस ओर इशारा करते हैं कि 'एजिंग' एक बहुकारकीय प्रक्रिया है और इसे महज एक उपाय से नहीं रोका जा सकता। 'एजिंग' क्या है? -एजिंग की अलग-अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर पर कुछ समान कारकों पर सहमत होते हैं : उम्र बढ़ने की प्रक्रिया समय पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति को बीमारियों, चोट और मौत के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

ट्रेंड

नई रोजगार योजना

किसी भी राष्ट्र की ताकत को उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और अनुशासन से मापा जा सकता है। हम नई स्कीम को लेकर आए है, जिससे उत्तर प्रदेश के युवा को प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

सामूहिक सहभागिता

दिल्ली के विकास के लिए सबका साथ और सामूहिक सहभागिता जरूरी है। जब हम मिलकर काम करेंगे, तभी हर समस्या का समाधान होगा और विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। आइए, एक साथ आगे बढ़े और दिल्ली को ऊंचाइयों तक ले जाएं!

-रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

भाजपा-आप किसान विरोधी

ऐसा लगता है कि दो किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में सांठगांठ कर ली है! पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर जबरन धरना स्थल से हटाया। भाजपा-आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही है।

-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

ओटीटी प्लेटफॉर्म

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बैंडिट क्वीन का सेंसर किया हुआ संस्करण काट दिया, मुझे यकीन भी नहीं है कि उन्हें कानूनी तौर पर ऐसा करने की अनुमति है.. उन्होंने बस फिल्म का अपना संस्करण पेश किया।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 21 मार्च 2025

क्लाइमेट चेंज के ख़तरे

विश्व मौसम संगठन की ताजा रिपोर्ट में यूं तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, जिसके बारे में पहले से अंदाजा न रहा हो, लेकिन यह एक बार फिर याद दिलाती है कि जीव जगत खतरनाक भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दस साल इस धरती पर अब तक के सबसे गर्म रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां बद से बदतर होती जा रही हैं।

AI Image

धरती पर रेकॉर्ड गर्मी

बढ़ती गर्मी | आम तौर पर माना जाता है कि इस ग्रह के निरंतर अधिकाधिक गर्म होते जाने का अहसास मानवीय चेतना के लिए एक नई बात है। लेकिन यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी के शुरुआती सालों में ही यह समझ लिया था कि मानवीय सभ्यता के केंद्र ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। उनके ध्यान में यह बात आ चुकी थी कि आसपास के देहाती इलाकों के मुकाबले शहरों में गर्मी ज्यादा होती है।

मारक रूप | गर्मी का मारक रूप भी तभी से दिखने लगा था। ऑस्ट्रेलिया में 1897 और लंदन में 1900 का साल गर्मी के लिहाज से खास माना गया था। कलकत्ता में 1905 में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो गर्मी के चलते कई यूरोपियंस की मौत भी दर्ज की गई थी। बाद के वर्षों में हालात लगातार गंभीर ही होते चले गए। 1962 से अब तक हिमालयी ग्लेशियरों का 30 फीसदी हिस्सा पिघल चुका है।

कमाई पर असर | क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान भी कम गंभीर नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 प्रमुख फसलों- मक्का, गेहूं, चावल, सोया, केला, आलू, कोको, कॉफी – की पैदावार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही नहीं, अगले 25 वर्षों में वैश्विक कमाई 19 फीसदी तक घटने की आशंका है। पॉट्सडैम इंस्टिट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के मुताबिक भारत में इन्हीं वजहों से कमाई में 25 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।

अब भी वक्त है | चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरह की गंभीरता हमारी सरकारों में दिखनी चाहिए, वह अब भी नहीं दिख रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप तो इन चिंताओं को सीधे तौर पर खारिज करते हैं। भारत सरकार ने जरूर इस पर गंभीरता दिखाई है। सबसे सकारात्मक बात यह है कि अभी भी अगर सही ढंग से प्रयास किए जाएं तो हालात सुधरने शुरू हो सकते हैं।

रोज़-ब-रोज़

कब आएं

शैलेंद्र पांडेय

'**बनारस कब** आएं कि भीड़भाड़ कम हो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन आराम से हो जाएं?' हर जानने वाला वह वक्त जानना चाहता है, जब उसे कम से कम भीड़ का सामना करना पड़े। बावजूद इसके, जब बाहर निकलो, तो लोगों का समुद्र टकरा ही जाता है। लगता है कि सभी यही सवाल पूछकर घर से निकलते हैं। नापने का अगर कोई जरिया होता, तो महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल में यह टॉप पर आता, कि कब आया जाए? जो एक बार इन जगहों पर चला जाता है, वह खुद को टूरिस्ट गाइड समझने लगता है। तो उनकी तरफ से सुझाव भी बिल्कुल आदेश जैसा आया, 'अभी नहीं, बसंत पंचमी वाले शाही स्नान के बाद जाना, सब खाली मिलेगा।' लो आ गए सब बसंत पंचमी के बाद। और इतने आ गए कि आवाज आने लगी, 'अब मत आओ'।

घूमने वाली लगभग सभी जगहों के साथ ऐसा ही होता है। हम जाना तो चाहते हैं, पर यह भी चाहते हैं कि जब हम जाएं, तब कोई न जाए। इसी चक्कर में कई बार इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है। फिर भी अभी थोड़ी राहत है। जब रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो वाले बिना मान-मनौव्वल कहीं जाने को राजी हो जाएं, होटल वाला आपको देखते ही रजिस्टर खोल दे कि कमरा खाली है, पक्के महाल में चाट-पकौड़ी के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े और गलियों में दूसरों से कंधे रगड़े बिना भी निकला जा सके, तो समझना चाहिए कि अभी मामला काबू में है। होली के बाद बिल्कुल ऐसा ही सीन है बनारस में। पान की दुकान पर खड़े एक सज्जन ने समझाया, 'चूना बिना रंग नहीं चढ़ता और ज्यादा खा लो तो जुबान कट जाती है। बनारस खाली सड़कों के लिए थोड़ी न है, लेकिन ऐसा भी मजा नहीं आता कि पैदल भी चल न सकें।' उन्होंने तसल्ली से पान का बीड़ा दबाया, ऊपर से दो सुपारी ली, दुकानदार के साथ बंद मुंह से ही कोई गंभीर वार्तालाप किया और फिर एक किनारे हाथ बांधकर खड़े हो गए। कुछ देर आसपास का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा, 'मौसम बिल्कुल फिट है, दिन में भी इस समय ज्यादा गर्मी नहीं लग रही और रात ठंडी हो जा रही है। इधर बीच कोई बड़ा त्योहार भी नहीं। किसी को घूमना हो तो अभी बनारस आ जाए।'

एकदा

पैसा नहीं बाधक

साल 1966 की बात है। प्रसिद्ध रूसी फिल्म निर्माता आंद्रेई तारकोवस्की भारत आए और आनंदवन में बाबा आमटे से मिले। वहां पुनर्वास और दिव्यांगों के लिए चल रही गतिविधियों को देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, 'एशिया में दिव्यांगों के लिए कई परियोजनाएं देखीं, लेकिन आनंदवन जैसा पुनर्वास केंद्र कहीं देखने को नहीं मिला।' तारकोवस्की खुद भी दिव्यांग थे और दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं मिल रही थी। बाबा ने सलाह दी - रोजगार के लिए प्रशिक्षण, रहने का ठिकाना, भोजन-पानी के लिए खेती जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। दिव्यांगों को बुनाई, सूत कताई, चर्म शिल्प, बढ़ईगीरी, छपाई के काम सिखाने की सलाह दी। तारकोवस्की को योजना बेहद पसंद आई, लेकिन उनके पास धन नहीं था। बाबा ने कहा, 'भाई, पैसे के लिए कोई काम नहीं रुकता।' इस बात ने जादू-सा असर दिखाया और आनंदवन के पास ही 'संधि निकेतन' की नींव खोदी गई, निर्माण कार्य शुरू हुआ। तारकोवस्की खुद व्हीलचेयर पर होते हुए भी चूना घोलते, ईंटें उठाते, पत्थर चुनकर बैलगाड़ी से लाते। उनके सुनहरे बाल मिट्टी से सन जाते, पर चेहरे पर खुशी होती। आनंदवन के लोगों ने भी श्रमदान किया। आखिरकार आनंदवन में एक और ऐतिहासिक कार्य पूरा हो गया। यह कहानी बताती है कि सच्ची सेवा में न सीमाएं होती हैं, न संसाधनों की कमी बाधा बनती है। बस, एक सशक्त संकल्प की जरूरत होती है।

Subrato Dhar

संकलन : दीनदयाल मुरारका

नीतीश कुमार ने हमेशा वंशवादी राजनीति का विरोध किया, मगर अब इसी राह पर चलते दिख रहे

नीतीश के बेटे सियासत में आए तो क्या होगा

राज कुमार सिंह

राजनीतिक रूप से बिहार बहुत जागरूक राज्य है, लेकिन यहां की राजनीति समाज की जटिलताओं में उलझी हुई है। इसी कारण, यहां के दोनों बड़े दल तीसरे नंबर की पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं। तीन दशक पहले जब लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार, जंगलराज और वंशवाद के आरोप लगे, तब नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। उन्होंने BJP के साथ दोस्ती कर ली। 2005 में लालू-राबड़ी शासन को हटाकर वह बिहार के मुख्यमंत्री बने।

सियासी चर्चा | अगर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को छोड़ दें, तो पिछले करीब दो दशकों से बिहार की सत्ता नीतीश के ही हाथों में रही है। सुविधा और जरूरत के हिसाब से वह अपने दोस्त बदलते रहे हैं। हर रिश्ते में शर्त यही रही कि सीएम पद बरकरार रहे। विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो फिर से उनके पाला बदलने और वंशवाद की राजनीति अपनाने की अटकलें जोरों पर हैं।

अटकलों की वजह | लालू और तेजस्वी यादव जब-तब नीतीश के प्रति प्रेम का इजहार करते रहते हैं। वहीं, BJP यह तो कहती है कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जवाब रहा कि ऐसे फैसले पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। NDA का सीएम BJP का संसदीय बोर्ड कैसे चुन सकता है?

महाराष्ट्र की मिसाल | महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को सामने रखकर शाह का बयान देखें तो सस्पेंस और गहरा जाता है। सियासी जरूरतों के चलते BJP ने कम विधायकों वाली पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट को सीएम पद दे दिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन इलेक्शन बाद अधिक सीटों के आधार पर फिर BJP ने अपना सीएम बना दिया। इसी वजह से बिहार में नीतीश के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।

नए समीकरण | 2020 के विधानसभा चुनाव में JDU को केवल 43 सीटें मिलीं। इसके बाद भी BJP ने नीतीश को ही सीएम बनाया। नीतीश को इतना नुकसान चिराग पासवान की वजह से उठाना पड़ा, जिन्होंने JDU के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। नीतीश ने इसके पीछे BJP का हाथ माना और

शायद इसी से खफा होकर वह लालू और कांग्रेस के गठबंधन में चले गए। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी NDA में वापसी हुई। BJP को इसका फायदा भी हुआ, पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नए समीकरण बनाए जाने लगे हैं।

BJP की चाहत | 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। पिछली बार BJP और JDU ने मिलकर 125 सीटें जीती थीं। लालू के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। इस बार BJP चाहती है कि उसका अपना आंकड़ा सौ के आसपास पहुंच जाए ताकि राज्य में पार्टी का सीएम बनाने का सपना पूरा हो सके। बहुमत का बाकी जुगाड़ दूसरे सहयोगी दलों से हो सकता है। लेकिन, ऐसा तभी होगा जब लालू और नीतीश का प्रदर्शन बेहद खराब हो। अगर BJP ज्यादा सीटों के आधार पर अपना सीएम बनाना चाहेगी, तो नीतीश शायद ही डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हों।

निशांत का भविष्य | नीतीश के बेटे निशांत कुमार पिता के साथ सीएम आवास में ही रहते हैं, लेकिन पहले कभी संकेत नहीं मिला कि वह राजनीति में सक्रिय होंगे। पिछले दिनों उन्होंने पहली बार राजनीतिक टिप्पणी की। तभी से कयास लगने लगे। तेजस्वी यादव और कुछ BJP नेताओं ने भी निशांत के राजनीति में आने को स्वागत योग्य बताया। हालांकि उस समय तक यह कयास ही था। अब निशांत जिस तरह मुख्यमंत्री निवास में JDU नेताओं के साथ होली खेलते दिखे और फिर उसके फोटो-पोस्टर सार्वजनिक किए गए, उसे राजनीति में प्रवेश का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

निशांत इसलिए जरूरी | कुछ लोग मानते हैं कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आए तो चुनाव के पहले या फिर बाद में JDU बिखर जाएगा। निशांत को लाकर ही नीतीश के वोट बैंक को बिखरने से बचाया जा सकता है। इसमें भविष्य की सत्ता राजनीति भी देखी जा रही है। BJP अगर JDU के बिना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुई, तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं, अगर RJD सबसे बड़ा दल बना तो वह भी एक बार फिर नीतीश की सत्ता की पालकी उठाने के बजाय निशांत को उप-मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगा। सत्ता के खेल ने कभी वंशवादी राजनीति के मुखर विरोधी रहे नीतीश कुमार को अब उसी वंशवादी राजनीति का राही बनने को मजबूर कर दिया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

उत्तराखंड की पहचान की लड़ाई क्या तेज़ होगी

चारु तिवारी

उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि 'क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ वालों के लिए है?' उनके ऐसा कहते ही कई जिलों में लोग सड़कों पर उतरे। BJP के विधायक भी बयान से नाराज दिखे। आखिरकार 17 मार्च को उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि उनके शब्दों को गलत समझा गया।

अधूरे सपने | ढाई दशक पहले चले अलग उत्तराखंड आंदोलन और 42 शहादतों के बाद बना यह राज्य फिर सुलग रहा है। एक तरफ लोग अपनी अस्मिता, जमीन और हक के लिए सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं के भड़काऊ बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

पहाड़ बनाम तराई | उत्तराखंड की जनता हमेशा से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ती रही है। 1979 में शुरू हुआ उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) इसी असंतोष की उपज था। 1990 के दशक में आंदोलन उग्र हुआ, जब मुलायम सिंह की सरकार ने मैदानी लोगों को पहाड़ों में बसाने की बात कही। 1994 में रामपुर तिराहा की हिंसक मुठभेड़ में कई लोग मारे गए। इसके बाद आठ पहाड़ी जिलों के साथ अलग राज्य का प्रस्ताव बना, जिसमें मायावती ने तराई के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाके जोड़ दिए। नवंबर 2000 में उत्तराखंड तो बना, लेकिन इसकी पहचान एक पहाड़ी राज्य के बजाय जनसांख्यिकीय असंतुलन से कमजोर हो गई।

चौड़ी होती खाई | आज हालात ये हैं कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में स्कूल, अस्पताल और उद्योग हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों के हजारों गांव 'भूतहा' बन चुके हैं, जहां कोई नहीं रहता। पिछले दो-तीन सालों से युवा भू-कानून और मूल निवास की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। सरकार ने भू-कानून में संशोधन के नाम पर मैदानी जिलों को इसके दायरे से बाहर रखा, जिससे पहाड़-मैदान की खाई और चौड़ी हो गई है।

विवादित बयान की वजह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को देना पड़ा इस्तीफा

कॉमन रूम

पानी और जवानी | अग्रवाल के बयान ने इस असंतोष को पहाड़ की अस्मिता से जोड़ दिया। जब बदरीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने विरोध किया, तो स्पीकर का रवैया देख लोगों को लगा कि उनकी पहचान को चुनौती दी जा रही है। पिछले एक महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं। युवाओं ने पुतले जलाए, आमरण अनशन किया, अपने खून से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। गैरसैंण में आंदोलनकारियों को 'सड़क छाप' कहने वाले महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी गुस्सा भड़का। दबाव में अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, पर सवाल वही बने हुए हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी क्यों सूख रही है? केंद्र का देवभूमि को पर्यटन हब बनाने का सपना क्या पहाड़ियों को और बेदखल नहीं करेगा?

पहचान की लड़ाई | अंग्रेजों ने यह अच्छे से समझा था कि हिमालय सिर्फ पेड़-पौधों का खजाना नहीं, बल्कि संस्कृतियों और पहचान का संगम है। मगर आज सरकारें इसे भुला चुकी हैं। इसके चलते तराई में आय बढ़ी, पर केदारनाथ और जोशीमठ जैसे नाजुक इलाके तबाह हो गए। युवा अब जल, जंगल, जमीन और रोजगार के लिए नया आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या क्षेत्रवाद के बीज जो कभी यहां नहीं थे, अब और गहरे होंगे? उत्तराखंड की जनता अपनी असली पहचान और हक की लड़ाई कितनी दूर ले जा पाएगी, यह वक्त बताएगा।

कम्युनिकेशन हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत जितने भी लोग आएं, सभी का स्वागत है

केंद्रीय संचार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री **ज्योतिरादित्य सिंधिया** अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर ही नहीं, राजनीति के बदलते समीकरणों को लेकर भी चर्चित होते रहते हैं। आजकल इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के भारत आने को लेकर भी खासी चर्चा है। बढ़ते टेलिकॉम फ्रॉड लोगों की चिंता का कारण बने हुए हैं। इन तमाम मसलों पर उनसे बात की है NBT की **पूनम पाण्डे** ने। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

■ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो BJP के लिए काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को?

यह सवाल आपको कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। मैं तो BJP का कार्यकर्ता हूं।

■ लोकसभा में अभी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं। क्या कुछ बदलाव हाउस के अंदर देखते हैं? कांग्रेस के जो पहले के आपके दोस्त रहे हैं, क्या वे संपर्क में हैं अभी भी?

हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में और जनसेवक के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि सेवक के रूप में हमें काम करना है और उसी विचारधारा से हम लोग काम कर रहे हैं। ये BJP की पद्धति है, सोच है और विचारधारा है। दूसरी पार्टियों की अपनी पद्धति है, अपनी विचारधारा है।

■ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया, लेकिन उसके बाद BJP फिर चुनाव जीतती गई। क्या बदलाव आया?

देश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि नकारात्मक प्रवृत्ति की पार्टियों के लिए, पारिवारिक पार्टियों के लिए आज उसके दिल में कोई जगह नहीं है। वही नतीजा आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, वही नतीजा लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा और वही नतीजा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी देखा।

■ कहा जा रहा है कि अब आप ग्वालियर के विकास कामों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप ग्वालियर से नाराज हैं या कोई बाधा आ रही है?

ग्वालियर ही क्यों? चाहे मुरैना हो, भिंड हो, दतिया हो, चंबल हो या कोई और क्षेत्र, जहां भी मैं अपना योगदान दे पाऊं, अपना सौभाग्य मानता हूं।

■ आप टेलिकॉम मंत्री भी हैं। स्पैम कॉल की दिक्कत और टेलिकॉम फ्रॉड के कई मामले आ रहे हैं। कैसे निपट रहे हैं इससे?

उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता की सर्विस मिले, उपभोक्ता को सुरक्षित रख पाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमने करीब पौने दो करोड़ मोबाइल फोन को डिस्कनेक्ट किया है। चोरी गए करीब 2.50 लाख मोबाइल फोन भी रिकवर किए। हमने करीब 1.5 लाख ऐसे SMS स्प्रेडर्स को ब्लैकलिस्ट किया जो गलत तरीके से सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉड के विषय में भी हमने करीब 15 लाख वट्सऐप ग्रुप डिस्कनेक्ट किए हैं, जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब कोशिश है कि वट्सऐप को भी मोबाइल नंबर के साथ मैच किया जाए। बहुत सारे स्पूफ कॉल, टेलिकॉम मार्केटिंग कॉल लोगों को परेशान करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। भारत के +91 कोड को छद्म रूप से दिखाकर बाहर से भी कॉल आती है। सॉफ्टवेयर के आधार पर हम हर दिन करीब 1.30 करोड़ कॉल रोकने में सक्षम हो पाए हैं, जो स्पूफ और स्पैम हैं। पिछले 6-7 महीने में स्पैम और स्पूफ कॉल की संख्या में करीब 94% गिरावट हुई है।

■ स्टारलिंक की भारत में संभावित एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं?

सैटलाइट की दो बहुत बड़ी जरूरत हैं। पहली- देश के कई ऐसे कोने हैं, जहां मोबाइल टावर के आधार पर या OFC फाइबर के आधार पर हमारी पहुंच नहीं हो पाती। वहां केवल सैटलाइट कनेक्टिविटी हो सकती है। दूसरी बात, भगवान ना करे, लेकिन जब नैचरल डिजास्टर होता है तब सैटकॉम का बहुत बड़ा योगदान होता है रेस्क्यू मिशन में, कनेक्टिविटी देने में। मैं मानता हूं कि हमारे लिए कम्युनिकेशन का हर फॉर्म, हमारी जरूरत है और जितने भी लोग आएं, उन सभी का स्वागत है। अभी रिलायंस, जियो और एयरटेल को लाइसेंस दे दिया है, जो लोग भी उन नियमों का पालन करते हैं, सभी का स्वागत है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ जरूरी है संतुलन

20 मार्च के लेख 'ट्रंप की नीति भारत को चीन के करीब लाई' में भारत और चीन के संबंधों में हो रहे सकारात्मक बदलावों और उनके पीछे के कारकों का विश्लेषण पढ़ने को मिला। ट्रंप प्रशासन की नीतियों से भारत आहत है। आने वाले समय में भारत और चीन एक-दूसरे के करीब आ जाएं, तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। सीमा पर सैन्य तैयारियों और CPEC जैसे मुद्दों के बावजूद, रणनीतिक मजबूरियों के कारण दोनों देश सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। ज्यादा टैरिफ लगाने की ट्रंप की नीति भारत और चीन दोनों को आपसी व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। भारत को अपनी आर्थिक और सामरिक नीतियों को संतुलित रखते हुए चीन के साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाने पर जरूर सोचना चाहिए।

नीलेश चौधरी, ईमेल से

■ लोकतंत्र पर भरोसा

यह पत्र 18 मार्च के संपादकीय 'आयोग की चुनौती' से संबंधित है। चुनाव आयोग का वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव फर्जी मतदान रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन इससे कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। डेटा लीक की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के ठोस उपाय करने होंगे। राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर डुप्लिकेट वोटर आईडी के मुद्दे को लेकर। इसलिए इसे लेकर सभी पक्षों की सहमति और पूरी पारदर्शिता जरूरी है, ताकि लोकतंत्र पर जनता का भरोसा बना रहे।

राजीव रंजन, ग्रेटर नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

यूक्रेन युद्ध पर US बोला, अब गेंद रूस के पाले में - एक खबर

- सवाल तो यही है, पूतिन का युद्ध के इस खेल से मन भरा या नहीं।

मयंक श्रीवास्तव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

मनोबल बढ़ाने वाला मिल जाए तो हर मंजिल आसान

संजय तेवतिया

हमारी सोच ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे निर्णयों में स्पष्टता, ऊर्जा और आत्मविश्वास झलकता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसे जीवन में सफलता की राह पर भी अग्रसर करती है। इसके लिए गुरु महत्वपूर्ण होता है। गुरु जगाने का काम करता है, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं।

महाभारत में जब अर्जुन हतोत्साहित हो गए और उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें सकारात्मक सोच और कर्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ाया। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करती है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। ऐसा ही उदाहरण हनुमानजी के जीवन में भी देखने को मिलता है। जब श्रीराम की सेवा में लंका जाने का कार्य सौंपा गया, तो पहले हनुमानजी को अपनी शक्ति का भान नहीं था। जामवंत ने उन्हें उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया और आत्मविश्वास से भर दिया। इसके बाद हनुमान ने समुद्र लांघकर सीता माता तक पहुंचने का असंभव कार्य भी संभव कर दिखाया। यह प्रेरणा हमें सिखाती है कि जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान को मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखने का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक बनाए रखता है। भारतीय संतों और गुरुओं ने धैर्य और संयम को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपने भीतर आत्मविश्वास व सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह समाज को भी प्रभावित करता है। जब एक व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो वह समाज में अच्छे बदलाव लाने की दिशा में प्रेरणा बनता है।

हमारी संस्कृति में सकारात्मक सोच महज विचार नहीं, एक संपूर्ण जीवनशैली है। यह आत्मविश्वास बढ़ाती है। यह सिखाती है कि हमें हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 मार्च, 2025

दैनिक जागरण
जिज्ञासा ही ज्ञान की दिशा में उन्मुख करती है

हठधर्मी का नतीजा

पंजाब-हरियाणा सीमा पर एक वर्ष से अधिक समय तक दो प्रमुख रास्तों को रोककर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाकर पंजाब सरकार ने वही किया, जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। किसानों के इस धरने के कारण न केवल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि व्यापारियों को अच्छा-खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। चूंकि किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अपना हठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास रास्ते खाली कराने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। यह वही आम आदमी पार्टी है, जिसने एक समय कृषि कानूनों के विरोध में जबरन दिल्ली घेर कर बैठे किसानों का हर तरह से समर्थन किया था। यह अच्छा है कि उसने मजबूरी में ही सही, अपने राजधर्म को समझा। यह समय की मांग है कि किसान नेता भी यह समझें कि हठधर्मिता दिखाने से उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। उन्हें यह भी समझना होगा कि यदि कोई अपनी मांगें मनवाने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान करने वाले तौर-तरीके अपनाता है तो वह जनता की सहानुभूति खो देता है और सरकारों के लिए उनकी मांगों पर विचार करना भी कठिन हो जाता है।

किसान संगठन अपनी अन्य अनेक मांगों समेत सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है, लेकिन केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि ऐसा कानून बनाना संभव नहीं और यदि उनके दबाव में वह बना भी दिया जाए तो उसके दुष्परिणाम किसानों को ही भुगतने होंगे। किसान नेताओं के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं कि यदि व्यापारी एमएसपी पर खरीद से पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा? इस पर हैरानी नहीं कि किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सातवें दौर की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यह ठीक है कि पंजाब सरकार की ओर से किसान संगठनों को सड़क से हटा देने से किसान नेता नाराज हैं, लेकिन उचित यह होगा कि उनके और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला कायम रहे। बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंच सकती है, जब दोनों ही पक्ष बीच का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। जहां सरकार के लिए ऐसे उपाय करने आवश्यक हैं, जिनसे खेती की लागत कम हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, वहीं किसान नेताओं को भी अपनी मांगों को लेकर जिद पकड़ने से बचना होगा। केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी कि वह किसान नेताओं के समक्ष वे तथ्य रखे, जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून किस तरह की समस्याएं पैदा करेगा।

निष्पक्ष जांच जरूरी

झारखंड में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में पेयजल विभाग की योजनाओं में घोटाले को लेकर आवाज बुलंद हुई। कारण है कि योजनाओं में तरह-तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं। इसी कड़ी में स्वर्णरेखा परियोजना के रांची प्रमंडल में हुए लगभग 22 करोड़ रुपये के घोटाले में चार कोषागार पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। हालांकि गड़बड़ियों की फेहरिस्त लंबी है। स्वर्णरेखा परियोजना ही नहीं, बल्कि कई पेयजल प्रमंडलों में घोटाले हुए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। तभी गड़बड़ी करने वाले सामने आएंगें और उन्हें दंडित किया जा सकेगा। पेयजल विभाग के कई प्रमंडलों में स्वच्छता मिशन के तहत खरीद में भी गड़बड़ी की गई है। मनचाही एजेंसियों से खरीद कर मनमाने तरीके से भुगतान भी किया है। वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर सरकार जांच करा रही है। अनियमितता की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। क्योंकि जांच रिपोर्ट को दबाने और दोषियों को बचाने के आरोप विभाग और अधिकारियों पर लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार कैंसर जैसा रोग है। यह बीमारी देश की व्यवस्था को खोखला कर रही है। इसका निदान समय की मांग है।

सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं

अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र

अजय कुमार

लागत में कटौती करने वाले तमाम नवाचारों के द्वारा निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में क्रांति की लहर पैदा कर दी है

सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी के अंतरिक्ष में लंबे प्रवास के बाद धरती पर आगमन से भारत के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसलिए और भी, क्योंकि भारत में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में इन्कोस्पार, 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ शुरू हुई। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया में कई सरकारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस क्रम में नासा, ईएसए और रोस्कोमास जैसी एजेंसियां अग्रणी हैं। एरियनस्पेस ने पिछली सदी के नौवें दशक में पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया। 1984 में यूएस कामर्शियल स्पेस लांच एक्ट आया और 1988 में निजी दूरसंचार उपग्रह लांच हुआ। निजी निवेश में, खासकर अमेरिका में अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ने लगीं। 2002 के बाद स्पेसएक्स ने लागत में कटौती करने वाले बहुत सारे नवाचारों द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति की लहर को जन्म दिया। सुनीता विलियम्स की वापसी में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सहयोग की अहम भूमिका रही।

आज अंतरिक्ष निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। कुछ साल पहले तक इसरो द्वारा हासिल अंतरिक्ष डाटा सीमित रूप में ही साझा किया जाता था। 2009 में इस नीति में बदलाव आया। 2020 में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने से इस क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की एक नई लहर आई है। आज इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 260 से अधिक हो गई है।

भारतीय स्टार्टअप इसरो के पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल माड्यूल के साथ स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर और फ्रांस के एरियन राकेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 15 से अधिक निजी उपग्रह लांच किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण की दूसरी विशेषता लागत में आई कमी है। नासा के अंतरिक्ष यान की लागत लगभग 54,500 डालर प्रति किलोग्राम थी, जबकि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 की कीमत लगभग 2,720 डालर प्रति किलोग्राम है। भारत में यह लगभग 30,000 डालर है। निजी भागीदारी उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को लगभग 30-40 प्रतिशत कम कर सकती है। स्टार्टअप्स वाणिज्यिक सप्लाई चेन माड्यूलर डिजाइनों और राइड-शेयर विकल्पों के उपयोग का लाभ उठाकर कम लागत में सैटेलाइट बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप छोटे सैटेलाइट बनाते हैं, जिससे लागत कम हो जाती है।

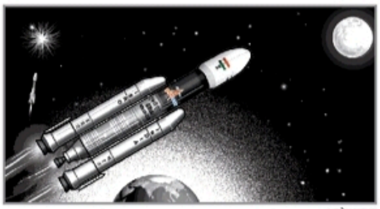

अवधेश राजपूत

पिछली सदी के अंतिम दशक में 10-20 टन के जियो उपग्रह की कार्यक्षमता अब एक छोटे 800 किलोग्राम के उपग्रह में प्राप्त की जा सकती है। इसरो का बड़े उपग्रह बनाने का इतिहास रहा है। इसके विपरीत, भारतीय स्टार्टअप छोटे उपग्रहों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पिक्सल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह का वजन लगभग 15 किलोग्राम है। अतीत के विपरीत जहां अधिकांश उन्नत तकनीकें इसरो द्वारा विकसित की गई थीं, वहीं स्टार्टअप अब नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ रही है। कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में निवेश और अनुप्रयोगों को आकर्षित करने और अपने स्वयं के उपग्रहों को लांच करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत हिस्सा हासिल करना चाहता है। केरल ने केस्पेस और स्पेस पार्क की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश ने एक स्पेस इनोवेशन सेंटर बनाया है। तेलंगाना ने स्पेसटेक फ्रेमवर्क बनाया है और तमिलनाडु कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के पास स्पेस बे और एक प्रोपेलेंट पार्क स्थापित करने जा रहा है। गुजरात इनस्पेस के साथ साझेदारी में एक स्पेस क्लस्टर बना रहा है। अन्य राज्य भी अंतरिक्ष गतिविधियों का बढ़ावा दे रहे हैं।

सरकारों और व्यवसायों द्वारा उपग्रह डाटा का बढ़ता उपयोग इसके बढ़ते विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक गांवों में फसल बीमा के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग हो रहा है। कर्नाटक में छह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की निगरानी, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पूरा किया जाना, राजस्थान और हरियाणा द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक भूसंपदा के भूमि रिकार्ड बनाना, असम में 30 जिलों में बाढ़ की चेतावनी देना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में साइक्लोन की चेतावनी का समय 50 प्रतिशत घटना, स्मार्ट शहरों में प्रापर्टी टैक्स में सुधार और मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किमी वन भूमि की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। स्टार्टअप नई डाटा-आधारित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्टेटस्योर कृषि ऋण देने वाले बैंकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में सैटेलाइट डाटा का उपयोग न केवल सरकारों और संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, अपितु कारोबारियों और छोटे व्यवसायों द्वारा भी किया जाएगा।

भारत के अंतरिक्ष निर्यात पर अब तक इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार था। अब स्टार्टअप्स उसके पूरक बन रहे हैं। उनके योगदान के कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा 0.3 अरब डालर से बढ़कर 11 अरब डालर होने का अनुमान है। बदलते परिदृश्य में केंद्र सरकार की भूमिका कार्यान्वयनकर्ता से बदलकर इसरो और स्टार्टअप सहित निजी खिलाड़ियों के बीच प्रमोटर, सुविधाकर्ता और मध्यस्थ की हो गई है। इसरो ने अपनी सुविधाओं को स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए खोल दिया है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया है। इस समय भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो सरकार के नेतृत्व वाले क्षेत्र से एक गतिशील एवं विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम में बदल रहा है। स्टार्टअप द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय केंद्रों को बढ़ावा देने और निजी निवेश द्वारा लागत कम करने के साथ, अंतरिक्ष अब हमसे दूर नहीं। हममें से हर कोई इससे लाभान्वित होने वाला है।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव एवं आइआइटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

अपने दायित्व को समझें शिक्षा संस्थान

बद्री नारायण

विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा की भूमिका इसलिए अहम है, क्योंकि वही प्रगति की आकांक्षा को जन्म देती है

आज भारत तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह परिवर्तन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी दिशाओं में हो रहा है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन हम कई बार देखते हैं, पर उन्हें समझ नहीं पाते, जबकि यह 'परिवर्तन का दौर' है। भारतीय समकालीन आधुनिक इतिहास को तीन रूपांतरकारी दौर में बांटा जा सकता है। पहला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का दौर। दूसरा, आजादी के बाद देश को बनाने के लक्ष्य को पाने की चाहतों का दौर और तीसरा, विकसित भारत का आज का दौर। विकसित भारत का यह मिशन समाज के प्रत्येक वर्ग से स्वतंत्रता आंदोलन जैसी प्रतिबद्धता की मांग करने के साथ यह हम सबसे अपने को नए परिवर्तनों से जोड़ने की भी अपेक्षा करता है। विकसित भारत के इस दौर में हमें व्यक्तिगत और संस्थागत, दोनों ही स्तरों पर अपने को पुनर्नवा करने की जरूरत है, तभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।

बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के वर्तमान एवं भविष्य पर गहन चिंतन हुआ। उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आइआइटी, आइआइएम एवं एनआइटी के निदेशक तथा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नीति निर्माता एवं अधिकारियों ने भाग लिया। उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि हमारे शिक्षण संस्थान भारत में विकास के प्रकाश स्तंभ बनेंगे एवं प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के लिए 'एंकर' का कार्य करेंगे। उनके इस वक्तव्य में भविष्योन्मुखी अपेक्षा निहित है। इसमें यह अपेक्षा है कि भारतीय शिक्षण संस्थान केवल चहारदीवारी के भीतर रहकर पढ़ाने, किताबी ज्ञान देने एवं डिग्री देने वाली संस्था के रूप में ही सीमित न रहें, बल्कि इनसे आगे निकल 'विकास एवं सामाजिक परिवर्तन' के चिंतन केंद्र के रूप में स्वयं को विकसित करें। इस प्रकार ये संस्थाएं अपने शोध, आंकड़ों, विकास समीक्षा एवं चिंतन के माध्यम से विकसित भारत के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिशा एवं दृष्टि देंगी। राष्ट्रपति की तरह प्रधानमंत्री भी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। एक बार साइंस कांग्रेस में उन्होंने देश के शिक्षण संस्थानों से समाज को भी अपनी प्रयोगशाला बनाने का आग्रह किया था। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान जब 'भारतीय समाज एवं अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से नाभिनाल का संबंध बना पाएंगे, तभी वे विकसित भारत के प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभा पाएंगे।

नई पीढ़ी पर भविष्य निर्माण का दायित्व। फाइल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने वाली है। वह भारतीय शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप को तोड़ते हुए एक प्रगतिशील रूपांतर के लिए नीति-नियम रचती है। इस शिक्षा नीति के तहत लचीलापन, अंतर अनुशासनिकता, समाज के विविध प्रयासों के साथ अंतः संवाद तथा समरस एवं विकासोन्मुखी गतिशीलता प्रदान करने की कोशिश दिखाई पड़ती है, ताकि भारतीय शिक्षा में संस्थागत एवं वैयक्तिक स्तर पर आधारभूत परिवर्तन हो सके। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के समक्ष यह चुनौती भी है कि वे अपनी पारंपरिक प्रकृति, सुविधाभोगी बौद्धिकता एवं अनेक तरह के रूढ़ बंधनों से मुक्त होकर सामाजिक बदलावों, विकास के लिए चल रहे अनगिनत प्रयासों से स्वयं को जोड़ें। आज देश को ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है, जो अपने ज्ञान से समाज में सकारात्मक नेतृत्व को दिशा-दृष्टि दे सकें। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ऐसे ही जुड़ाव से हम अपने समाज में निहित पारदर्शी देवत्व को देख और सुन पाएंगे। इस संदर्भ में दूसरी जरूरत है कि समाज एवं शिक्षा के साथ ही राज्य एवं शिक्षा के बीच भी संवाद गहन हो। यह संवाद ऐसा हो, जो दोनों में भेद न पैदा करे, बल्कि दोनों को समृद्ध कर सके। हमारे शिक्षा संस्थान एवं बौद्धिक जगत राज्य द्वारा चलाई जा रही अनेक विकासपरक योजनाओं एवं किए जा रहे कार्यों का सम्यक मूल्यांकन कर उनमें व्याप्त कमियों से उसे अवगत कराए। हमारे यहां योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन तो होते हैं, पर उन्हें बौद्धिक ज्ञान में बदलने के उपक्रम में हम पीछे रह जाते हैं।

पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की पहल पर देश के 20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आइआइएम, आइआइटी इत्यादि ने मिलकर भारत में चल रहे विकास कार्यों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया था, जो अब अनेक खंडों में प्रकाशित होकर आ गया है। आज ऐसे ही विविध स्तरों पर अनेक प्रयासों की जरूरत है। बीते दिनों मैं उत्तर प्रदेश के एक राज्य विश्वविद्यालय गया था। वहां के छात्रों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विकसित भारत अब हमारे लिए विकास मंत्र है। उस युवा छात्र की यही दृष्टि अगर हमारे शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों में आ जाए तो विकसित भारत के इस लक्ष्य को पाने में हमें सुविधा होगी। भारत की आजादी में जिस भावना से देश के लोग जुटे थे, आज उसी प्रतिबद्ध भाव से विकसित भारत के लक्ष्य से हमें जुड़ना होगा। इस महायज्ञ में शिक्षा संस्थानों, बौद्धिकों, शोधार्थियों एवं छात्रों की महती भूमिका है। शिक्षा की भूमिका विकसित भारत के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा हममें आगे बढ़ने एवं विकसित होने की आकांक्षा को जन्म देती है। यही आकांक्षा वह उत्प्रेरक शक्ति है, जो भारत के सामान्यजन को विकसित भारत के मिशन से जोड़ सकती है।

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निष्ठा

निष्ठा का अर्थ है-किसी व्यक्ति, सिद्धांत या कर्तव्य के प्रति वफादारी, समर्पण एवं दृढ़ता, जो किसी के प्रति सच्ची और निरंतर प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाए। आज की आधुनिकता और आगे बढ़ने की होड़ में निष्ठा और कर्तव्यपरायणता आदि मानवीय गुण लोगों के लिए अपवाद होते जा रहे हैं। लोगों में अनास्था एवं कर्तव्य विमुखता एक उपचारविहीन व्याधि के समान फैलती जा रही है। हैरत की बात है कि लोगों को इसमें किसी तरह की बुराई भी नजर नहीं आ रही है। कई नौजवान तो निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, समर्पण को निरर्थक एवं बेजा मानने लगे हैं। माता-पिता अपनी संतान को पालने-पोसने में बड़ा संघर्ष करते हैं। जितना संभव होता है उन्हें निष्ठा, बड़ों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाते हैं। अपने स्वयं के जीवन से उन्हें निष्ठावान बनने को प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वे बड़े होने के बाद इससे विमुख हो जाते हैं तो उन्हें दुख होता है।

निष्ठा के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ है। किसी व्यक्ति को उसकी निष्ठा को लेकर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जब बालक निष्ठा, धर्मपरायणता और उच्च व्यवहार लिए आगे बढ़ता है तो यही गुण उसे समाज की एक अग्रणी इकाई बनाते हैं। हमें अपनी निजी प्राथमिकताओं को त्याग दूसरों के लिए जीने की कला में पारंगत होना चाहिए। अपने सहयोगी और अधीनस्थ के प्रति निष्ठा रखनी और दिखानी भी चाहिए, तभी हम उनकी निष्ठा के पात्र बन सकते हैं। निष्ठा में विश्वास एक बड़ा मंत्र है। फिर वह माता-पिता के प्रति हो, अपने कार्य के प्रति हो, देश के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो, अन्यथा व्यवस्था में दरार पड़ जाती है और वह टूट जाती है। निष्ठावान व्यक्ति को आत्मसंतोष तो होता ही है वह समाज और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति जैसा होता है। समय के साथ खुद की विसंगतियों में सुधार कर हम दुख में टूटने, बिखरने से बच सकते हैं।

छाया श्रीवास्तव

बनावटी तस्वीरों से बढ़ता अवसाद

डा. मोनिका शर्मा

मौजूदा दौर में तकनीक के सधे-सार्थक इस्तेमाल की समझ हमें कई समस्याओं से बचा सकती है

सामाजिक आयोजन, पारिवारिक समारोह, सांस्कृतिक सम्मेलन या व्यक्तिगत भेंट। सुखद वाकया हो या किसी के संसार छोड़ जाने का पीड़ादायी प्रसंग। सब कुछ तस्वीरों तक सिमट रहा है। छवियां, जो कभी स्मृतियां सहेजने का माध्यम समझी जाती थीं, अब साझे पलों को वर्चुअल संसार में साझा करने के उद्देश्य से ली जाने लगी हैं। संवाद का दायरा घटा है तो लोग डिजिटल मेकअप के भी लती हो रहे हैं। तकलीफदेह है कि फिल्टर यानी तस्वीर को सुंदर बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करने की आदत अवसाद के घेरे में भी ला रही है।

वस्तुतः तकनीकी सुविधाओं से मिला नकलीपन ओढ़ने का यह व्यवहार कई मोर्चों पर पीड़ादायी भी बन गया है। लोगों पर आम आयोजनों में भी सज-धजकर पहुंचने का मानसिक दबाव बढ़ा है। हर पल चौकन्ने रहने की एक बाध्यता मिलने-बैठने की सहजता पर भारी पड़ रही है। हर पल को कैमरे में कैद करने की मनोवृत्ति ने सामाजिकता के भाव को ही बदल दिया है। फिल्टर्ड तस्वीरों ने अपने ही चेहरे की असली छवि भुला दी है। हर आयु वर्ग के लोग इस वर्चुअल निखार-संवार के जाल में फंस रहे हैं। कुछ समय पहले गूगल द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन में सामने आया था कि अच्छी सेल्फी लेने के लिए अमेरिका और भारत में फिल्टर इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अध्ययन के मुताबिक भारतीय महिलाएं अपनी तस्वीरों को सुंदर बनाने के लिए अधिक उत्साहित रहती हैं। इसके लिए वे कई फिल्टर एप और एडिटिंग माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं।

विडंबना यह भी है कि मेल-मुलाकात की यादगार के तौर पर ली जा रही तस्वीरें वास्तव में याददाश्त को कमजोर करने लगी हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार लोग सोचते हैं कि फोटो लेने से उन्हें कुछ बेहतर याद रखने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। अध्ययनकर्ता जूलिया सोरोस का कहना है कि 'मैं यह नहीं कह रही हूं कि लोगों को कभी भी तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कब करना चाहिए इसके प्रति सजगता आवश्यक है।' बावजूद इसके सब कुछ दूसरों तक पहुंचाने की रुग्ण मानसिकता के चलते मृतक स्वजन के साथ तस्वीरें लेकर इंटरनेट मीडिया पर डालने के उदाहरण भी कम नहीं। सब कुछ स्क्रीन में सहेजने की आदत दुर्घटनाओं का भी कारण बन रही है। हार्वर्ड सहित अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोध बताते हैं कि एक तस्वीर लेने की इच्छा उसी तस्वीर को इंटरनेट मीडिया मंचों पर साझा करने की इच्छा से और बढ़ जाती है। समझना कठिन नहीं कि अपने असली व्यक्तित्व के बजाय फिल्टर्ड छवियों में सुंदर दिखने की चाहत इस लत को और बढ़ाती है। मौजूदा दौर में तकनीक के सधे-सार्थक इस्तेमाल की समझ ही इस खुद आमंत्रित किए जा रहे अवसाद से हमें बचा सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

इतिहास के नाम पर दासता

'आक्रांता के महिमामंडन की बीमारी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में प्रवीण लखेरा ने संदेश दिया है कि आक्रांताओं का महिमामंडन एक मानसिक दासता है और सभ्यता को अपने सांस्कृतिक मूल्यों व सत्य के आधार पर इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि दमनकारियों के प्रतीकों से गौरव खोजना चाहिए। इतिहास केवल घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब उस इतिहास में आक्रांताओं का महिमामंडन किया जाता है, तो वह केवल तथ्यात्मक विकृति नहीं होती, बल्कि वह मानसिक पराजय होती है। औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासकों को 'न्यायप्रिय' या 'धार्मिक सहिष्णु' सिद्ध करने का प्रयास इसी बौद्धिक भ्रम का प्रतीक है। जिस शासक का शासन मंदिरों के विध्वंस, मतांतरण, कर उत्पीड़न और सांस्कृतिक विघटन पर आधारित हो, उसका गुणगान करना ऐतिहासिक विवेक का नहीं, वैचारिक गुलामी का प्रमाण है। यह न केवल ऐतिहासिक असत्य है, बल्कि पीड़ित जनस्मृति का अपमान भी। चिंतन का विषय यह है कि इतिहास में उन व्यक्तित्वों को आदर्श स्थान क्यों दिया जाए, जिन्होंने समाज में समावेश नहीं, बल्कि विखंडन का बीज बोया? क्या हम स्मृति की सत्ता को सच्चाई पर रखेंगे या प्रतीकों की सत्ता को भ्रम पर टिकाए रखेंगे? इतिहास का उद्देश्य स्मारक बनाना नहीं, मूल्य देना होना चाहिए। जो शासक भय और हिंसा के बल पर सत्ता स्थापित करें, वे इतिहास में सबक हो सकते हैं, आदर्श नहीं। सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना तभी जीवंत रह सकती है, जब वह अपने मूल्यों, आदर्शों और आत्मसम्मान की नींव पर खड़ी हो, न कि उन आक्रांताओं की विरासत में गौरव की खोज करे, जिन्होंने उसके आत्मा को रौंदा था। यदि स्मृति को दिशा नहीं दी गई, तो इतिहास प्रेरणा नहीं बनेगा, बल्कि भ्रम का दर्पण बनकर सभ्यता को आत्मविस्मृति की ओर धकेल देगा। आक्रांताओं का महिमामंडन एक मानसिक दासता है। सभ्यता को अपने सांस्कृतिक मूल्यों व सत्य के आधार पर इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि दमनकारियों के प्रतीकों से गौरव खोजना चाहिए।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

नशे का बढ़ता प्रयोग चिंता का विषय

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में युवाओं एवं वयस्कों के बीच शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। यह न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों और सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर कर रहा है। प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। जागरूकता अभियान, सख्त कानूनों का प्रवर्तन और नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नशा और नाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नशा चाहे कोई भी क्यों न हो, यह हमेशा शरीर, धन का नाश ही करता आ रहा है।

गुनगुन, फरीदाबाद

आधार लिंकिंग के साथ मतदान हो अनिवार्य

चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान पहचान पत्रों का आधार से लिंकिंग स्वागत योग्य और प्रशंसनीय है और साथ ही फर्जी मतदाताओं को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक भी। इसके साथ फर्जी मतदाताओं की पहचान के साथ उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जब सरकार और चुनाव आयोग टेक्नोलाजी के माध्यम से सभी मतदाताओं के मतदान पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो रही है, तो इसके प्रभाव से किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता स्थापित हो सकेगी। इसलिए सभी मतदाताओं द्वारा किसी भी चुनाव में मतदान भी अनिवार्य करने की कानूनी प्रक्रिया पर भी विचार किया जा सकता है। किसी भी मतदाता द्वारा चुनाव तिथि पर देश के किसी भी क्षेत्र में मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कम से कम जिला स्तर पर बहुपयोगी मतदान केंद्र स्थापित हो सकते हैं। यह प्रक्रिया आनलाइन भी हो सकती है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

छिपा हुआ भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र के लिए असली खतरा है। -जेफिर टीचआउट

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खुशियों के मीटर में भारत को पाकिस्तान सहित युद्धग्रस्त यूक्रेन व फलस्तीन से भी ज्यादा दुखी बताया जाना इन वैश्विक सूचकांकों की विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े करता ही है, यह संशय भी पैदा करता है कि आखिर वास्तविक खुशी है क्या?

खुशियों का विरोधाभास

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर की ओर से जारी विश्व खुशहाली सूचकांक-2025 की रिपोर्ट, जिसमें भारत को पाकिस्तान समेत युद्धग्रस्त यूक्रेन व फलस्तीन से भी ज्यादा अवसादग्रस्त व असंतुष्ट बताया गया है, ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया है कि क्या इस तरह के वैश्विक सूचकांक वाकई तथ्यों पर आधारित होते हैं? इससे यह सवाल भी पैदा होता है कि वास्तविक खुशी और उसे मापने की कसौटी आखिर है क्या। भले ही रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार आया हो, लेकिन आर्थिक दिवालिएपन और गृहयुद्ध जैसे हालात से जूझ रहे पाकिस्तान को अगर उससे ऊपर रखा गया है, तो स्वाभाविक रूप से संदेह तो उत्पन्न होगा ही। युद्धग्रस्त देशों की बात करें, तो इस्राइल आठवें, फलस्तीन 108 वें, रूस 66वें और यूक्रेन 111वें स्थान पर है, जबकि भारतीय बगैर किसी युद्ध या विनाश के भी दुखी हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। बावजूद इसके कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की विकास दर से उम्मीदें लगाए हुए हैं, खुशियों के मीटर में भारत का स्कोर चाड, बुर्किना फासो, बेनिन और सोमालिया जैसे देशों से थोड़ा ही ऊपर है। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि इन देशों की तरह की अराजकता व संघर्ष ही वास्तविक खुशियों का मूल है और हमें इसका ही अनुसरण करना चाहिए? चौंकाने वाली बात यह भी है कि सकल खुशहाली सूचकांक का विचार देने वाला भूटान, जिसकी 2024 की रिपोर्ट में 79वीं रैंकिंग थी, इस वर्ष कोई रैंकिंग नहीं पा सका है। यही नहीं, मध्य अमेरिकी राष्ट्र बेलिज, जिसे दुनिया में सर्वाधिक हत्या दर वाले देशों में से एक माना जाता है, खुशियों के मीटर में अमेरिका से ठीक नीचे 25वें पायदान पर है। हैरान करने वाली बात है कि आखिर वहां के लोग इतने खुश क्यों हैं। रिपोर्ट की मानें, तो वर्षों से आर्थिक संकट, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति से जूझ रहा वेनेजुएला भारत से ज्यादा खुशहाल है, तो क्या अराजकता और अस्थिरता ही अब वैश्विक खुशी के मापदंड बन चुके हैं? अगर ऐसा है, तो पूरी सभ्यता की कसौटियों का क्या? हत्यारे को हत्या करने में, तो किसी को बदला लेने में, तो किसी और को परोपकार करने में खुशी मिल सकती है। खुशी के पैमाने सबके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उन पैमानों को सामान्य बताकर ऐसा संशय पैदा करना कि लोग जान ही न सकें कि वास्तविक खुशी क्या है, कहां तक उचित है? जो सूचकांक ऐसा करते हैं, उनका स्तर महज एक दिन की सनसनी तक सीमित रह जाए, तो हैरत नहीं!

घर खरीदने वालों के सपनों में सेंध

फर्जीवाड़े से अनेक बिल्डर खुद मालामाल होकर कंपनियों को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। ऐसे बिल्डरों की निजी संपत्तियों को जब्त करके अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएं। इसके अलावा, भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डरों के खिलाफ कानून का सख्त डंडा चले, तो खरीदारों को सही मायने में न्याय के साथ घर भी जल्द मिलेगा।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

समय पर फ्लैट नहीं मिलने से हजारों लोग रो रहे हैं। हम उनके आंसू भले ही न पोंछ सकें, लेकिन उनकी समस्याओं का हल तो निकलना चाहिए। मुकदमेबाजी में फंसे हजारों घरों के खरीदारों से हमदर्दी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने बैंकों और बिल्डरों के सांठगांठ की सीबीआई जांच कराने की बात कही है। सीबीआई जांच के अंजाम को समझने के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में चल रहे दूसरे मुकदमों का हाल जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार, ढाई हजार से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामलों की जांच पांच साल से और 3,500 मामलों की जांच करीब 10 साल से सीबीआई के पास लंबित है। छह साल पहले जारी नोटिस के बावजूद सीबीआई और सीवीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर नहीं किया। घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान और बिल्डरों के कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में रेरा का गठन किया गया था, लेकिन अदालतों में बढ़ रहे मामलों से साफ है कि अधिकांश राज्यों में रेरा अपने मकसद को पूरा करने में विफल रही है।

सिस्टम से हताश और मुकदमेबाजी से परेशान घर खरीदारों की समस्याओं का मूल कारण समझकर ही उनका निवारण हो सकता है। दो साल पहले गठित अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े सभी पक्षकारों का विवरण शामिल है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार, पूरे देश में फंसे हुए दो तिहाई से ज्यादा प्रोजेक्ट एनसीआर और मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में हैं। सीएजी की पुरानी रिपोर्ट में नोएडा में बिल्डर, अफसर और नेताओं के गठजोड़ का विस्तार से खुलासा है। उसके अनुसार, वर्ष 2005 से 2018 के बीच सिर्फ तीन बिल्डरों को 80 फीसदी वाणिज्यिक प्लॉट का आवंटन हुआ था। उन कंपनियों से 14,958 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया वसूलने में नोएडा के अधिकारी विफल रहे। उनमें से एक कंपनी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने ईडी की जांच कराने की बात कही है।

अफसरों और बिल्डरों के भ्रष्ट गठजोड़ के और भी कई आयाम हैं। ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर तीन गांवों में 2,000 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कॉलोनी और विला बनवा दिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ऐसे प्रोजेक्ट्स में अफसर और बिल्डर मलाई हजम करके निरीह जनता को अदालतों के चक्कर काटने के लिए अभिशप्त कर देते हैं। घर खरीदारों की याचिका के अनुसार, डेवलपर्स की देरी के चलते उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं मिला, लेकिन ईएमआई के भुगतान के लिए बैंक उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बैंकों के वकील के दावे के अनुसार, दिवालिया हो रहे बिल्डरों के लिए बैंकों की जवाबदेही नहीं है। इस पर जजों ने सवाल पूछा कि साइट पर एक ईंट भी नहीं, तो फिर बैंकों ने 60 फीसदी लोन कैसे दे दिया। इस पूरे मामले की तह में जाने पर घर खरीदारों के साथ देश के खजाने को लग रही चपत को समझा जा सकता है।

वित्त मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 33.53 लाख करोड़ रुपये का हाउसिंग लोन है, जो जीडीपी का 11.25 फीसदी है। सभी बिल्डर गलत या दागी नहीं हैं। उनमें से कई लोग सिस्टम की वजह से प्रोजेक्ट को सही वक्त पर पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन, किसान आंदोलन, बैंकों का पठानी ब्याज और सुस्त नौकरशाही की वजह से प्रोजेक्ट के अप्रूवल और मास्टर प्लान में विलंब, इसके कारण रहे हैं। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ पहल करने की जरूरत है, जिससे कि घर खरीदारों को बेवजह की मुकदमेबाजी का सामना न करना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने कहा है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी साथ दे। अधूरे प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को कब्जा और घर का रजिस्ट्रेशन कैसे मिले, इस बारे में एनक्लैट और सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट से घर खरीदारों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए तीन मुद्दों को बारीकी से समझना जरूरी है। पहला-सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में जांच को कैसे भटकाया जा सकता है, इसकी बानगी 23 जनवरी, 2025 के आदेश से मिलती है। उसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित एसआईटी के अधिकारी जांच की आड़ में मुआवजा पाने वाले भू-स्वामियों को ही धमका रहे हैं। इसलिए नई एसआईटी में उत्तर प्रदेश से बाहर के आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है। लेकिन पुराने अनुभवों से साफ है कि एसआईटी या सीबीआई जांच से मीडिया की सुर्खियां भले ही बढ़ जाएं, लेकिन लोगों को जल्द न्याय मिलना मुश्किल है।

दूसरा-किसी एक प्रोजेक्ट में ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने के साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स से जुड़े उन लोगों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने की हैसियत नहीं रखते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से देश के सभी पीड़ित घर खरीदारों को न्याय मिलना चाहिए। तीसरा-आवास जनता का मौलिक अधिकार है, इसलिए ग्रीन बेंच की तर्ज पर घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष बेंच का गठन होना चाहिए। एक अन्य मामले में जजों ने कहा है कि जब तक अधिकारियों के ऊपर कंटेंप्ट कार्रवाई नहीं हो, तब तक अदालतों के फैसलों का पालन नहीं होता। इसलिए अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी बिल्डरों और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से कठोर दंड मिलना चाहिए।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सरकारी अथॉरिटी में ग्राहकों के साथ हो रही ठगी को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फर्जीवाड़े से अनेक बिल्डर सरकार और ग्राहकों का पैसा हवाला से ट्रांसफर करके खुद मालामाल होकर कंपनियों को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। ऐसे बिल्डरों की निजी संपत्तियों को जब्त करके अधूरे प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण होना चाहिए। जिन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों परिवारों के घर के सपने बिखर गए हैं, उनकी पेंशन को रोकने के साथ संपत्तियों का सरकार अधिग्रहण करे। भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ कानून का सख्त डंडा चले, तो घर खरीदारों को सही मायने में न्याय के साथ घर भी जल्द मिलेगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी शिवानंद सरस्वती

इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि कोई इन्सान किसी कार्य को करने के लिए एक ही प्रयास करता है, अगर वह काम हो गया, तो ठीक और नहीं हुआ, तो वह संतुष्ट हो जाता है। वह अतिरिक्त प्रयास करना भूल गया है।

अतिरिक्त प्रयास से ही बनेगी बात

क्या आपने कभी मानव जीवन के महत्व और महिमा को समझा है? और आपने कभी महसूस किया है कि यह जीवन कितना अनमोल उपहार है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन एक उत्कृष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? वास्तव में इसका उद्देश्य चिरस्थायी शांति और खुशी की प्राप्ति के लिए है। आप भी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि जीवन केवल सांस लेना, खाना, पचाना, सोना भर नहीं है, बल्कि जीवन में कुछ सार्थक हासिल भी करना है। आप जीवन को अच्छी तरह से तब जीते हैं, जब आप मन का संतुलन और उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के साथ-साथ मानवता के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग जीवन को इस तरह परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास खाने को टोस्ट, मक्खन और जैम, पहनने को फैशनेबल कपड़े, रहने को एक बंगला और घूमने के लिए एक मोटर कार तो होनी ही चाहिए। यह सब मिल भी गया, तो उसके बाद क्या? क्या केवल भौतिक सुख-सुविधाएं ही आपको वास्तविक सुख दे सकती हैं? केवल भौतिक सुख-सुविधाएं ही क्या आत्म को उन्नत कर सकती हैं? क्या केवल भौतिक सुख-सुविधाएं ही आपको साहस, शांति और आनंद प्रदान कर सकती हैं? निरंतर ध्यान भटकाने वाली इच्छाओं के चक्कर में जीवन के वास्तविक लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए।

अवास्तविक को वास्तविक, क्षणभंगुर को स्थायी समझने की भूल करना तथा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य आत्म-साक्षात्कार को भूल जाने से बड़ी कोई भूल नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि कोई इन्सान किसी कार्य को करने के लिए एक ही प्रयास करता है, अगर वह काम हो गया, तो ठीक और नहीं हुआ, तो वह संतुष्ट हो जाता है। वह अतिरिक्त प्रयास करना भूल गया है। आपने कभी सोचा है कि जब आप बच्चे थे, तब आप असहाय थे। अगर आपको बीमारी घेर लेती है और आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं, तब भी आप असहाय ही होते हैं। जब बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाएं आप पर टूट पड़ती हैं, उस वक्त भी आप असहाय ही होते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, तब भी आप असहाय ही होते हैं। फिर आप इतने घमंडी और अहंकारी क्यों हो गए हैं? अपने भ्रमों से ऊपर उठकर विवेक, आत्म-विश्लेषण के माध्यम से अच्छाई प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास ही जीवन को सही दिशा देगा। तभी आप अपने शरीर और मन से परे जा पाओगे, तभी मुक्त और खुश रह पाओगे। सत्य को साथी मानें और अच्छाई के मूल सिद्धांतों से विचलित न हों। इसके साथ परिश्रम और सावधानी से हृदय के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करें। साहस, दृढ़ विश्वास और सामान्य ज्ञान के साथ सच्चाई से अपना जीवन जिएं। समाज में कितने लोग आपसे डरते हैं, यह असली वीरता और साहस नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर अहंकार पर काबू पाना असली वीरता है। पूर्वाग्रह से पैदा हुए सभी भेद और मतभेदों को त्याग दें। सभी से प्यार करें। भाईचारे की भावना से सभी के साथ सहयोग करें और अपने दिल में करुणा की ज्योति जलाएं।

जीवन का हर पल जिएं

सूत्र

नकारात्मक गुणों पर विजय प्राप्त करें और अपने मधुर मूल घर, शाश्वत शांति और आनंद के निवास पर लौटें। परिश्रमपूर्वक संघर्ष करके और व्यावहारिक अच्छाई के जीवन के माध्यम से, जिसे योग कहा जाता है, इसी जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करें। इस तरह जीवन का हर पल जिएं।

दूसरा पहलू

डेढ़ सौ साल पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, आगरा में फिल्मों की तरह नहीं, बल्कि आधुनिक तरीके से इलाज होता है।

1857 की क्रांति और आगरा का पागलखाना

भूपेंद्र कुमार

उस अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल कॉल्विन की क्या कहानी है, जो 1857 की क्रांति में पागल हो गया था और उसकी कब्र आगरा फोर्ट में है।

अठारहवीं सदी के विशाल दरवाजे से प्रवेश करते समय लातिन अमेरिकी कथाकार ग्रैबियल गार्सिया मारखेज की मनोरोगियों की पृष्ठभूमि पर लिखी बेचैन करने वाली कहानी, मुझे तो बस एक कॉल करनी थी, जहन में तैरने लगती है। सामने 172 एकड़ में औपनिवेशिक काल की इमारतों वाला हरा-भरा कैंपस है। आगरा के प्रख्यात मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डॉ. दिनेश राठौड़ कहते हैं, 150 साल से ज्यादा पुराने इस संस्थान ने नए तौर-तरीकों को तेजी से अपनाया है।

फिल्मों में मानसिक रोगियों के इलाज को जिस तरह से दिखाया जाता है, वैसा कुछ अब नहीं है। यह आम अस्पताल की तरह है। ओपीडी में रोजाना लगभग 250 मरीज आते हैं। स्थायी मरीजों में ज्यादातर कुछ हफ्तों में ठीक होकर चले जाते हैं। जिनका परिवार नहीं है, वे यहां रहते हैं और फिर पुनर्वास संगठनों की मदद से बेहतर जीवन गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक चेयर पर बिजली के झटके जैसा कोई इलाज यहां नहीं है। तो फिर उस अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल कॉल्विन की क्या कहानी है, जो 1857 की क्रांति में पागल हो गया था और उसकी कब्र आगरा फोर्ट में दीवान-ए-आम के सामने है। इसके लिए हमें गुजरे दौर में लौटना होगा। आगरा में 1859 में पागलखाना बनाने की तात्कालिक वजह नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध, जिसका मुख्यालय आगरा था, के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का क्रांति के दौरान की परिस्थितियों की वजह से पागल होना था। उन्हें यहां कभी भर्ती नहीं किया गया। उनकी मौत की तात्कालिक वजह 9 सितंबर, 1857 को हैजे से हुई बताई गई। बाद में ब्रिटिश सरकार को लगा कि क्रांति से प्रभावित अंग्रेजों के इलाज के लिए आगरा में मानसिक संस्थान बनना चाहिए। इस संस्थान में भर्ती होने वाली पहली मरीज एक भिखारिन थी। उस समय आईजी जेल ही इसके प्रमुख होते थे। 1904 में लखनऊ का पागलखाना बंद कर इसके मरीजों और रिकॉर्ड को आगरा शिफ्ट कर दिया गया, ताकि एक ही जगह बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी साल आईजी जेल की जगह डॉ. काकरन को पहला मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया गया। 1957 में संस्थान के प्रमुख डॉ. केसी दुबे की पहल ने पूरी दुनिया का ध्यान आगरा की ओर खींचा। यह था मानसिक मरीजों के वार्ड खुले रखना। 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वायत्तशासी निकाय बना दिया और मेंटल हॉस्पिटल की जगह नया नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल। ...और आज यहां खिली धूप में अपनों और समाज से ठुकराए लोग भविष्य का ताना-बाना बुनते हैं।

कॉल्विन को यहां कभी भर्ती नहीं किया गया। उनकी मौत 9 सितंबर, 1857 को हैजे से हुई बताई गई। बाद में ब्रिटिश सरकार को लगा कि क्रांति से प्रभावित अंग्रेजों के इलाज के लिए आगरा में मानसिक संस्थान बनना चाहिए।

आंकड़े

मजदूरी की दर

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में लगे पुरुष मजदूरों को मिलने वाली दैनिक मजदूरी की दरें सबसे ज्यादा केरल में है।

राज्य	मजदूरी
केरल	893.6
तमिलनाडु	539.7
हिमाचल प्रदेश	526.9
आंध्र प्रदेश	524.5
हरियाणा	493.0

संबंधित राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी के आंकड़े, रुपयों में
स्रोत : RBI

रामानंद स्वामी आठ वर्ष की उम्र में द्वारकापुरी पहुंचे, तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण ने दर्शन देकर कहा, 'तुम उद्धव के अवतार हो, मेरे ज्ञान और भक्ति का प्रचार करो।'

रामानंद बने भक्ति के प्रचारक

अंतर्यात्रा
संकलित

रामानंद स्वामी के बारे में बताया जाता है कि वह उद्धव अवतार थे। अयोध्या में पैदा हुए रामानंद स्वामी के पिता का नाम अजय शर्मा और माता का नाम सुमति देवी था। माता-पिता ने उनका नाम श्रीराम शर्मा रखा था। आठ वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी पहुंचे।

बताया जाता है कि यहां पर भगवान श्रीकृष्ण ने रामानंद को साक्षात दर्शन देकर कहा, 'तुम उद्धव के अवतार हो, मेरे ज्ञान और भक्ति का प्रचार करो।' इसके बाद वह रैवताचल (गिरनार पर्वत) पर आत्मानंद महाराज के पास पहुंचे और उनसे दीक्षा ली, लेकिन निराकार वादी होने की वजह से वह उस स्थान पर ज्यादा दिन नहीं टिक सके। इसके बाद वह श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे, जहां वैष्णवराज रामानुजाचार्य ने उनको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर वैष्णवी महादीक्षा दी। इसके बाद वह उद्धवीय संप्रदाय का प्रचार करने लगे। वृंदावन में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की। तीर्थाटन करते हुए वह सौराष्ट्र पहुंचे, जहां उनके अनेक अनुयायी बन गए। बताया जाता है कि उन्होंने कई भक्तों को भगवान श्रीकृष्ण के साक्षात दर्शन भी करवाए थे। भगवान स्वामीनारायण ने खुद पीपलाणा नामक स्थान पर रामानंद स्वामी से दीक्षा ली थी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 10 फरवरी, 1966

भारत व चीन का संघर्ष विश्व भर के लिए चुनौती

भारत व चीन का संघर्ष
विश्व भर के लिये चुनौती

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड विल्सन ने भारत व चीन के आपसी संघर्ष और संबंधों की चर्चा की और कहा कि इस संघर्ष का परिणाम न केवल एशिया, बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती है।

अधिक संवेदनशील होने की जरूरत

पिछले कुछ वर्षों में सशस्त्र बलों की जरूरतों के प्रति सरकार संवेदनशील हुई है, लेकिन अब भी कई मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

महेंद्र तिवारी
मुद्दा

जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में पिछले छह महीने के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कार्यरत व सेवानिवृत्त कई कार्मिकों से मिलने का मौका मिला। इनमें पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत देश के अन्य हिस्सों के वीर व उनके सम्मानित परिजन शामिल थे। इनसे मिलते वक्त मन में कई सवाल थे। मसलन, देश के लिए जीने-बलिदान होने का जज्बा लेकर डटे इन वीरों और उनके परिजन में सेवा को लेकर संतुष्टि का स्तर क्या है? ये सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? जम्मू-कश्मीर में कितना बदलाव नजर आता है? लेकिन, सबसे बड़ी जिज्ञासा मन में यह थी कि सेवा में रहते हुए बल छोड़ने वाले कार्मिकों की संख्या बढ़ क्यों रही है?

इस जिज्ञासा की बड़ी वजह थी एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक, वर्ष 2020 से 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) व असम राइफल्स (एआर) के 55 हजार से ज्यादा कार्मिकों ने नौकरी छोड़ दी है। इनमें 47,891 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, जबकि 7,664 ने त्यागपत्र दे दिया।

पहली बात, सशस्त्र बलों व उनके परिवारों में कई अपेक्षाओं व उलाहनों के बावजूद सरकारों के प्रति सकारात्मक भाव बढ़ा है। बल के कार्मिकों से लेकर परिजन तक यह मानते हैं कि उनसे जुड़े मुद्दों पर पहले से बेहतर सुनवाई शुरू हुई है। पिछले कुछ वर्षों में उनके निजी हितों की ओर भी सरकार संवेदनशील हुई है। अगर वे अपने पारिवारिक विवाद, जमीन-जायदाद, सामाजिक मुद्दों को अपने गृह जिले व क्षेत्र में उठाते हैं, तो स्थानीय प्रशासन उस पर तत्परता से ध्यान देने लगा है। आम लोगों के बीच भी सम्मान का भाव बढ़ा है। 'भारत के वीर ट्रस्ट' बनने से वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के निकट संबंधियों को सहायता मिलनी सहज हुई है।

दूसरी अहम बात, वीरगति के बाद परिवार व सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य की चिंता से जुड़ी है। इनमें सेवा संबंधी लाभ, सुविधाएं, सेहत व उनकी मनोदशा जैसे विषय सबसे ऊपर हैं। इनमें टीस है कि दंगा, बवाल से लेकर सीमा व नक्सल प्रभावित उच्चतम संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चों पर वे तैनात होते हैं। पुलवामा व दंतेवाड़ा जैसा बलिदान देते हैं। लेकिन, सेना के समान सम्मान व सुविधाएं अब तक नहीं मिल पा रही हैं। इनमें पेंशन लाभ, कैंटीन से जुड़ी विसंगति, बच्चों की शिक्षा में आरक्षण, बल की भर्तियों में रक्त संबंधियों को रियायत से लेकर शहीद का दर्जा देने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं।

परिजन में टीस है कि बल में शामिल उनके घर का प्रिय सदस्य परिवार की आवश्यकता के ज्यादातर अवसरों पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। बलों में कार्यरत कार्मिकों के बच्चे चाहते हैं कि दूसरे बच्चों के मां-बाप की तरह उनके माता-पिता भी जन्मदिन व मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवंत पलों पर उनके साथ हों। घर में बुजुर्ग चाहते हैं कि वर्ष में उनके बेटे/बेटी का जन्मदिन, तो कम से कम उनकी आंखों के सामने मनाया जाए। घर में कोई महत्वपूर्ण अवसर हो, तो वे भी शामिल हों। लेकिन, अक्सर होता है कि बल के कार्मिक इन अनमोल पलों का भी हिस्सा नहीं बन पाते। परिवार से दूर बलों के कई कार्मिक और उनके परिजन इन खास मौकों पर अनुपस्थिति को सह नहीं पाते हैं। बल से वापसी का यह भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है।

इसी तरह कार्मिकों की सेहत व उनकी मनोदशा परिवारों में चिंता का विषय बन रही है। परिजन कहते हैं कि अर्धसैनिक बलों में सेवा के अवसर को कार्मिक के निरोगी और बलवान होने की निशानी के तौर पर लिया जाता था। लेकिन, इधर बीमारी या अवसाद से जान गंवाने वाले कार्मिकों की संख्या बढ़ी है। खास मौकों पर भी छुट्टी मिलने में कठिनाई अलग-अलग पृष्ठभूमि व समझ वाले परिवारों में कई बार कलह और विवाद की वजह बन जाती है, जो जान गंवाने तक पहुंच जाती है। सरकारी आंकड़े परिवारों की इस चिंता की तस्दीक करते हैं।

वर्ष 2019 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के 84 कार्मिकों की मौत हार्ट अटैक या अन्य बीमारियों से हुई थी। यह संख्या अब हर साल 100 पार कर रही है। इसी तरह हर वर्ष 100 से ज्यादा कार्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। चिंता वाली बात है कि अगस्त 2024 में लोकसभा में प्रश्नोत्तर में दिए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 तक अर्धसैनिक बलों के 577 जवानों की हार्ट अटैक या अन्य बीमारियों से मृत्यु हुई। वहीं, गत वर्ष चार दिसंबर को राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2020 से 2024 के बीच 730 कार्मिकों ने खुदकुशी की। ये आंकड़े विचलित करने वाले हैं। ऐसे में देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों और इनके परिवार को स्वस्थ व प्रसन्न रखना सरकार व समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। इस ओर हमें और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान
1936

हम कितने खुश

यह एक सुखद व स्वागतयोग्य आदिम जिज्ञासा है कि कौन कितना खुश है? शायद इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का इंतजार रहता है और इस साल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, खुशी की होड़ में शामिल किए गए दुनिया के 147 देशों में भारत का स्थान 118वां है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड की साझेदारी के तहत प्रकाशित इस खास विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 में गौर करने लायक अनेक बातें हैं। रिपोर्ट देखकर किसी को भी हतोत्साहित या दुखी होने की नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने की जरूरत है। खुशी मापने के अपने-अपने पैमाने संभव हैं। पहला असंतोष तो यही हो रहा है कि खुशी रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुश देश बताया गया है। पाकिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। यह बहस तलब है कि क्या पाकिस्तान में ज्यादा भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, हिंसा और आतंकवाद है? क्या खुशी की रिपोर्ट तैयार करने वालों के पैमाने में ही दोष है?

भारत के अन्य पड़ोसियों में श्रीलंका 133वें, बांग्लादेश 134वें और चीन 68वें स्थान पर है। यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी छोटे देश के लिए खुश होना ज्यादा आसान है। एक बड़े देश की चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। चीन खुशहाल और उभरती महाशक्ति होने का दावा करता है, पर वह दुनिया के 50 सबसे ज्यादा खुश देशों में शामिल नहीं है। भारत तो दुनिया में ऐसी किसी होड़ में शामिल नहीं होता है, पर चीन बढ़-चढ़कर तमाम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है, फिर भी वह सबसे ज्यादा खुश देशों में शुमार नहीं है! कहीं न कहीं चीन की विशाल आबादी भी आड़े आ रही होगी। चीन बड़ी आबादी के बावजूद भारत से पांच गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत आबादी के लिहाज से सबसे आगे निकल गया है और भारत की विविधता के अलावा उसके तंत्र की उदारता भी कहीं न कहीं खुशी में बाधा बन रही है। भारत में खुश लोगों की संख्या भी बहुत है और दुखी लोग भी बहुत हैं। यहां यह ध्यान रखना होगा कि खुशी केवल आर्थिक तरक्की की वजह से नहीं आएगी। देश में आर्थिक व सामाजिक स्तर पर और तेज विकास की जरूरत है। हालांकि, बहुत आर्थिक और सामाजिक विकास के बावजूद अमेरिका खिसकते हुए 24वें स्थान पर चला गया है।

यह ध्यान रखना होगा कि खुशी केवल आर्थिक तरक्की की वजह से नहीं आएगी। देश में आर्थिक व सामाजिक स्तर पर और तेज विकास की जरूरत है।

आश्चर्य नहीं, फिनलैंड फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है, उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। आश्चर्य नहीं, अफगानिस्तान खुशी के सबसे निचले पायदान पर पाया गया है, क्योंकि कई अफगान महिलाओं ने कहा है कि उनका जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल, हम भारतीयों को अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। भारत साल 2022 में 92वें स्थान पर पहुंच गया था, तो क्या हम सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं? समाज केंद्रित संस्कृति, परिवार और मिलकर रहने में हम आगे हैं, पर कौन लोग हैं, जो भारतीयों को स्वतंत्रता के पैमाने पर पीछे मान रहे हैं? यह स्वीकार करने में हर्ज नहीं कि पश्चिमी पैमाने भारतीयों की खुशी या दुख के सही आकलन में नाकाम हैं। खैर, हमें अपनी खुशी या सुख की यात्रा को आगे बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 21 मार्च, 1950

काश्मीर का आर्थिक मोर्चा

काश्मीर सरकार इस समय दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक मोर्चे का उद्देश्य है पाकिस्तानी आक्रमण से रियासत के अस्तित्व की रक्षा करना और दूसरे का उद्देश्य रियासत की आम जनता की आर्थिक अवस्था का सुधार करना है। दोनों मोर्चे एक-दूसरे के पूरक हैं। जितना पहला जरूरी है, उतना ही दूसरा भी। आर्थिक मोर्चे पर जितनी कामयाबी मिलेगी, वह अन्त में काश्मीर का भविष्य तय करने के लिये होने वाले जनमत-संग्रह को उतना ही अधिक प्रभावित करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि शेख अब्दुल्ला और उनकी सरकार का झुकाव साम्यवादी विचारधारा की ओर अधिक है। किंतु शेख अब्दुल्ला ने उस दिन राजधानी में पत्र-प्रतिनिधियों को बताया कि वह किसी खास विचारधारा के 'गुलाम' नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'हमारी मुख्य विचारधारा है, आम जनता की मदद करना, विभिन्न प्रकार के शोषणों से उसे मुक्त करना और सुखी बनाना।' जो सरकार सच्चाई और ईमानदारी के साथ आम जनता का भला करने की कोशिश करेगी, वही लोगों का प्रेम और विश्वास सम्पादन कर सकेगी।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि असली भारत उसके देहातों में बसता है। देहात ही उनकी योजना के मध्य बिन्दु रहते थे। खेती देश का मुख्य धन्धा है। उसी पर देश का जीवन मुख्यतः अवलंबित है। किंतु यदि खेती करने वाले किसानों की हालत ही दयाजनक रहेगी, तो देश का जीवन किस प्रकार सुखी और समृद्ध हो सकेगा? समय के प्रवाह के साथ देश के सभी भागों में खेती की बहुत सी जमीन खेती करने वालों के हाथों से निकलकर उन लोगों के हाथों में चली गई, जो स्वयं खेती नहीं करते, बल्कि दूसरों की मेहनत पर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस कारण खेतों पर जो काम करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। यह अस्वाभाविक स्थिति है और उसको खत्म करने के लिए भारतीय राज्यों में कदम उठाये जा रहे हैं। जागीरदारी, जमींदारी जैसी प्रथाओं का उन्मूलन किया जा रहा है। काश्मीर रियासत में भी जमींदारी को खत्म करने और वास्तव में खेती करने वालों को जमीन सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। काश्मीर के माल मंत्री का कहना है कि जम्मू और काश्मीर में जमीन के ऐसे मालिकों की संख्या जो खुद काश्त नहीं करते, १,२१,८०० है और उनके अधिकार में ६,४३,४००० एकड़ भूमि है।

फिर अमन का अमेरिकी आगाज

अमेरिका-रूस संबंध सुधार की जैसी कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वैसी ही कोशिश पहले राष्ट्रपति रुजवेल्ट, केनेडी और निक्सन कर चुके हैं।

यहां स्कैन करें

जोरावर दौलत सिंह | रणनीतिक विशेषज्ञ

हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पूरी मुखरता से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों से संबंध जोड़ना चाहता है। ध्यान रहे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यूक्रेन युद्ध को अमेरिका और रूस के बीच चल रहा एक ऐसा छद्म युद्ध बताया है, जिसे खत्म होना चाहिए। इस मोर्चे पर राष्ट्रपति ट्रंप और उप-राष्ट्रपति वेंस अपने सार्वजनिक बयानों में ज्यादा स्पष्ट रहे हैं।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की सबसे हालिया 2.5 घंटे लंबी टेलीफोन वार्ता में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका व रूस के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंधों वाला भविष्य बहुत लाभकारी है। यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने स्थायी शांति की जरूरत पर रजामंदी का इजहार किया है। यह तय हुआ है कि दोनों नेता संघर्ष को व्यापक रूप से खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत शुरू करेंगे।

ध्यान रहे, यह अमेरिका-रूस संबंधों की एक अशांत सदी में निर्णायक मोड़ है, इससे पहले कुछ ही ऐसी मिसालें हैं, जब मेल-मिलाप के ऐसे मौके मुमकिन जान पड़े थे। पहला मौका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब आया था, जब विश्व स्तर पर अलग-थलग पड़े सोवियत शासन ने अपने देश में व्यवस्था व आर्थिक स्थिरता बहाल की थी। तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज भी महामंदी से जूझ रहा था। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट ने 1933 में सोवियत रूस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उस दशक में जब नाजी जर्मनी पूरे यूरोप में उत्पात मचा रहा था, तब वाशिंगटन और मॉस्को, दोनों इस दुष्ट विचारधारा का सिर कलम करने के लिए एक ऐतिहासिक गठजोड़ में शामिल हो गए थे।

संबंधों में सुधार की दूसरी खिड़की 1960 के दशक की शुरुआत में खुली थी। साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान युद्ध के खतरे बहुत गंभीर हो गए थे, जब महाशक्तियां परमाणु टकराव के कगार पर पहुंच गई थीं। तब केनेडी की चतुर 'बैक चैनल' कूटनीति से और सत्ता प्रतिष्ठान में मौजूद कट्टरपंथियों को किनारे लगाने के बाद भू-राजनीतिक स्थिरता बहाल हुई थी। खतरनाक टकरावों के ढर्रे को बदलने की कसम खाते हुए केनेडी ने जून 1963 में अपना प्रसिद्ध शांति भाषण दिया था, जहां उन्होंने सोवियत रूस के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, 'इतिहास हमें सिखाता है कि राष्ट्रों के बीच दुश्मनी... हमेशा के लिए नहीं रहती है।'

अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार का तीसरा चरण वियतनाम में अपनी हार से अमेरिका की रणनीतिक थकावट और देश में अंदर-बाहर की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुआ। घरेलू स्तर पर फैलती अशांति राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जैसे शीत योद्धा की विश्व दृष्टि को बदलने के लिए पर्याप्त थी। तब 1970 के दशक में चीन के साथ तालमेल और सोवियत संघ के साथ समझौता हुआ, जिसका अमेरिकियों ने समर्थन किया। लोगों ने निक्सन को 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में 521 चुनावी वोटों के साथ बड़ी जीत से नवाजा। तीनों ही मामलों में, अमेरिका की ओर से अमन की मांग की गई और सोवियत रूस ने मुकम्मल जवाब दिया।

ध्यान देने की बात है कि संबंध सुधार का हर चरण अमेरिकी नेता के निधन के साथ समाप्त हुआ है और फिर नीतियों में आमूल-चूल बदलाव की शुरुआत हुई है। जैसे, रूजवेल्ट ने रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था की कल्पना की थी, पर वह 1945 तक दुनिया से विदा हो गए। उनकी जगह ऐसे लोग सत्ता में आए, जो हर कीमत पर दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व के हिमायती थे। नतीजा, कुछ ही वर्षों में शीत युद्ध छिड़ गया। केनेडी की वैश्विक दृष्टि भी बहुत परिष्कृत थी। वह खतरों के प्रति सचेत थे। उन्हें एहसास हो गया था कि प्रतिद्वंद्वी के साथ संबंध सुधारना प्रत्येक महाशक्ति और पूरे विश्व के हित में है। 1978 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन एसेसिनेशन्स द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के अनुसार, केनेडी को सचमुच साजिश से मारा गया था। केनेडी के बाद फिर से अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करने की पुरानी नीति ने सिर उठा लिया था। यह नीति तब तक चली, जब तक वियतनाम में झटका न मिला।

ठीक इसी तरह, राष्ट्रपति पद से निक्सन की अपमानजनक विदाई के साथ, तनाव कम करने या संबंध सुधारने की नीति समाप्त हो गई थी और 1980 के दशक में दुनिया में नए सिरे से शीत युद्ध ने फन फैला लिया। इस ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का दौर टिकाऊ है?

बहरहाल, तनाव घटाने की दिशा में अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहले, यूक्रेन में हस्तक्षेप करके अमेरिका वास्तव में थक चुका है। उसे खजाने, सैन्य साख और वैश्विक स्थिति में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी, ट्रंप को एक नई दुनिया विरासत में मिली है। यह दुनिया कतई वैसी एकध्रुवीय नहीं दिखती है, जब अमेरिका विश्व पटल पर बेरोक आगे बढ़ रहा था। तीसरी, वैश्विक प्रतिष्ठानों का संस्करण अब अमेरिकी राजनीतिक निकायों के साथ मेल नहीं खा रहा है।

इसमें कोई शक नहीं कि रूस के साथ फिर जुड़ाव की अमेरिकी खोज असली है और यह विश्व व्यवस्था को स्थिर करने व बहुध्रुवीय दुनिया में बेहतर बदलावों को बहाल करने की ओर इशारा करती है। संबंध सुधार का यह नया चरण स्वाभाविक ही पारंपरिक अभिजात वर्ग के लिए खतरा है, जो यह समझता है कि रूजवेल्ट, केनेडी और निक्सन ने मास्को के साथ तनाव घटाने की कोशिश करके पाप किया था। वास्तव में, पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी सियासी तंत्र में वैश्विकतावादी सोच रखने वाले अभी भी मौजूद हैं। इस वैचारिक तंत्र को वापस लाने के लिए दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ेगी, यहां एकमात्र अगुवा के रूप में डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

यह पूर्वानुमान मुश्किल है कि संबंध सुधार का नया चरण कैसे सामने आएगा। जिस बात पर जोर दिया जा सकता है, वह यह है कि अब दुनिया में शक्ति संतुलन उन पिछली मिसालों के विपरीत है, जब दुनिया के बाकी हिस्सों पर अमेरिकी श्रेष्ठता जगजाहिर थी। आज गैर-पश्चिमी दुनिया ज्यादा सक्षम व शक्तिशाली है। सत्ता के नए बहुध्रुवीय विन्यास को अब पुराने पश्चिमी प्रतिष्ठान द्वारा उलटा नहीं जा सकता। दरअसल, यही बुनियादी हकीकत डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यावहारिक नेता और राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत करती है, जो एक महान शक्ति के रूप में अमेरिका के लिए ज्यादा यथार्थवादी भविष्य का सपना दिखा रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

राष्ट्रपति भवन में रमजान और खत्म शरीफ की परंपरा

यहां स्कैन करें

विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

अगर आप राष्ट्रीय राजधानी के मदर टेरेसा क्रेसेंट से राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 13 से अंदर जाएं, तो वहां आपको एक मस्जिद मिलेगी। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभी ने रमजान के दौरान यहां नमाज अदा की है। यह राष्ट्रपति भवन की मस्जिद है। यहां सभी राष्ट्रपति रमजान के दौरान खत्म शरीफ के मौके पर पधारते हैं। रमजान के आखिरी अशरे में खत्म शरीफ का आयोजन किया जाता है, जिसमें *कुरान शरीफ* का पाठ पूरा किया जाता है। यह एक तरह की इबादत है, जिसमें *कुरान* का पाठ शामिल है। जिस दिन यह पूरा होता है, उसे खत्म शरीफ कहा जाता है। इस दिन, राष्ट्रपति धूमधाम से मस्जिद में आते हैं और राष्ट्रपति भवन की मस्जिद के इमाम को पगड़ी और उपहार भेंट करते हैं। बेशक, यहां से भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक गहरा मौलिक संदेश सारे संसार में जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खत्म शरीफ के अवसर पर हमेशा राष्ट्रपति भवन मस्जिद में पधारते थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में रहने वाले कर्मचारी भी सपरिवार मौजूद रहते हैं।

राष्ट्रपति भवन में इस मस्जिद का निर्माण 1950 के दशक की शुरुआत में हुआ था। बता दें कि जब 1931 में राष्ट्रपति भवन (पूर्व में वायसराय हाउस) बनकर तैयार हो गया, तब वहां कोई मंदिर या मस्जिद नहीं थी। इसके वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने मस्जिद के लिए कोई जगह आवंटित नहीं की थी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहल पर ही राष्ट्रपति भवन परिसर में एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि चर्च या गुरुद्वारे के लिए जगह आवंटित नहीं की गई थी, क्योंकि गुरुद्वारा रकाब गंज और नॉर्थ एवेन्यू का कैथेड्रल चर्च राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर स्थित हैं। एक अनुमान के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन के अंदर करीब 500 परिवार रहते हैं। राष्ट्रपति भवन मस्जिद के पहले इमाम हाफिज हसीनउद्दीन साहब थे। वह मेरठ से थे और 2005 में उनका निधन हो गया। उन्होंने दशकों तक राष्ट्रपति भवन मस्जिद में सेवा की।

ईद पर राष्ट्रपति भवन मस्जिद में उत्सव का माहौल होता है। राष्ट्रपति की ओर से सभी कर्मचारियों को मिठाई बांटी जाती है। मस्जिद के इमाम के लिए अपने परिवार के साथ यहां रहने का भी प्रावधान है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से उनके विवाहित बच्चों को यहां रहने की अनुमति नहीं है। इमाम का वेतन यहां रहने वाले कर्मचारियों के सहयोग से ही दिया जाता है। यहां सिर्फ राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी ही नमाज अदा कर सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन के पुराने मुलाजिमों को याद है, जब डॉक्टर कलाम भी जुमा की नमाज अदा करने पहुंचते थे। वह नमाज के बाद उन सभी लोगों के साथ कुछ समय बिताते थे, जो उनके साथ नमाज पढ़ रहे होते थे। डॉक्टर कलाम युवा नमाजियों से उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में अवश्य बातें करते थे।

राष्ट्रपति भवन में प्रथम राष्ट्रपति के समय से ही दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस, बाबा नानक का जन्मदिन मिलकर मनाने की परंपरा है।

वैसे, राष्ट्रपति भवन की मस्जिद के पास एक मंदिर भी है। यहां सभी प्रमुख हिंदू त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दरअसल, राष्ट्रपति भवन में देश के सभी महत्वपूर्ण त्योहार मनाने की परंपरा देश के प्रथम राष्ट्रपति ने शुरू की थी। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने स्टाफ से त्योहारों का आयोजन करने और उनमें राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। वह आगंतुकों और कर्मचारियों के साथ सूखे रंगों से होली खेलते थे। इस अवसर पर उनकी पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी प्रसाद मेहमानों के साथ भोजन करती थीं। सभी उन्हें 'मां जी' कहते थे। परिसर में लगभग हर त्योहार मनाने की परंपरा चल निकली थी। राजेंद्र बाबू कुछ समय रुकने के बाद व्यस्त होने के चलते चले जाते, पर उनकी पत्नी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहती थीं। राष्ट्रपति भवन के सैकड़ों कर्मचारी देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के नेतृत्व में शुरू से दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस, बाबा नानक का जन्मदिन मिलकर मनाते आए हैं। जो भी इन गरिमामय कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है, वह हमेशा के लिए गौरवान्वित हो जाता है।

बेशक, यह बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति भवन में सभी प्रमुख त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

प्रश्नों से जो परे, वही प्रेम

तुम किसके साथ सहज और स्वच्छंद अनुभव करते हो? उसी के साथ, जो तुम्हारे प्रेम पर संदेह नहीं करता, जो विश्वास करता है कि तुम उसको प्यार करते हो। है न? जब कोई तुम्हारे प्रेम पर संदेह करता है और तुम्हें निरंतर अपने प्रेम को साबित करना पड़ता है, तब यह तुम्हारे लिए एक भारी बोझ बन जाता है। ऐसे लोग तुमसे प्रश्न करते हैं और तुम्हारे प्रत्येक कार्य का स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो, उसकी व्याख्या देना मानसिक बोझ है। तुम्हारा स्वभाव है, बोझ को हटाना और जब तुम्हारे प्रेम पर प्रश्न किया जाता है, तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता।

जब तुम किसी कार्य का कारण जानना चाहते हो, तो स्वयं के लिए न्याय मांग रहे हो और तुम एक दूरी पैदा करते हो। तुम्हारा पूरा उद्देश्य है समीप आना, लेकिन तुम एक दूरी पैदा कर देते हो। जब लोग कार्यों का स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो वे कर्ताभाव से बोल रहे हैं और उस कर्तापन को तुम पर थोप रहे हैं। यह बेचैनी लाता है। जब कोई इस तरह तुम्हारे साथ है, जैसे तुम्हारा ही हिस्सा, तब वह तुमको प्रश्न नहीं करता। इसमें संपूर्ण निकटता और एकता है, जो प्रश्नों के परे है। न तो स्पष्टीकरण मांगो और न ही दो।

तुम किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम अनुभव करते हो और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तब तुम क्या करते हो? हताश हो जाते हो, प्रेम को नफरत में पलटकर बदले की इच्छा रखते हो, बार-बार उसे यह याद दिलाते हो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो और वह तुम्हें कितना कम! तुम तुनकमिजाज और सनकी हो जाते हो, गुस्सा प्रदर्शित करते हो, अपमानित महसूस करते हो और अपने सम्मान की रक्षा की चेष्टा करते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि दोबारा कभी प्रेम नहीं करोगे, आहत हो जाते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारे संग अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। तुम अलग और उदासीन रहना चाहते हो।

परंतु तुम देख चुके हो कि इनमें से कुछ भी काम नहीं करता; ये चीजें स्थिति को और बिगाड़ती हैं। तो इससे निकलने का उपाय क्या है? अपने प्रेममय स्वभाव को हम कैसे बनाए रखें? धैर्य रखो, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को बदलो। केंद्रित रहो और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सीमित रखो। कभी-कभी प्रेम की अत्यधिक अभिव्यक्ति भी लोगों को दूर कर देती है। यह मान लो कि वे भी तुम्हें प्यार करते हैं और उनके प्रेम की अभिव्यक्ति जैसी है, उसे स्वीकार करो। यह तुम्हारी मांग को कृतज्ञता में बदल देगा। जीवन में तुम जितना अधिक कृतज्ञ होते हो, तुम्हें उतना ही अधिक प्रेम मिलता है।

प्रेम की अभिव्यक्ति जैसी है, उसे स्वीकार करो। यह तुम्हारी मांग को कृतज्ञता में बदल देगा। जीवन में तुम जितना अधिक कृतज्ञ होते हो, तुम्हें उतना ही अधिक प्रेम मिलता है।

जान लो, दर्द प्रेम का अंश है और इसके लिए भी जिम्मेदारी लो। जब तुम अपने केंद्र से दूर होते हो, तब तुम दुखी होते हो और सांसारिकता का स्वभाव दुख है।

श्री श्री रविशंकर

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

विधायकों को विधानसभा के नियमों की, प्रक्रिया की जितनी अधिक जानकारी होगी, सदन का उतना ही श्रेष्ठ उपयोग हो पाएगा। सदस्य प्रश्नकाल सहित अन्य प्रक्रियागत साधनों द्वारा सदन में बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे।

संकीर्ण राजनीति का अखाड़ा न बनें छात्र संघ

लोकतंत्र में छात्र संघों और छात्र नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छात्र संघ युवा मन का सकारात्मक, संगठित और साकार रूप हैं। वे युवाओं की शक्ति और ऊर्जा के मान्य प्रतिनिधि हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन, आरक्षण संबंधी सामाजिक न्याय आंदोलन, श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्र-ध्वज फहराने संबंधी तिरंगा आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन तक समाज-सत्ता को बदलने संबंधी सभी बड़े आंदोलनों में छात्रों और छात्र संघों की बड़ी भूमिका रही है। उल्लेखनीय है, आपातकाल विरोधी जन-आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अग्रणी भूमिका थी। यह वह दौर था, जब छात्र व्यवस्था में सुधार या बदलाव की सकारात्मक राजनीति करते थे। व्यक्तिगत स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं से परे जाकर वे सामाजिक-राष्ट्रीय मुद्दों व छात्रहित के लिए त्याग एवं समर्पण के साथ काम करते थे। वे सपने देखने वाले और जुनूनी लोग थे। वे 'करियरिस्ट' नहीं थे। वे पढ़ने-लिखने में भी अच्छे होते थे।

इक्कीसवीं सदी आते-आते मुख्यधारा की राजनीति में अपराधियों व धन-पशुओं का बोलबाला होने लगा था। छात्र संघ व छात्र राजनीति भी इस बदलाव से अछूती नहीं रह सकी। आज छात्र राजनीति मुख्यधारा की राजनीति का शॉर्टकट रास्ता है। यह एक प्लेटफॉर्म है। आज मुख्यधारा की राजनीति की जो भी बुराइयां हैं, वे छात्र राजनीति में भी साफ दिखाई देती हैं। छात्र संघ चुनाव जीतने की अर्हता जाति, धनबल और बाहुबल है। लालच और डर का खुला खेल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में होता है। लिंगदोह कमेटी की नियमावली की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो प्रत्याशी या संगठन धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल नहीं करता, उसे कमजोर समझा जाता है। यही कारण है कि बढ़ती गुंडागर्दी और हिंसा के कारण कई राज्य सरकारों ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी है।

पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुने हुए छात्र नेता शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मियों के साथ अभद्रता और मार-पीट तक करने लगे हैं। फिर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे निंदनीय आचरण की रील बनाते हैं और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल करते हैं। विवि प्रशासन को इसका गंभीर संज्ञान लेकर ऐसी अपराधी मानसिकता और व्यवहार की नकेल कसने की जरूरत है।

प्रो. रसाल सिंह, प्राचार्य

अनुलोम-विलोम

विश्वविद्यालय छात्र संघ

विद्यार्थी संघ कॉलेजों के लिए बहुत जरूरी

देश के राजनीतिक-सामाजिक आंदोलनों में छात्र संघों की क्या भूमिका रही है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुनिया भर में बड़े राजनीतिक बदलावों में इन विद्यार्थी संघों ने अहम भूमिका निभाई है। मगर हाल के दिनों में, खासकर भारत में मुख्यधारा की कलुष राजनीति की छाया पड़ने से ये विद्यार्थी संघ भी कुछ विचलन के शिकार हुए हैं। मगर उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। हालांकि, कई दशकों से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक लोग इनसे मुक्ति पाने की तरकीबें भिड़ाते रहते हैं। इसकी ठोस वजहें हैं।

पिछले कुछ दशकों में, खासकर आपातकाल के ठीक बाद हुए चुनावों में बड़ी संख्या में कॉलेजों के प्राध्यापक विभिन्न पार्टियों के सिंबल पर लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच गए। नतीजा यह निकला कि बड़ी संख्या में कॉलेज शिक्षकों के भीतर दलीय राजनीति के प्रति रुझान पैदा हुआ। वे लाइब्रेरी में वक्त बिताने के बजाय विभिन्न पार्टियों और राजनेताओं के यहां दरबार लगाने लगे। सबसे बुरी बात यह है कि अन्य सेवाओं की तरह चुनाव लड़ने के लिए उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने की बाध्यता भी नहीं है। चूंकि यूजीसी एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए उन्हें यह छूट हासिल है। इसलिए उनका ध्यान क्लास व पठन-पाठन के प्रति बहुत गंभीर नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक इसी प्रवृत्ति के थे या हैं। मगर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के कॉलेजों में विषयवार प्राध्यापकों की उपलब्धता कितनी कम है? यदि उनमें से एक चौथाई प्राध्यापक भी राजनीतिक दलों के आकाओं की परिक्रमा में जुटे हों, तो फिर सोचिए कि वहां के विद्यार्थियों की क्या स्थिति होगी? ऐसे में, छात्र संघ उचित ही कॉलेज-विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। यह बात गुरु जी लोगों को नागवार गुजरती है।

कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं कि शिक्षक शराब पीकर क्लास लेने आ गए, मगर कक्षा के विद्यार्थी बिगाड़ के डर से उनका विरोध न कर सके, तब छात्र संघ उनकी मदद के लिए आगे आया। एक पहलू भ्रष्टाचार का भी है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विभिन्न मदों में सरकार व यूजीसी से अच्छा-खासा कोष मिलता है। उनमें भ्रष्टाचार पर भी छात्र नेताओं की नजर होती है, यह बात भी कुलपतियों, प्राचार्यों व शिक्षकों को रास नहीं आती। लिहाजा, वे अब छात्र संघ से ही मुक्ति पा लेना चाहते हैं। मगर यह घातक होगा, क्योंकि ये न सिर्फ देश की राजनीति की नर्सरियां हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण नियंत्रक इकाई भी।

यशस्वी राय, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 21 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं, और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं।
-गौतम बुद्ध

गड़े मुर्दों की राजनीति

महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है, और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यह हिंसा औरंगजेब की कब्र हटाने की अफवाह के बाद दो गुटों में हुई झड़प और पत्थरबाजी के बाद भड़की। इस सांप्रदायिक उन्माद भड़कने का कारण एक फिल्म में संभाजी और औरंगजेब के बीच ऐतिहासिक युद्ध के फिल्मांकन को माना जा रहा है। उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहाना कि फिल्म में सच्चा इतिहास दिखाने के चलते दंगे भड़के, निहायत गैर-जिम्मेदाराना और समुदाय विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। इसे औरंगजेब के प्रति गुस्सा बता कर उन्होंने शांति बहाली की बजाय अपनी पक्षपाती सोच ही उजागर की है। पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में

सभी 51 संदिग्ध मुसलमान हैं। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल द्वारा किए गए प्रदर्शन और पुतला जलाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों समेत प्रशासन चुप्पी साधे हैं। पुलिस के अनुसार दंगाई कुल्हाड़ी, डंडे, लोहे के सरिए और ईंट-पत्थर हाथों में लिए हुए थे। उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला तक किया। पुलिस वाहन फूंके गए, महिला पुलिसकर्मियों तक को नहीं बख्शा। सियासी दलों का आरोप-प्रत्यारोप का दौर चालू है, और नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी लगातार जारी है। जो वाहन, घर-दुकानें फूंके गए, उससे दोनों समुदाय के लोगों को क्षति पहुंची जिसकी भरपाई करने में सालों का वक्त लग सकता है। मुगल बादशाह को निशाने पर रख कर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दल ने जनता का ध्यान भटकाने का सिलसिला जारी रखा है। गड़े मुर्दे उखाड़ कर बजरिए इतिहास वे जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी समस्याओं को गड्ढे में डालने के प्रयास करते हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और देश की अखंडता को ठेस लगती है। विभाजनकारी बातें और भड़काऊ बयानबाजी पर पाबंदी न लगाई गई तो इसके विपरीत असर समूचे राष्ट्र को भुगतने पड़ सकते हैं। जनता को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस भटकाव से तौबा करना सीखना होगा। अराजक तत्वों, दंगाइयों और पुलिसकर्मियों पर हिंसक बल प्रयोग करने वाले उपद्रवियों को कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मगर इस सबके पीछे की साजिशों का भंडाफोड़ करने में भी कोताही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे वैश्विक रूप से देश की छवि भी कम धूमिल नहीं होती।

ट्रंप की मध्यस्थता और शांति

रूस और यूक्रेन के बीच तीन वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर भी बातचीत पूर्ण युद्धबंदी की दिशा में बढ़ाया गया सकारात्मक कदम है। दोनों शीर्ष नेताओं ने सीमित युद्ध विराम पर सहमति जताई। इस सशर्त शांति समझौते के तहत रूस 30 दिनों तक रूस और रूस दोनों एक दूसरे के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी तरह युद्ध विराम पर अपनी सहमति नहीं दी और यह शर्त भी रख दी कि एक महीने के दौरान यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य सहायता पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए,

यूक्रेन सैन्य शक्ति न जुटाए। हालांकि सीमित युद्ध विराम के बीच रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए सशर्त शांति समझौते की राह में अनेक तरह की बाधाएं और जटिलताएं भी दिखाई दे रही हैं। रूस के द्वारा सीमित युद्ध विराम के लिए जो शर्त निर्धारित की गई हैं, वे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनसे एकदम अलहदा है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को यह सुरक्षा गारंटी मिले कि रूस भविष्य में यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। करीब बीस दिन पहले जब व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप ने फटकार लगाई थी तब ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों की बैठक आयोजित कर यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया था। वास्तव में पश्चिमी यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अलग से योजना बना रहे हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि यूक्रेन के कुल भूभाग का करीब पांचवा हिस्सा रूस के कब्जे में है। यूक्रेन आश्वस्त नहीं है कि रूस इस भूभाग को उसे लौटाएगा। जाहिर है पूर्ण युद्धविराम के लिए इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत होनी चाहिए। जहां तक भारत का संबंध है तो वह संवाद और कूटनीति के जरिए समस्याओं का हाल चाहता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप के प्रयासों से स्थाई युद्ध विराम होगा और रक्तपात तथा तबाही का अंत होगा, लेकिन यूरोपीय देशों को भी ट्रंप का समर्थन करने के लिए आगे आना होगा।

विश्व कठपुतली दिवस/अमरपाल सिंह वर्मा

मंच तो सजे हैं मगर...

बदले परिवेश में यह पारंपरिक कला लगातार उपेक्षा की शिकार होकर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पहले गांव-गांव में कठपुतली को धागे से नचाने वाले कलाकार थे, जो अब अंगुलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। राजस्थान अपनी रंग-बिरंगी लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश की लोक संस्कृति अपने में लोक कलाओं के कई रंग समेटे हुए है। यहां की लोक कलाओं का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रही है कठपुतली कला। सदियों से यह कला न केवल लोक मनोरंजन का माध्यम रही है, बल्कि सामाजिक संदेशों, ऐतिहासिक घटनाओं और लोक गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भी रही है।

लेकिन बदले परिवेश में यह पारंपरिक कला लगातार उपेक्षा की शिकार होती चली गई और धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पहले गांव-गांव में कठपुतली को धागे से नचाने वाले कलाकार थे, जो अब उंगलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। विभिन्न मंच तो अब भी सजते हैं पर कठपुतलियां गायब हैं। कुछ दशक पहले तक कठपुतली कला न केवल स्वस्थ मनोरंजन का जरिया थी, बल्कि लोक शिक्षा का माध्यम भी थी। कोई भी मेला कठपुतली के बिना अधूरा माना जाता था। इंसान के इशारे पर नाचने वाली बेजान कठपुतलियों ने जहां राजा-महाराजाओं की वीरता की कहानियां जन-जन तक पहुंचाईं, वहीं लोक में प्रचलित विभिन्न प्रेम कहानियों को भी विख्यात किया। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के प्रति जागरूकता जगाने में कठपुतली कला का बड़ा योगदान रहा है। अशिक्षित जन तक नैतिक शिक्षाओं और सामाजिक संदेशों को विशिष्ट भाव-भंगिमाओं और चुटीले संवादों के जरिए जितने सरल और प्रभावी तरीके से इन कठपुतलियों ने पहुंचाया, लोक कलाओं में वैसा दूसरा उदाहरण मिल पाना मुश्किल है। बीस-तीस साल पहले तक कठपुतली का महत्त्व बरकरार था पर जैसे-जैसे मनोरंजन के आधुनिक साधनों का आगमन हुआ, यह अनूठी कला धीरे-धीरे हाशिए पर चली गई। पहले लोग मनोरंजन के पास खुद चल कर जाते थे लेकिन जब केवल टीवी के तार के जरिए मनोरंजन उनके घर तक पहुंचने लगा तो स्थितियां बदलने लगीं। हजारों टेलीविजन चैनलों, सिनेमा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते असर से पारंपरिक लोक कलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। पूरा दिन स्मार्टफोन में घुसे रहने वाले लोग कठपुतली प्रदर्शन देखने जाएंगे, यह सोचना भी व्यर्थ लगता है।

वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं

वन दिवस

प्रमोद भार्गव

वैश्विक फलक पर सबसे अहम गणना, जनगणना मानी जाती है। हालांकि पालतू-पशु, वन्य जीव और वृक्षों की गिनती भी होती रही हैं, लेकिन इन्हें जनगणना के मुकाबले अहमियत नहीं दी जाती। यही वजह रही कि विश्व स्तर पर वृक्षों की गिनती के निष्कर्षों को समाचार माध्यमों ने उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था, जबकि पेड़ों की अस्मिता पर ही मनुष्य और अन्य प्राणियों का जीवन टिका है। गोया, पेड़ ऐसी प्राकृतिक संपदा है, जिसका यदि विनाश होता है, तो मनुष्य का सुखद जीवन भी संभव नहीं है।

जब से मानव सभ्यता के विकास का क्रम शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक वृक्षों की संख्या में 46 फीसद की कमी आई है। पेड़ों की गिनती के अब तक के सबसे समग्र वैश्विक अभियान में दुनिया भर के वैज्ञानिक समूहों ने यह निष्कर्ष निकाला है। इस अध्ययन का आकलन है कि विश्व में तीन लाख करोड़ वृक्ष हैं यानी मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति 422 पेड़ हैं। हालांकि यह आंकड़ा पूर्व आकलित अनुमानों से साढ़े सात गुना ज्यादा बताया जा रहा है। दरअसल, पूर्व के वैश्विक आकलन ने तय किया था कि दुनिया भर में महज 400 अरब पेड़ हैं। मसलन, प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 61 है। यह आकलन व्यक्ति आधारित था, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था। दरअसल, दुनिया में अभी भी ऐसे दुर्गम स्थलों पर जंगलों का विस्तार है, जहां सर्वेक्षण में लगे मानव-समूहों का पहुंचना और पहुंच कर सर्वे करना आसान नहीं है क्योंकि इन जंगलों में एक तो अभी रास्ते नहीं हैं। दूसरे, खतरनाक वन्य-जीवों की मौजूदगी भी है।

पेड़ों की यह गिनती उपग्रह द्वारा ली गई छवियों के माध्यम से की गई है। इस गणना को तकनीक की भाषा में 'सेटेलाइट इमेजरी' कहते हैं। इस तकनीक से पूरा सर्वे वन-प्रांतरों में लिया गया है। इसमें जमीनी स्तर पर कोई आंकड़े नहीं जुटाए गए हैं। अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिष्ठित जनरल 'नेचर' में छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेड़ों की उच्च सघनता रूस, स्कैंडीनेविया और उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाई गई है। इन घने वनों में दुनिया के 24 फीसद पेड़ हैं। पृथ्वी पर विद्यमान 43 प्रतिशत यानी करीब 1.4 लाख करोड़ पेड़ उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों में हैं। इन वनों का चिंताजनक पहलू यह भी है कि वनों या पेड़ों की घटती दर भी इन्हीं जंगलों में सबसे ज्यादा है। 22 फीसद पेड़ शीतोष्ण क्षेत्रों में हैं। इस अध्ययन की प्रामाणिकता इसलिए असंदिग्ध है, क्योंकि इस सामूहिक अध्ययन को बेहद गंभीरता से किया गया है। इस हेतु 15 देशों के वैज्ञानिक समूह बने। इन समूहों ने उपग्रह

चित्रों के माध्यम से वन क्षेत्र का आकलन प्रति वर्ग किलोमीटर में मौजूद पेड़ों की संख्या के मानचित्रीकरण में सुपर कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करके किया है। इस गिनती में दुनिया के सभी सघन वनों की संख्या 4 लाख से भी अधिक है। दुनिया के ज्यादातर राष्ट्रीय वन क्षेत्रों में हुए अध्ययनों को भी तुलना के लिए जगह दी गई। उपग्रह चित्रों के इस्तेमाल से पेड़ों के आकलन के साथ स्थानीय जलवायु, भौगोलिक स्थिति, पेड़-पौधे, मिट्टी की दशाओं पर मानव के प्रभाव को भी आधार बनाया गया।

इससे जो निष्कर्ष निकले, उनसे तय हुआ कि मानवीय हलचल और उसके जंगलों में हस्तक्षेप से पेड़ों की संख्या में गिरावट की दर से सीधा संबंध है। जिन वन-क्षेत्रों में मनुष्य की आबादी बढ़ी है, उन क्षेत्रों में पेड़ों का घनत्व तेजी से घटा है। वनों की कटाई, भूमि के उपयोग में बदलाव, वन प्रबंधन और मानवीय गतिविधियों के चलते हर साल दुनिया में 15 अरब पेड़ कम हो रहे हैं। जिस तरह से भारत समेत पूरी दुनिया में अनियंत्रित औद्योगीकरण, शहरीकरण और बड़े बांध एवं चार और छह पंक्तियों के राजमार्गों की संरचनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, उससे भी जंगल खत्म हो रहे हैं। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने के लिए भी सैकड़ों पेड़ काटे गए थे। ऐसे समय जब दुनिया भर के पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक जलवायु संकट के दिनोंदिन और गहराते जाने की चेतावनी दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा मददगार वनों का सिमटना या पेड़ों का घटना वैश्विक होती दुनिया के लिए चिंता का विषय है। विकास के नाम पर जंगलों के सफाए में तेजी भूमंडलीय आर्थिक उदारवाद के बाद आई है। पिछले 15 साल में ब्राजील में 17 हजार, म्यांमार में 8, इंडोनेशिया में 12, मेक्सिको में 7, कोलंबिया में 6.5 और भारत में 4 हजार प्रति वर्ग किमी. के हिसाब से वनों का विनाश हो रहा है। यानी एक साल में 170 लाख हेक्टेयर की गति से वन लुप्त हो रहे हैं। वनों के विनाश की यही रफ्तार रही तो जंगलों को 4 से 8 प्रतिशत क्षेत्र 2030 तक विलुप्त हो जाएंगे। 2040 तक 17 से 35 प्रतिशत सघन वन मिट जाएंगे। इस समय तक इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि 20 से 75 की संख्या में दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियां प्रति दिन नष्ट होने लग जाएंगी। नतीजतन, आगामी 15 सालों में 15 फीसद वृक्षों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इनकी विलुप्ति का असर फसलों पर भी पड़ेगा।

वृक्षों का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि वृक्ष जीव जगत के लिए जीवन-तत्वों का सृजन करते हैं। वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, भू-क्षरण न हों, ऐसा पेड़ों की अधिकता से ही संभव है। वर्षा चक्र की नियमित निरंतरता पेड़ों पर ही निर्भर है। पेड़ मनुष्य जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, इसका वैज्ञानिक आकलन भारतीय अनुसंधान परिषद ने किया है। इस आकलन के अनुसार, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पर्यावरण के लिहाज से एक हेक्टेयर क्षेत्र वन से 1.41 लाख रुपये का लाभ होता है। इसके साथ ही 50 साल में एक वृक्ष 15.70 लाख की लागत का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देता है। पेड़ लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की भूमि की नमी बनाए रखता है। 2.5 लाख रुपये मूल्य की ऑक्सीजन, 2 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रोटीनों का संरक्षण करता है। वृक्ष की अन्य उपयोगिता में 5 लाख रुपये मूल्य के समतुल्य वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण और 2.5 लाख रुपये मूल्य के बराबर की भागीदारी पक्षियों, जीव-जंतुओं और कीट-पतंगों को आश्रय-स्थल उपलब्ध कराने के रूप में करता है। वृक्षों की इन्हीं मूल्यवान उपयोगिताओं को ध्यान में रख कर हमारे ऋषि-मुनियों ने इन्हें देव तुल्य माना और इनके महत्त्व को पूजा से जोड़ कर संरक्षण के अनूठे और दीर्घकालिक उपाय किए। इसलिए भारतीय जनजीवन का प्रकृति से गहरा आत्मीय संबंध है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> पेड़ों की अस्मिता पर ही मनुष्य और अन्य प्राणियों का जीवन टिका है। गोया, पेड़ ऐसी प्राकृतिक संपदा है, जिसका विनाश होता है, तो मनुष्य का सुखद जीवन भी संभव नहीं है। जब से मानव सभ्यता के विकास का क्रम शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक वृक्षों की संख्या में 46 फीसद की कमी आई है। पेड़ों की गिनती के अब तक के सबसे समग्र वैश्विक अभियान में वैज्ञानिक समूहों ने यह निष्कर्ष निकाला है। आकलन है कि विश्व में तीन लाख करोड़ वृक्ष हैं

भारत में पुनर्चक्रण
कारोबारी नहीं जीवन मॉडल

- 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' उत्पादन और उपभोग का ऐसा मॉडल है, जिसमें यथासंभव विद्यमान सामग्रियों एवं उत्पादों को साझा करना, पट्टे पर देना, दोबारा इस्तेमाल, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण शामिल हैं
- भारत में अभी 3,500 से अधिक पुनर्चक्रण इकाइयां हैं, जो सालाना 4.5 करोड़ टन से ज्यादा कचरा संसाधित करने में सक्षम हैं
- भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को व्यवसाय मॉडल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यहां पुनर्चक्रण कारोबारी मॉडल न होकर जीवन मॉडल है

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स गुजरात के भाजपा नेता हरेन पांड्या की निकट संबंधी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी? सुनीता के पिता दीपक पांड्या हरेन पांड्या के चाचा थे। वे मेहसाणा जिला, जहां से पीएम मोदी भी आते हैं, के मूल निवासी हैं। हमारे गुजराती दोस्त/बहन/भाई चारों तरफ हैं!

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

समाधान ही तो नहीं सूझ रहा

जल संकट **रजनीश कपूर**

भारत में प्राचीन काल से नदियों को पूजा जाता रहा है। जल को अमृत माना गया है। यह भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है परंतु आज देश भर में गंभीर जल संकट की स्थिति है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने देश के जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 60 करोड़ से अधिक लोग पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि जल संकट की जड़ें कहां हैं, और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

भारत में जल संकट कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह और गहरा गया है। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य, जो कृषि के लिए जाने जाते हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गर्मियों के दौरान पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। नदियां, जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थीं, अब प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार हो रही हैं। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। सरकारें आती-जाती रहीं पर नदियों की किसी ने नहीं सोची। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ाया है। अब अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ की घटनाएं आम हो गई हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 में 5,177 क्यूबिक मीटर थी, जो घट कर 1,545 क्यूबिक मीटर रह गई है। यह आंकड़ा देश को 'जल तनाव' की श्रेणी में खड़ा कर देता है। यही स्थिति रही तो आने वाले दशकों में भारत 'जल संकटग्रस्त' देश बन सकता है। जल संकट के पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है जल का अंधाधुंध दोहन। खेती के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग खासकर ट्यूबवेल और बोरवेल के जरिए करने से भूजल का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। दूसरा कारण है जल संसाधनों का प्रदूषण। औद्योगिक कचरा, सीवेज और रासायनिक खाद नदियों और झीलों को जहरीला बना रहे हैं। बढ़ता शहरीकरण भी संकट को बढ़ा रहा है। कंक्रीट के जंगल बनने से वर्षा का जल जमीन में नहीं रिस पाता जिससे भूजल पुनर्भरण प्रभावित होता है। जल प्रबंधन

में कमी और नीतियों का ठीक से लागू न होना भी एक बड़ी समस्या है। लोग पानी को मुफ्त संसाधन समझ कर उसकी बर्बादी करते हैं। सिंचाई के लिए पुरानी और अकुशल तकनीकों का इस्तेमाल अभी भी जारी है।

जल संकट का असर हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। कृषि, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पानी की कमी से प्रभावित हो रही है। किसानों को फसल नुकसान और कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में पानी की किल्लत से लोग टैंकर माफिया पर निर्भर हो गए हैं। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि प्रदूषित पानी से बीमारियां फैल रही हैं। सामाजिक स्तर पर जल संकट तनाव और संघर्ष को जन्म दे रहा है। नदियों के पानी को लेकर राज्यों के बीच कावेरी और यमुना जल बंटवारे का विवाद इसका बड़ा उदाहरण है। समय रहते समस्या का समाधान न हुआ तो देश की शांति और विकास के लिए भी खतरा बन सकता है।

जल संकट से निपटने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले तो जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा जल संचयन को हर घर, स्कूल और ऑफिस में अनिवार्य करना चाहिए। सरकार ने 'जल शक्ति अभियान' शुरू अवश्य किया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। जरूरी है पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित कर उनका जीर्णोद्धार। पौराणिक कुंडों को साफ-सुथरा कर वर्षा जल संचय का बड़ा स्रोत बनाया जा सकता है, जिससे भूजल का स्तर भी सुधरेगा।

कृषि में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। कम पानी खपत वाली फसल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उद्योगों को अपशिष्ट जल को शोधन करके दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से बचाने के लिए सख्त कानून और उनकी निगरानी जरूरी है। शहरी नियोजन में हरे-भरे क्षेत्रों और जल निकायों को संरक्षित करना होगा। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण शामिल किया जा सकता है। नदियों को जोड़ने की परियोजना, यदि ठीक से लागू हो तो, पानी के असमान वितरण को कम कर सकती है। भूजल के उपयोग पर नियंत्रण के लिए भी कानून जरूरी है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे निष्ठा से निभाए। हर नागरिक को पानी की एक-एक बूंद बचाने का संकल्प लेना होगा। जल संकट भारत जैसे हर देश के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असाध्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है, और समय आ गया है कि हम इसे सिर्फ पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि इसके संरक्षण को जीवन का भी हिस्सा बनाएं।

परेशानियां **श्रीराम शर्मा आचार्य**

मनुष्य अपनी परेशानियों से छूटने का उपाय निरंतर करता रहता है। वस्तुतः उसका सारा उपक्रम, उद्योग, परिश्रम और पुरुषार्थ है ही केवल परेशानियां कम करने और कष्टों से छूटने के लिए। किन्तु उसके कष्टों में कमी के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। मनुष्य अंधकार में हाथ-पांव मारता हुआ सुख की दिशा की बजाय भ्रम की वीथियों में भटकता फिर रहा है। सुख के प्रयास में दुःख ही पाता चला जा रहा है। निस्संदेह मनुष्य की यह दुर्दशा दया की ही पात्र है। और वह भी तब जब संसार में अशक्य अथवा असाध्य जैसा कुछ भी नहीं है। बस, मनुष्य को इतना भर ध्यान में रखना है कि प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ निष्ठा, उपयुक्त दृष्टिकोण, मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास संजोए रखना है ताकि वह अपने प्रयासों को सही दिशा दे सके। उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तृष्णा भयानक अजगर के समान है। जब यह किसी मनुष्य में अनियंत्रित हो जाती है, तो संपूर्ण संसार को निगल जाने की इच्छा किया करती है। अपनी इस अनुचित इच्छा से प्रेरित होकर जब वह अग्रसर होता है, तब भयानक संघर्ष, विरोध एवं बैर में फंस कर चोट खाता है, तड़पता है। स्वार्थ से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि मानसिक विकृतियों का जन्म होता है, जो स्वयं ही किसी अन्य साधन के बिना मनुष्य को जला कर भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त होती हैं। दृष्टिकोण की अव्यापकता भयानक बंदीग्रह है, जिसमें बंदी बना मनुष्य एकाकीपन और सूनेपन से घिर कर तड़पता-कलपता रहता है। संकीर्ण दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपनी मान्यताओं, विश्वासों अथवा भावनाओं से भिन्न किसी भावना, विश्वास अथवा मान्यता को सहन नहीं कर पाता। किसी दूसरी सभ्यता अथवा संस्कृति को फूटी आंख भी फलते-फूलते नहीं देख सकता। जो उससे संबंधित है, वही सत्य है, शिव है और सुंदर, अन्य सब कुछ अमंगल एवं अशुभ है। इस विविधताओं, विभिन्नताओं एवं अन्यताओं से भरे संसार में भला इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह सकता है? उससे भिन्न मान्यताएं उठेंगी, विविधताएं व्यग्र करेंगी और भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य बड़ा दिल रखते हुए सर्वहित का हेतु बनने का दृष्टिकोण अपनाए।

रीडर्स मेल

अतीतजीवी बनने का कोई लाभ नहीं

दैनिक जीवन में हम कभी-कभार ऐसा जरूर सोचते होंगे कि उस वक्त ऐसा होता तो हम आज ऐसा कर सकते थे। यह चिंतन प्रत्येक मनुष्य के भीतर निरंतर चलता है परंतु यह चिंतन जब अधिक चलने लगे तो हमें एकदम से सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि यह हकीकत है कि हम अपने अतीत को परिवर्तित नहीं कर सकते। अलबत्ता, अतीत से सीख लेकर भविष्य को और बेहतर बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। इसलिए अतीत की चर्चा लंबे समय तक करना ठीक नहीं कहा गया है क्योंकि इससे वर्तमान नष्ट होता है। हाथ से निकल चुके समय और अवसरों पर व्यर्थ चिंता करने की बजाय उन पर चिंतन करें और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। बहुत से लोग अपने खोए हुए अवसर और विभिन्न परिस्थितियों के कारण की गई गलतियों और जानबूझकर की गई गलतियों के कारण अपने मन में पैदा निराशा के भाव से ताउम्र परेशान रहते हैं परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी समस्याओं का उपाय एक ही है। और वह उपाय है कि आप समस्याओं की जड़ में जाएं, उनको देखें-समझें और उनसे सीखें। और फिर एक नया रास्ता बनाएं, सफलता का नया अध्याय लिखें।

देवानंद राय, ई मेल से

गौरवान्वित किया सुनीता ने

भारत की मातृभूमि पर समय-समय पर ऐसी बेटियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत की आन-बान-शान को चार चांद लगाए हैं। तिरंगे को पहचान बना कर उन्होंने नया इतिहास रच दिया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 286 दिन बिताने के बाद भारत की बेटी सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। सुनीता स्पेस ड्रिंक कैप्सूल में सवार होकर लौटीं। उन्होंने अंतरिक्ष में बताएं तो 4576 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उन्होंने 12.1 करोड़ से अधिक मील की यात्रा 17 घंटे में पूरी की। स्पेस स्टेशन से धरती पर इतनी सहजता से पहुंचना इतना आसान नहीं था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने धैर्य और साहस का अभूतपूर्व परिचय दिया। इन मानवीय भावनाओं को अपने साहस का संबल बनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने का काम किया है।

मीना धानिया, दिल्ली

कुत्तों को बांध कर न रखें

कुत्ता छुट्टा जानवर है। यह इंसानों के बीच रह कर अपशिष्ट पदार्थ खाकर पर्यावरण को साफ करता है। इसके अलावा भी लोग धार्मिक दृष्टि से कुत्ते को खाना डालते हैं। कुत्ता रोड पर घूमने वाला जीव है। उसे घर में बांध कर रखना अनुचित है। वह भी अपने स्वभाव के अनुसार छुट्टा रहना पसंद करता है। उसे बांध कर रखने के अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं। एक तरह से बागी जैसा व्यवहार वह करने लगता है। इसकी पुष्टि कानपुर की एक खबर करती है। कानपुर में एक संभ्रांत घर में पले कुत्ते ने अपनी मालकिन को नोच कर मार डाला। संभ्रांत घरों के साथ अनेक लोग घर में कुत्ता बांध कर रखते हैं। वे कुत्ता क्यों पालते हैं, वही जानें। लेकिन कुत्ता पाल कर वे अनचाहे खतरों को बुलावा जरूर देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के काटने की खबरें भी पेपर में आती रहती हैं। लोग बेवजह इनके हमले के शिकार होते हैं। ऐसे में नगर पालिकाएं कुत्तों की नसबंदी कर लोगों को राहत देती हैं। बहरहाल, कुत्तों को बांध कर रखने वाले संभल जाएं।

सीमा गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 213

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा कक्ष 1209-1210, बाराखंबा लेन, ज्वलंत हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

58 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई थी वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में, जबकि अब इसमें केवल दो ही सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था।

हिंदू-मुसलमानों के वास्तविक संबंध संपूर्ण देश में स्पष्ट होने लगे थे। मोपला-विद्रोह से सबक लेकर जिन स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू-संगठन का मंत्र जन-जन में फूंका, उनकी 23 दिसंबर, 1926 को निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदू होकर भी 'हिंदी' कहलानेवाले नेता स्तब्ध रह गए। पर मुसलमानों ने हत्यारे अब्दुल रशीद को 'गाजी' कहना शुरू कर दिया। पिछले तीन-चार वर्षों की घटनाओं से नागपुर का वातावरण भी दूषित हो गया था। वर्ष 1924 से नागपुर में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने के कारण उनका पारा और भी चढ़ गया था। सतरंजीपुरा, हंसापुरी तथा जुम्मा मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की निकलनेवाली शोभायात्राएं उनके मन को रह-रहकर कचोटती थीं। अतः उन्होंने हिंदुओं को नाना प्रकार से सताने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अकेला-दुकेला हिंदू मिल गया तो उसे पकड़कर पीटते थे तथा हिंदू मोहल्लों में से लड़कियों को भगाकर ले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती गईं। किंतु अब ये ज्यादतियां पचाई नहीं जा सकती थीं। डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, गोविंदराव चोलकर, रामचंद्र कोष्टी, भाऊजी कावरे, अण्णा सोहोनी, बालाजी सुखदेव तथा कृष्णाजी जोशी आदि सप्तऋषि जब पट्टेदार खादी की ऊंची काली टोपी, सफेद कमीज, खाकी कोट, कांछा लगाए हुए धोती, और हाथ में सोटा लेकर घूमते तो गुंडों का दिल कांपने लगता। एकाध बार तो उनके जाने मात्र से भालदारपुरा के मुसलमानों ने भगाई हुई एक हिंदू लड़की को वापस कर दिया।

संघ की शाखाओं का विस्तार : डाक्टरजी केवल कल और आज का विचार न करते हुए समाज के शाश्वत स्थैर्य के लिए भविष्य में दूर तक देखते थे तथा उसके लिए तरुणों के साथ बाल और शिशुओं को भी संस्कारित करने की उन्होंने तैयारी की थी। मोहिते बाड़े में लगनेवाली संघ शाखा का 1927 के प्रारंभ में स्वरूप विस्तृत होने लगा। अब उसमें आयु के अनुसार शिशु, बाल, तरुण तथा प्रौढ़ स्वयंसेवकों के अलग-अलग पथक बनाकर उन्हें लव, चिलया, कुश, ध्रुव, प्रह्लाद, अभिमन्यु, भीम तथा भीष्म नाम दिए गए। 'भीष्म' पथक में संघ से संबंधित प्रौढ़, 'भीम' में बड़े तरुण, 'कुश' तथा 'प्रह्लाद' में तरुण, किशोर तथा बाल और 'लव' एवं 'चिलया' पथक में दस वर्ष से नीचे के शिशुओं का वर्गीकरण किया गया था। सत्तर-अस्सी तरुणों के लाठी के कार्यक्रम से वातावरण इतना उत्साहपूर्ण दिखाई देता था कि उससे वीरभाव का संचार हुए बिना नहीं रहता। नागपुर में वातावरण गरम होते हुए भी डाक्टरजी ने कुछ तरुणों का गर्मियों में ही एक प्रशिक्षण-वर्ग लगाया। वे उन्हें इस योग्य बना देना चाहते थे कि कहीं भी संघ का कार्य कर सकें।

आजकल

पुराने घाव फिर से हरे करता नागपुर

नागपुर इन दिनों सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। दावा किया जाता है कि नागपुर में ऐसा सांप्रदायिक तनाव 98 वर्षों के बाद पैदा हुआ है। इससे पहले 1927 में नागपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आयु दो वर्ष भी नहीं हुई थी। लेकिन उस समय संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा एकत्र की गई खुफिया सूचनाओं एवं अन्य तैयारियों के कारण समाज कैसे दंगाइयों का मुकाबला कर सका, आज इस तथ्य को भी समझना हमारे लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है

दंगों की आग में एक बार फिर झुलसा नागपुर। फाइल

डा. केशव बलिराम हेडगेवार।

वर्ग के दिनों में ही डाक्टरजी के घर पर पथराव का प्रमाण अधिक बढ़ गया तथा बीच-बीच में डाक्टरजी एवं कई अन्य हिंदू नेताओं के पास गुमनाम पत्र आने लगे जिनमें धमकी दी गई कि 'सावधान रहिए, हम लोग आपका खून करने वाले हैं।' डाक्टरजी को मिले धमकी भरे पत्रों में से एक पत्र 15 मई के 'महाराष्ट्र' में अब्दुल करीम के हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है। उसकी भाषा से पता चलता है कि वह किसी सिरफिरे गुंडे की करतूत थी। उसमें लिखा था, 'आप नागपुर के मुसलमानों का बड़ा दोस्त हो ('दोस्त' शब्द व्यंग्यात्मक था)। आपने रामटेक में मुसलमानों से शरारत की है। वह शरारत आपको मौत नजदीक लाने का तरीका है। अपना ध्यान रखना, एक बरस के अंदर तुम मुरगी सरीखे काटे जावेंगे और तुम्हारी हड्डी मुसलमान बांट के चूसेंगे।'

डाक्टरजी को स्पष्ट दिखने लगा था कि अब संघर्ष होकर रहेगा। अतः उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों में आक्रमण की तैयारी करने के लिए चलनेवाली गुप्त बैठकों की टोह लेने की व्यवस्था की थी। जून-जुलाई से ही हिंदू बस्तियों में मुसलमानों की टोलियां कुछ देखभाल करती हुई घूमती नजर आती थीं तथा मस्जिद में बार-बार होनेवाली बैठकों के समाचार भी आगे आनेवाले संकट की सूचना दे रहे थे। दुर्योग से उस समय महाराष्ट्र में सर्वत्र ब्राह्मण-अब्राह्मण के बीच बड़ी कटुता निर्मित हो गई थी। इससे मुसलमानों को आशा थी कि इस कटुता का लाभ लेकर हिंदू-संगठन की तैयारी करनेवाले तथा मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करनेवाले सफेदपोश लोगों को अच्छा सबक सिखाया जा सकेगा। किंतु समय रहते उनके षड्यंत्र का सुराग संघ को मिल चुका था। संघ के प्रारंभ में तथा 1927 के संघर्ष के पूर्व डाक्टरजी ने बैठकों तथा सभाओं में अनेक बार बताया था कि 'मैं अकेला हूं' की भावना कितनी आत्मघाती तथा हास्यास्पद है।

डाक्टरजी जहां एक ओर अपने समाज को जाग्रत एवं सुसज्जित करने का प्रयत्न कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के द्वारा अपने मोहल्लों में आक्रमण का व्यूह किस प्रकार रचा जा रहा है, इसकी भी खोज-खबर रखते थे। इसी कारण गणेशोत्सव में महालक्ष्मी तथा गौरी के प्रसाद के दिन महाल क्षेत्र में दंगा करने की मुसलमानों की योजना का उन्हें पहले ही पता लग गया था। अतः झगड़े के संभाव्य क्षेत्र में स्थान-स्थान पर उन्होंने लाठियां इकट्ठी करके रखवा दीं। साथ ही असुरक्षित दिखनेवाले क्षेत्रों में डाक्टरजी ने स्वयं जाकर लोगों को सचेत रहने की सूचना दी। चार सितंबर को निकलनेवाले एक जुलूस के हस्तपत्रक बांटे गए। इसमें मुसलमानों को आह्वान किया गया था कि उपरोक्त तारीख को नवाबपुरा मस्जिद में इकट्ठा हों।

महालक्ष्मी उत्सव : इस 'पुण्यप्रद' यात्रा के लिए महालक्ष्मी उत्सव के दिन दोपहर दो बजे का समय निश्चित करने के पीछे मुसलमानों की चाल थी। नागपुर-बरार भाग में महालक्ष्मी का उत्सव बड़े वैभव तथा साज-बाज के साथ मनाया जाता है। लोग दोनों देवी-प्रतिमाओं का रेशमी तथा जरी के कीमती वस्त्रों से शृंगार करते हैं तथा घर के हीरे, मोती, सोने आदि के मूल्यवान गहनों से उन्हें अलंकृत कर घर-घर पूजा की जाती है। नैवेद्य के लिए इतने प्रकार की चीजें पकाई जाती हैं कि 'चौंसठ व्यंजन छत्तीस भोग' की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। दोपहर दो बजे से सायंकाल तक देवी पधारती हैं। मुसलमानों के नेताओं ने यह योजना बनाई थी कि दोपहर को भोजन की दौड़धूप में यदि हिंदू मोहल्लों पर हमला बोल दिया तो सभी भोजन-भट्टों में भगदड़ मच जाएगी तथा उस स्थिति का लाभ उठाते हुए महालक्ष्मी को तोड़-फोड़कर उसके अलंकार लूटने का स्वर्ण-अवसर हाथ लग जाएगा। इसी योजना के साथ दिन के बारह बजे नवाबपुरा की मस्जिद के पास मुसलमानों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था।

उस दिन डाक्टर हेडगेवार नागपुर में नहीं थे। वह प्रतिवर्ष की भांति गणेशोत्सव में भाषण देने के लिए चांदा, वर्धा आदि स्थानों के दौरे पर गए थे। किंतु जाने से पहले वह झगड़ा हुआ तो क्या करना है, इस संबंध में सभी निर्देश देकर गए थे। उन्होंने मुसलमानों की तैयारी का तो पता लग लिया था, किंतु हिंदुओं की सजगता का पता नहीं चलने दिया था। डाक्टरजी की सूचना के अनुसार अण्णा सोहोनी के नेतृत्व में स्वयंसेवक मोहिते बाड़े की टूटी दीवार की आड़ में 12 बजे दोपहर से ही इकट्ठा होने लगे। अण्णाजी ने उनको ठीक प्रकार से बांट दिया तथा डा. मुंजे के घर से महाल तक सभी गली-कूचों में उन्हें सावधानी के साथ छिपकर बैठने की सूचना दी। कुल 16 टुकड़ियां बनाई गई थीं। सब मिलाकर सौ-सवा सौ तरुण होंगे। जैसा कि निश्चित हुआ था रविवार, दिनांक चार सितंबर को दोपहर के दो बजे मुसलमानों का जुलूस निकला। 'अल्ला हो अकबर' तथा 'दीन दीन' के नारे जोर-जोर से लगाए जा रहे थे। अंग्रेजों के राज्य में एक प्रांत की राजधानी में इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुसलमान लाठी, तलवार, भाला, छुरिका आदि शस्त्रास्त्र से सज्ज अत्यंत उन्मत्त बर्ताव करते हुए जा रहे थे।

डटकर किया मुकाबला : वह अत्यंत डरावना दृश्य था। वाईकर गली, केलीबाग, सिटी हाई स्कूल का प्रवेशद्वार, डा. हरदास का अस्पताल आदि सभी क्षेत्रों में घरों में बैठे हुए हिंदू 'दीन-दीन' के गगनभेदी स्वर को सुनकर डर के मारे कांप रहे थे। जैसे-जैसे जुलूस निकट आता जाता था वैसे-वैसे लगता था कि मानो अब हृदय की धड़कन भी बंद हो जाएगी। परंतु दूसरी ओर इन्हीं गलियों में छिपे स्वयंसेवक भी निर्भयता से जुलूस की बाट देख रहे थे। आत्म संरक्षण का उनका निश्चय दृढ़ था। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ पर उन्हें भरोसा था। थोड़ी ही देर में सड़क से जानेवाला जुलूस वाईकर की गली में गाली-गलौच तथा मारपीट करता हुआ घुसा। उसी समय गली में एक ओर चुपके से खड़े हुए स्वयंसेवकों ने उस संकरी गली में घुसे हुए गुंडों के ऊपर अपने प्रहार के हाथ दिखाने शुरू कर दिए। बस, मुसलमान आततायी लहुलुहान होकर उलटे पांव भागने लगे। 'दीन-दीन' करते तथा अपने होश-हवास खोकर कुछ गुंडों ने जुलूस को छोड़कर महाल-भाग की दूसरी गलियों में घुसने का प्रयत्न किया। लेकिन वहां भी वही रक्ताभिषेक होते ही जुलूस बिल्कुल तितर-बितर हो गया तथा मुसलमान अकेले-दुकेले हिंदू को मारते-पीटते चिटणीस पार्क की तरफ भागने लगे। उस समय उनकी बौखलाहट तथा गाली-गलौच से यह साफ दिखता था कि पहली ही झड़प में उनकी अपेक्षा भंग हो गई थी।

इतना बड़ा जुलूस थोड़े से तरुणों ने ही छिन्न-विच्छिन्न कर दिया, यह वार्ता बिजली की तरह सारे क्षेत्र में घर-घर में फैल गई। सुनते ही बाकी लोग भी भोजन-मिष्ठान छोड़कर रेशमी धोती बांधे ही लाठियां लेकर निकल आए तथा जुलूस पर टूट पड़े। अंत में अंधेरे का आश्रय लेकर अपने काले मुंह छिपाने के लिए भालदारपुरा की ओर भागने के सिवाय मुसलमानों के सम्मुख और कोई चारा नहीं बचा। रविवार रात्रि को सारे शहर में झड़पें होती रहीं। किंतु उनमें हिंदुओं का ही पलड़ा भारी था। रात-भर लोगों ने पहरा लगाया। इसके बाद तीन दिन मारधाड़ में ही बीते। लेकिन इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि डा. हेडगेवार ने समय रहते नागपुर के हिंदुओं को एकजुट एवं प्रशिक्षित न किया होता, तो चार सितंबर, 1927 को हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत विकट होती।

(नाना पालकर द्वारा डा. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक 'डा. हेडगेवार' के एक अध्याय 'नागपुर का दंगा' का संपादित अंश)

(संकलन एवं प्रस्तुति : ओमप्रकाश तिवारी)

खरी-खरी

एक नंबर के ईमानदार आदमी

सूरज सखा

वे एक नंबर के ईमानदार आदमी थे। किसी का कार्य किए बिना कुछ नहीं लेते थे। लेकिन काम करवाने के बाद वे अपना हक छोड़ते नहीं थे। इसलिए उनके क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से उन्हें एक नंबर का ईमानदार माना जाता था। नाम उनका मुक्तिदास और उम्र यही कोई पचास के आसपास। नगर निगम में काम करते थे। पद से बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी ईमानदारी के आधार पर अच्छी-खासी धाक जमा रखी थी। ऊपर तक उनके हाथ थे। कानून को कभी हाथ में नहीं लेते, बल्कि कानून को वे भली प्रकार काम में लेते थे। वे अक्सर अपने 'क्लाइंट्स' को डराते रहते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी गलत काम करने वाला उससे बच नहीं सकता। ऐसी स्थिति से निजात पाने का रास्ता उनके पास है और जो उनके पास आता था तो कानून के हाथ छोटे हो जाते थे।

मेरा भी एक बार उनसे सामना पड़ा। मेरे मकान के पास से एक आम रास्ता था। मुझे आम आदमी और आम रास्ता पसंद नहीं है। मेरे पास से आम आदमी गुजरे, यह मुझे गवारा नहीं था। नगर निगम गया तो वहां सभी ने एकमत होकर कहा कि मुक्तिदास जी को पकड़ो। मैंने मालूम किया कि वे कहां मिलेंगे। पता चला कि वे कैंटीन में मिल जाएंगे। कैंटीन में पहुंचा तो वे गरमा-गरम समोसे खाते हुए किसी को नेक सलाह दे रहे थे। मुझे देखकर बोले- 'आओ भाई बैठो, समोसे खाओगे। वहीं दूसरी ओर साथ वाला व्यक्ति रुआंसा होकर बोला, 'अब कब तक मेरा काम पूरा होने की उम्मीद है।'

मुक्तिदास ने चाय को सुड़का और मटमैले दांत निकालकर बोले- 'भाई जल्दी हो तो तुम किसी और से मिल लो। अफसर को पकड़ लो। मेरी काम कराने की अपनी शैली है। हो जाएगा तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। साथ वाला स्वयं ही चुप हो गया। चुपचाप उठा, चाय-समोसे का भुगतान कर रवाना हो गया। उसकी सीट मैंने ली तो वे बोले, 'किसने सताया है तुम्हें?' मैं बोला, 'मुझे आम आदमी और आम रास्ते ने परेशान कर दिया है। यह कैसे भी बंद होना चाहिए।'

पोस्ट

क्या यह कोई संयोग है कि यूएसएड की सहायता बंद होने के कुछ ही दिन बाद कथित किसान आंदोलन बंद करा दिया गया। विक्रांत@vikrantkumar

पंजाब में किसानों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इस बार वैसा हाहाकार क्यों नहीं हुआ, जैसा पहले हुआ था? क्या हाहाकार यह देखकर होता है कि सरकार किसकी है? सिवा कांग्रेस पार्टी के, कोई अन्य पार्टी इस पर कुछ बोल ही नहीं रही। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाना गलत है। एएसआइ को उसकी कब्र के बाहर उसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों की लिस्ट का एक बड़ा सा बोर्ड लगा देना चाहिए। उसके द्वारा सतनामियों, सिखों, हिंदुओं के नरसंहारों की डिटेल्स के साथ भी एक बोर्ड लगा देना चाहिए। दिव्य कुमार सोती@DivyaSoti

रेवड़ी राजनीति के चलते महाराष्ट्र सरकार को कर्मियों को वेतन देने में मुश्किल आ रही है। राज्य के खस्ताहाल खजाने की चर्चा के बजाय वहां औरंगजेब पर बहस जारी है। वह एक खराब शासक था, पर उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। तवलीन सिंह@tavleen_singh

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए?

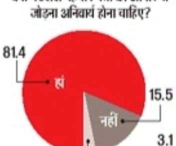

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पंजाब सरकार ने किसान संगठनों से रास्ते खाली करा कर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

योगी जी की राह पर चले महाशय मान,
बुलडोजर चलवा दिया साफ हुआ मैदान।
साफ हुआ मैदान कहीं भी दो अब धरना,
किंतु रोड के बीच न आकर बिल्कुल अड़ना।
कैसा भी हो रोग और कैसा भी रोगी,
सबका एक इलाज फार्मूला है बस योगी!
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

सुरक्षित सीटें घटीं तो किसे लाभ-हानि

झारखंड में लोकसभा और विधानसभा सीटों की प्रकृति के साथ-साथ संख्या में भी बदलाव की संभावना है। इसकी वजह अगले वर्ष से राज्य में लागू होने वाला परिसीमन है। सीटों के नए सिरे से निर्धारण में आबादी के विस्तार की ज्यादा भूमिका होगी। जब सीटें निर्धारित की गई थी, तब उस हिसाब से उसकी संख्या तय की गई थी, लेकिन तेजी से आबादी बढ़ने के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं और नए रिहायशी इलाकों का भी विस्तार हुआ है। प्रस्तावित परिसीमन को देखते हुए आरोप-प्रत्यारोप से लेकर नफा-नुकसान को लेकर राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका है कि आबादी कम होने को आधार बनाकर राज्य में लोकसभा और विधानसभा की आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या घटाई जा सकती है।

हालांकि अभी यह केवल अनुमान है, लेकिन यह मसला राजनीति के केंद्र में आ गया है। अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने यह आशंका जताई है कि आदिवासी सुरक्षित सीटें घटाई जा सकती हैं और ऐसा राज्य हित में नहीं होगा। जवाब में विपक्षी दल भाजपा ने आदिवासियों की कम होती आबादी को बदली जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और घुसपैठ के आरोपों से जोड़ा, लेकिन फिलहाल सीटें घटने की आशंका प्रकट कर सत्तारूढ़ गठबंधन ने इससे पैदा होने वाली सहानुभूति को अपने पक्ष में करने की पहल की है।

राज्य में क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उभार और उसके नेतृत्व में चल रहे आइएनडीआइए गठबंधन की बढ़त ने भाजपा को पीछे धकेल रखा है। खासकर आदिवासी सुरक्षित सीटों पर गठबंधन का ऐसा प्रभाव है कि मुश्किल से भाजपा का खाता खुल पा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो भाजपा को सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। परंपरागत सीटों पर दिग्गज आदिवासी नेताओं की एक नहीं चली। केंद्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का मंत्री रहने के बावजूद अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से पराजित हो गए तो भाजपा के भितरखाने इसे लेकर खलबली है कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए। विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी सुरक्षित सीटों पर भाजपा की स्थिति कुछ ऐसी ही रही। 28 में से केवल एक आदिवासी सुरक्षित विधानसभा सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि पार्टी ने पूरे तामझाम के साथ चुनाव से पहले ऐसे कई नेताओं को दल में शामिल किया था, जिन पर जीत दिलाने का दारोमदार था। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इसमें प्रमुख थे। हालांकि चंपाई सिर्फ अपनी सीट ही निकाल पाए। अपने बेटे तक का राजनीतिक करियर आरंभ कराने में वे विफल रहे। वहीं, किसी आदिवासी सीट पर उनका प्रभाव नहीं दिखा।

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके पति की भी भाजपा में एंट्री हो गई, लेकिन कोड़ा अपनी परंपरागत सिंहभूम सीट बचाने में सफल नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा झटका सीता सोरेन के प्रदर्शन से भाजपा को लगा। सीता सोरेन ने उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, जब हेमंत सोरेन जेल में थे। बेहतर राजनीतिक भविष्य की आस में सोरेन परिवार को छोड़ वह न सिर्फ भाजपा में गईं, बल्कि कई संगीन आरोप भी लगाए। इससे लग रहा था कि भाजपा को लाभ होगा, लेकिन सीता सोरेन न तो लोकसभा चुनाव जीत पाईं न विधानसभा चुनाव। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह झामुमो में वापसी के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में परिसीमन के दौरान अगर आदिवासी सुरक्षित सीटें कम हुई तो सत्तारूढ़ गठबंधन इसे अपने प्रभाव को कम करने की दिशा में की गई राजनीतिक कार्रवाई बताकर सहानुभूति पाने की भरसक कोशिश करेगा। इसका अहसास भाजपा को है, तभी तो पार्टी इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रख रही है। आदिवासी आबादी घटने को लेकर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी संदेश दिया जा रहा है कि सुरक्षित सीटें यथावत रखी जाएं, अन्यथा इसका और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक मायने में भाजपा के आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। इसका दारोमदार अब प्रदेश नेतृत्व पर है कि वे किस हद तक अपनी बात रख पाते हैं। फिलहाल शानदार बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे हेमंत सोरेन के पास भाजपा को निशाना बनाने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो असरकारक हो सकते हैं। इस परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा के समक्ष होगी।

पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर बजाते हेमंत सोरेन। फाइल

मंथन

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

यमुना सफाई की व्यापक योजना

यमुना की बदहाली को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर योजनाएं बनें, उनका क्रियान्वयन हो एवं वे सतत चलें। साथ ही, समय समय पर उनकी समीक्षा भी की जाए

विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, अतिक्रमण और अविरल प्रवाह के अभाव में यमुना नदी बदहाल हो चुकी है। दिल्ली में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक यमुना का लगभग 22 किमी बहाव क्षेत्र है जो गंभीर रूप से प्रदूषित है। इस प्रदूषण में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी घरेलू सीवेज की है। दिल्ली में सीवेज को शोधित करने हेतु केवल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनमें से 16 ही मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्रतिदिन 71 करोड़ गैलन सीवेज उत्पन्न होता है जिसमें से 60 करोड़ गैलन का ही शोधन हो रहा है और शेष अशोधित सीवेज सीधे यमुना में गिर रहा है।

ध्यातव्य है कि वर्ष 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था। भारत और जापान की सहभागिता से बनी इस योजना का उद्देश्य था- सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, कच्चे सीवेज को नदी में छोड़ने के लिए निगरानी और यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय करना आदि। लेकिन यह विडंबना ही कही जा सकती है कि हजारों करोड़ रुपये का बजट लगने के बाद भी धरातल पर परिणाम लगभग शून्य है। विदित है कि सीवेज ढांचे को मजबूत करना, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना एवं साफ-सफाई आदि के लिए राज्य और स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं, फिर इसमें लापरवाही करने वाले निकायों अथवा राज्यों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाल ही में संसद की एक समिति ने जल परियोजनाओं में फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई है। समिति ने यह भी बताया कि दिल्ली के एक हिस्से में यमुना नदी की जीवन को बनाए रखने की क्षमता लगभग नगण्य पाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी में 33 निगरानी स्थलों में से 23 स्थल प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते।

हाल ही में एक समाचार से यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में 58 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई, जहां अब केवल दो ही सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य यमुना का पानी लाभार्थी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान के बीच बंटवारे के नियमन की जिम्मेदारी, न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एवं सतही व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी है।

प्रश्न यह है कि क्या इस रिवर बोर्ड का काम समाप्त हो गया अथवा बिना पर्याप्त सदस्यों के यह बोर्ड कैसे काम कर रहा है? वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक आदेश में यह कहा कि हरियाणा राज्य हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्यधारा में सीधे 10 क्यूसेक पानी छोड़े और वजीराबाद तक नदी का प्रवाह बनाए रखे। लेकिन विडंबना है कि विगत लंबे समय से वजीराबाद से आगे यमुना में उसके हिस्से का प्राकृतिक जल आ ही नहीं रहा है।

नियमों की अनदेखी : हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नालों से प्रदूषण की हिस्सेदारी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह सामने आया है कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (59.9 प्रतिशत बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड) नजफगढ़ नाले की है। इसके बाद सबसे ज्यादा 27.48 प्रतिशत प्रदूषण शाहदरा ड्रेन से जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब पर्यावरण विभाग आगे की कार्ययोजना पर काम कर रहा है।

दिल्ली अथवा किसी भी महानगर में नाले बरसाती पानी की निकासी के लिए होते हैं। आबादी का सीवेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर और औद्योगिक क्षेत्र का अपशिष्ट कामन एफ्लुएंट प्लान से पूरी तरह शोधित होकर ही किसी नदी में जाना चाहिए। किंतु यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजधानी में शासन-प्रशासन की मिलीभगत और नियमों की अनदेखी से छोटे-बड़े सभी नालों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट बह रहा है।

दिल्ली में कालिंदी कुंज के निकट यमुना नदी की स्थिति, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। फाइल

यमुना सफाई के लिए जरूरी है कि हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में समुचित समन्वय हो। औद्योगिक क्षेत्र से भी समन्वय एवं निगरानी के प्रयास किए जाएं। नगरीय एवं अनधिकृत आबादी क्षेत्र में पर्याप्त सीवेज संशोधन प्लांट लगाए जाएं और उनकी निगरानी हो। वे बड़े नाले जो सीधे यमुना में गिरते हैं, उन पर जगह-जगह प्री फिल्टर व राक फिल्टर जैसी तकनीक से प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास किए जाएं। स्थानीय जल स्रोतों को वर्षा एवं बाढ़ के समय भरने के लिए यमुना बहाव क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र व्यवस्था बनाई जाए। नालों के पानी को जलाशयों में रोकते हुए नदी की ओर जाने दिया जाए। यमुना की सफाई में जन भागीदारी एवं जागरूकता हेतु समय-समय पर सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यमुना के लिए व्यापक एवं सतत कार्य योजना तत्काल लागू करनी होगी। यमुना केवल एक नदी नहीं है, यह जीवनदायिनी है। इससे प्रकृति-पर्यावरण, संस्कृति, कृषि एवं आर्थिकी भी जुड़ी है। अतः इसके पुनरुद्धार हेतु विकल्पहीन प्रतिबद्धता आवश्यक है।

****

कल्पमेधा

अपूर्ण, अनिश्चित या भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे से परिवर्तित करना है।

- ह्वेटले

हिंसा का दायरा

मणिपुर पहले ही जातीय टकराव और हिंसा के दौर में झुलस रहा है और अब तक वहां शांति के लिए की गई तमाम कवायदों का कोई ठोस हासिल सामने नहीं आया है। करीब पौने दो वर्ष पहले वहां शुरू हुई हिंसा और उसके बाद अराजकता का माहौल आज भी कमोबेश जारी है और उसके हल का रास्ता सरकार नहीं निकाल सकी है। मणिपुर में लगातार जारी अशांति के मुख्य कारणों को संबोधित करके जहां उसका कोई समाधान निकालने के लिए सभी स्तरों पर हर संभव उपाय किए जाने चाहिए थे, वहां हालत यह है कि अब राज्य में टकराव के नए कारक पैदा हो रहे हैं, नए क्षेत्रों में हिंसा का विस्तार हो रहा है और उससे हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका खड़ी हो रही है। सवाल है कि केंद्र से लेकर राज्य तक का समूचा सरकारी तंत्र वहां के ज्यादातर इलाकों में पसरी अराजकता की स्थिति को संभालने और शांति कायम करने के प्रयासों में किन वजहों से नाकाम साबित हुआ है। इसका कारण सिर्फ हालात की जटिलता है या समस्या का हल निकालने के प्रति दूरदर्शिता की कमी और उदासीनता? आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो के अलावा दूसरी जनजातियां भी अलग मुद्दों पर आमने-सामने खड़ी हो रही हैं?

गौरतलब है कि राज्य के अशांत चूड़ाचांदपुर जिले में कुछ दिन पहले हमार समुदाय के एक नेता पर हमला होने के बाद जोमी समुदाय के साथ हमार समुदाय के लोगों की झड़पें शुरू हो गई थीं। हालांकि इसके बाद हमार और जोमी समुदायों के शीर्ष निकायों ने पहल की और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच शांति के लिए समझौता हुआ। मगर यह अफसोसनाक है कि उस समझौते पर कुछ देर अमल करना भी जरूरी नहीं समझा गया और दोनों समुदायों के बीच फिर हिंसा होने लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच जिले के उच्च अधिकारियों और खुद कुकी-जो समुदाय के विधायकों ने शांति के लिए अपील की। मगर इन सबका कोई असर नहीं पड़ा। सवाल है कि हिंसक टकराव में शामिल दोनों पक्षों के बरक्स सरकारी तंत्र को क्या इस बात की आशंका नहीं थी कि वहां जैसा माहौल अभी बना हुआ है, उसमें एक मामूली-सी चिंगारी भी फिर से हिंसा की आग को भड़का दे सकती है?

हिंसा और अराजकता को पूरी तरह रोकने और खत्म करने के प्रति सरकार की उदासीनता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक छोटे राज्य में हिंसा की शुरुआत के अब दो वर्ष होने जा रहे हैं और आज भी मुख्य समस्या के हल का कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से यह स्थिति टकराव और हिंसा में शामिल समुदायों के बीच असंतोष के कायम रहने का नतीजा है, लेकिन समस्या का हल निकालने से लेकर हिंसा पर काबू पाने के सभी अधिकार हाथ में होने के बावजूद सरकार और उसका समूचा तंत्र इस मसले पर किन वजहों से पूरी तरह नाकाम दिखता है? मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू है। मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अब अलग मुद्दों के साथ नए समुदायों के बीच जिस तरह का टकराव खड़ा हो रहा है, अगर समय रहते उसे थामने के लिए ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम नहीं किया गया तो इसके नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

तबाही की जंग

इजराइल और हमास के बीच दो महीने पुराना संघर्ष विराम जमीन पर कितना उतर सका, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके बावजूद इजराइल ने इस बार बिना किसी उकसावे के गाजा पर हवाई हमले किए। हालांकि उसका दावा है कि गाजा की ओर से मिसाइल दागी गई। इजराइल के सैन्य हमले में अब तक बयालीस हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बमबारी से बचने के लिए नागरिक भूखे-प्यासे मारे-मारे फिर रहे हैं। अफसोसनाक यह भी है कि उन तक मानवीय सहायता भी नहीं पहुंचने दी जा रही। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल किसी भी नियम और शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसने संघर्ष विराम के बावजूद कर गाजा पर भारी हवाई हमले किए, जिसमें पांच सौ बानबे लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? हमास के साथ उसका अस्थायी संघर्ष विराम इसलिए हुआ था, ताकि हमले में अपहृत बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। हमास ने कुछ बंधक छोड़े भी। यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं।

वर्चस्व के इस जंग के बीच आम फिलिस्तीनी दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। संघर्ष विराम टूटने के बाद गाजा क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर होने का अंदेशा है। इजराइल ने दोबारा हमले कर साफ कर दिया है कि शांति प्रयासों में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गाजा को तबाह कर देने पर आमादा है। यह अजीब बात है कि वह हमले के बीच युद्धविराम से जुड़ी वार्ताएं जारी रखने की बात कर रहा है। उसने बुधवार को दोबारा हमले किए, जिससे पचासी नागरिकों की मौत हो गई। ये हमले उस समय हुए, जब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। शांति और समस्या के हल की कोशिश के बजाय इजराइल ने इस बार उत्तरी गाजा पर शिकंजा कस दिया है। इससे फिलिस्तीनी नागरिकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। सवाल है कि उन आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन कब तक होता रहेगा, जो युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं!

चुनौती बनता ठोस कचरे का निपटान

ठोस कचरा तेजी से पसर रहा है। नतीजा यह कि दुनिया एक नई समस्या की ओर बढ़ चली है। भारत में सालाना छह करोड़ बीस लाख टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें प्लास्टिक और चिकित्सीय जैव कचरा शामिल है।

सुशील कुमार सिंह

बढ़ती जनसंख्या के साथ यह समस्या आम है कि उपयोग में लाई गई वस्तुओं को जब कचरे में बदलते हैं, तो फिर उनका क्या होता है? ठोस अपशिष्ट ऐसी ही चुनौतियों में शुमार है। इससे अनेक खतरे भी हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि से दुनिया जूझ ही रही थी कि अब ठोस अपशिष्ट भी नई-नई शक्लो-सूरत में मुंह चिढ़ा रहा है। भारत में हरित विकास की अवधारणा अभी जोर नहीं पकड़ पाई है, जबकि दूसरी ओर ठोस कचरा तेजी से पसर रहा है। नतीजा यह कि दुनिया एक नई समस्या की ओर बढ़ चली है। भारत में सालाना छह करोड़ बीस लाख टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें प्लास्टिक और चिकित्सीय जैव कचरा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन लगभग अस्सी लाख टन है और पंद्रह लाख टन ई-कचरा भी एक बड़ी समस्या है।

अब यह भी समझना होगा कि आखिर ठोस कचरा होता क्या है। घर, कारोबार, उद्योग, संस्थाओं और कृषि से निकलने वाले बेकार या अवांछित ठोस या अर्ध-ठोस पदार्थों को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट में कई तरह के पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, कार्डबोर्ड, खाद्य अपशिष्ट, उपकरण और निर्माण अपशिष्ट आदि। इसके अलावा, चिकित्सा जैव अपशिष्ट यानी अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट। इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट (ई-कचरा) मसलन, बैटरी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसी बेकार वस्तुएं। निर्माण स्थलों का मलबा, जिसमें ईंटें, सीमेंट और लकड़ी समेत रेडियोधर्मी अपशिष्ट जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो गैस, तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) की वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रपट 2024 के अनुसार, जैसे-जैसे देश अमीर होते जाते हैं, उद्योगीकरण और शहरीकरण की दर, आवास और खपत में वृद्धि होती है। उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला बाजार में उपलब्ध हो जाती है। और यही प्रति व्यक्ति उत्पन्न अपशिष्ट की औसत मात्रा में वृद्धि करने लगती है। रपट से यह पता चलता है कि हर साल दुनिया भर में दो अरब टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह अपशिष्ट 2030 तक ढाई अरब टन से अधिक तथा 2040 में सवा तीन अरब टन और 2050 तक पौने चार अरब टन हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, प्रति व्यक्ति ठोस कचरा उत्पादन में उत्तर अमेरिका अव्वल है, जबकि कुल ठोस अपशिष्ट के मामले में पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया पहले नंबर पर है। वैसे बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों में चीन को विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषक के रूप में पहचाना गया है। चीन ने पिछले पंद्रह वर्षों में ठोस कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है।

वर्ष 2022 में 175 देशों ने प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि

ठोस अपशिष्ट धरती को एक नए नुकसान की ओर धकेल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी अपनी जगह हैं। मसलन, ठोस कचरा हवा और पानी में हानिकारक रसायन छोड़ सकता है, जिससे मस्तिष्क क्षति और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठोस कचरे को अनुचित तरीके से संभालने से चोट लग सकती है। ठोस अपशिष्ट जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है, हवा को प्रदूषित कर सकता है और भूमि को भी खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके खराब प्रबंधन से हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ठोस कचरे का अनुचित निपटान जलवायु संकट बढ़ा सकता है। खतरनाक कचरे में पेंट, सालवेंट, 'आटोमोटिव' अपशिष्ट, कीटनाशक और पारायुक्त अपशिष्ट शामिल हैं। खतरनाक पदार्थ विस्फोट कर सकते या आग लगने का कारण बन सकते हैं और कुछ मनुष्यों या पर्यावरण में विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। उपभोक्ता उत्पाद और उनकी 'पैकेजिंग' में भी कुछ रसायन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।

संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजंसी की 2023 की रपट में भी ऐसे ठोस अपशिष्ट के खतरों से आगाह किया गया है। कार्बनिक प्रदूषक चिंता का कारण हैं, क्योंकि ये हवा और पानी से लंबी दूरी तक चले जाते हैं। ठोस अपशिष्ट कई ऐसी बीमारियों का भी कारण हैं, जिन्हें पहचानना शायद अभी बाकी है। वहीं अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन में कम निवेश हुआ है। भारत वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग सात हजार 366 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो देश भर में अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए आबंटित समग्र कार्यक्रम बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजंसी की 2023 की रपट में भी ऐसे ठोस अपशिष्ट के खतरों से आगाह किया गया है। कार्बनिक प्रदूषक चिंता का कारण हैं, क्योंकि ये हवा और पानी से लंबी दूरी तक चले जाते हैं। ठोस अपशिष्ट कई ऐसी बीमारियों का भी कारण हैं जिन्हें पहचानना शायद अभी बाकी है। वहीं अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन में कम निवेश हुआ है। भारत वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग सात हजार 366 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो देश भर में अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए आबंटित समग्र कार्यक्रम बजट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 'नेचर जर्नल' के अनुसार भारत सालाना नब्बे लाख तीस हजार टन उत्सर्जन कर दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष पर है। यह वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग पांचवां हिस्सा है। जाहिर है, यह भारत के लिए चिंता का विषय है।

ठोस अपशिष्ट दुनिया के लिए चुनौती है। मगर इनमें कुछ आर्थिक अवसर भी छिपे हैं। अनुमान के मुताबिक भारत द्वारा अपनाई गई चक्रीय अर्थव्यवस्था से 40 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति समेत कई संदर्भों में यह रोजगार का एक जरिया भी बना हुआ है। कबाड़ से करोड़ों बनाने की अवधारणा को भी ठोस अपशिष्ट में देखा जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी के बीच कचरा बीनने वाले को देखा जाना आम है। इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट नुकसान के साथ कई लोगों के लिए रोजी-रोटी है। बावजूद इसके, अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान का रास्ता खोजा ही जाना चाहिए।

अकेले शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग डेढ़ करोड़ टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। मगर देखा जाए तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन कानून और नीतियां जिस सक्रियता के साथ लागू होनी चाहिए, वह अभी भी मजबूत धरातल नहीं बना पा रही हैं। यह सच है कि भारत में उचित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 इलेक्ट्रानिक कचरे को संभालने के लिए है, जिसे दो नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 भी हमारे यहां है, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में देखें, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021 एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल, ठोस अपशिष्ट से दुनिया अनजान नहीं है। ऐसे में, इसके उत्पादन और निपटान में संतुलन ही आने वाले खतरे को कम कर सकेगा।

पता नहीं क्यों

अमिताभ स.

एक सवाल हमेशा हर किसी के जेहन में उठता है कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है या ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता! किसी भी विषय या मसले पर बात की जाए, सवाल उठेगा ही कि पता नहीं क्यों! एक जमाने में स्कूलों में अध्यापक मासूम बच्चों के भी कान खींचते थे, गालों पर थप्पड़ रसीद कर देते थे, कोमल हथेलियों पर फट्टे तक से पीटते थे, लेकिन कोई बच्चा स्कूल में अवसाद के कारण आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता था या फिर आत्महत्या नहीं करता था। इसके क्या कारण रहे होंगे? हर किसी के बचपन में रोज-रोज नए और महंगे खिलौनों के लिए जिद करना, मिलने पर उनसे खेल कर आनंदित होना, लेकिन एक-दो बार खेलने के बाद मन भर जाना। ऐसा पता नहीं क्यों? ज्यादातर घर कच्चे थे, कमरे कम थे, लेकिन किसी के बुजुर्ग माता-पिता कभी वृद्ध आश्रम नहीं जाते थे। पता नहीं क्यों? परिवार बहुत बड़े होते थे, पड़ोसियों के बच्चे भी दिन भर आस-पड़ोस की छत और आंगन में खेलते थे, घरों में ही शादियों जैसे बड़े समारोह हो जाते थे। पता नहीं क्यों?

सुबह और शाम गली-मुहल्ले के हर घर के बाहर कोयले या फिर उपले से अंगीठी सुलगाई जाती थी, धुआं गली-घरों में घुस जाता था, कोई चूं नहीं करता था और प्रदूषण का रोना नहीं था। पता नहीं क्यों? घर-परिवार में रोज गाय के खाने के लिए रोटियां सेंकने और निकालने की परंपरा के बावजूद गृहस्थी का बजट डगमगाता नहीं था और आमतौर पर संतुलित रहता था। जबकि आज परिवार के अपने खाने-पीने का बजट ही भारी पड़ने लगा है। पता नहीं क्यों? खाने को सादी दाल-रोटी होती थी, बावजूद इसके किसी को भी खून की कमी नहीं होती थी। रोग भी कम थे। पता नहीं क्यों?

पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए तब 'जिम' नहीं थे। दिन भर चूल्हा-चौका करते-करते हुए भी आमतौर पर सेहतमंद रहती थीं। पता नहीं क्यों? सगे भाई-भाई और भाई-बहन छोटी-छोटी बातों पर खूब लड़ते-झगड़ते थे। आपस में कुट्टी और कुटाई तक की नौबत आ जाती थी, लेकिन कुछ देर में फिर घुल-मिल जाते थे। मनमुटाव लंबा नहीं खिंचता था। पता नहीं क्यों? माता-पिता भी कई बार किसी मामूली बात पर भी बच्चों को थप्पड़ मार देते थे, लेकिन उनका मान-सम्मान कभी कम नहीं होता था। पता नहीं क्यों? आज यह समझना मुश्किल हो गया है कि लोग अनमोल रिश्ते दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अपनी बेमानी जिद पर अड़े रहते हैं। कई लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ अपने तेवर दिखाने लगते हैं। पता नहीं क्यों?

आज सोच बदल रही है। जैसे हर मोबाइल या उपकरण का नया माडल पहले के या पुराने से बेहतर होता है। नई युवा पीढ़ी की सोच पुरानी और दरम्यानी पीढ़ी से हट कर है। कुछ समय पहले एक बार किसी के घर की नाली बंद हो गई। रसोई, स्नान गृह वगैरह में सीवर का गंदा पानी बाहर निकलने लगा। गंदा पानी घर में घुसने से सारे काम रुक गए। गृहिणी ने प्लंबर को फोन किया। संयोग से वह खाली था। साइकिल दौड़ाता कुछ देर में आ गया। उसने कुछ ही देर में नाली खोल दी। मेहनताने के तौर पर पांच सौ रुपए मांगे तो घर की मालकिन भौंचक्की रह गई। बोली, 'मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूं। मुझे तो बच्चों को एक घंटा पढ़ाने के भी पांच सौ रुपए नहीं मिलते। तुम दो सौ रुपए ले लो... यही जायज है।' प्लंबर नहीं माना। अपनी बात पर अड़ा रहा। कहा-सुनी सुन कर भीतर से घर की बुजुर्ग महिला बाहर आ गईं। सारी बात सुनने-समझने के बाद बहू से उन्होंने कहा कि 'तूने तो दो सौ रुपए ज्यादा बोल दिए हैं। मुश्किल से बीस रुपए का काम है। इसे पचास रुपए देकर हिसाब करो।' मगर प्लंबर नहीं मान रहा था। इतने में घर की मालकिन का नौजवान बेटा बाहर से घर आया। वह मां का हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। समझाने लगा कि 'मां, वह दस मिनट में दौड़ा आया और फटाफट मिनटों में नाली खोल दी। उसने तुम्हारा कितना परेशानी कम कर दी। तुम्हारा तनाव दूर कर दिया। वह नहीं आता, तो दिन भर तुम्हारा काम न निपट पाता। इसे पांच सौ रुपए तो दो ही, ऊपर से पचास रुपए का इनाम भी दे दो!' मां और दादी नौजवान की समझ सुन कर हैरान हुए।

दुनिया मेरे आगे

बीते कल, आज और आने वाले कल की तीन पीढ़ियों की समझ में जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। विचारक जोनाथन मार्टेसन का मानना है कि भावनाएं और विचार लहरों की तरह होते हैं। आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किन लहरों की सवारी करनी है?

शायद इसी को पीढ़ियों का अंतराल कहते हैं। बीते कल, आज और आने वाले कल की तीन पीढ़ियों की समझ में जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। विचारक जोनाथन मार्टेसन का मानना है कि भावनाएं और विचार लहरों की तरह होते हैं। आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किन लहरों की सवारी करनी है?

जाहिर है कि एक जाने वाला कल होता है, और दूसरा आने वाला कल। यानी कुछ भी स्थिर नहीं होता। सब कुछ बदलने वाला होता है। हर चीज पाने या मिलने के सुख के संग-संग बिछुड़ने या न मिलने का दुख साथ चलता है। एक अमेरिकी उपन्यासकार जैक ने लिखा है कि हाथ में सदा अच्छे पत्ते आना ही जीवन नहीं है... खराब पत्तों के साथ अच्छा खेलना ही जीवन है। दोनों में अंतर यह होता है कि बीता कल एक गुजर चुका समय होता है, जिसमें हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि आने वाला कल एक अवसर होता है, जिस पर हम कर्म या क्रिया से नियंत्रित और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सीखने और सुधारने की प्रक्रिया बीते कल और आने वाले कल के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होती है।

हौसले की उड़ान

भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स सकुशल लौट आई हैं। कोई तकनीकी खराबी आने के कारण वे लगभग नौ महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रहीं। मगर पूरे धैर्य और आत्मविश्वास से सुनीता ने उस कठिन समय को गुजारा। उनके हौसले से सभी को सीखना चाहिए। हमें मेहनत और हिम्मत रख कर अपने सभी काम करने चाहिए। असफलताएं हमारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करें, तो घबराना नहीं चाहिए। हमारे देश में चंद्रयान-3 को संचालित करने में हमारे देश की महिला वैज्ञानिकों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाया था जो बेटियों को कमजोर समझते हैं। इससे पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष में कदम रख अपने माता-पिता के साथ भारत का भी मान दुनियाभर में बढ़ाया था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी बेटों की तरह अपना करिअर बनाने के मौके देने चाहिए। पढ़ा लिखा कर उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए ताकि जिंदगी में कभी पढ़ाई न करने के कारण कहीं निराश न होना पड़े।

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

स्त्री की जगह

किसी भी समाज के विकास का अंदाजा उस सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी से लगाया जा सकता है। महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। आज भारतीय समाज में भेदभाव रहित स्त्री-पुरुष समानता की बात की जा रही है, ताकि महिलाएं प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्थाओं से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता का इस्तेमाल एक बेहतर समाज के निर्माण में कर सकें। इसी उद्देश्य से अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी दबाव बन रहा है। इसीलिए विधायिका में महिलाओं को आरक्षण की बात भी उठी थी। कई सामाजिक जटिलताओं से समझा जा सकता है कि पुरुष प्रधान समाज महिला आरक्षण के प्रति कितना गंभीर है। महिला आरक्षण को कुछ लोग अगर बैसाखी मानते हैं, तो यह उनकी भूल है। दरअसल, यह तो छोटा-सा मुआवजा भर है उस वंचना का, जो सदियों से 'आधी दुनिया' पर किया जाता रहा है।

- खुशबू कुमारी, लखनऊ

दुस्साहस और कानून

हाल ही में मऊगंज जिले में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। एक एएसआइ की हत्या कर दी गई। यदि कानून रक्षकों पर ही हमला होने लगेगा तब आम जनता की रक्षा कौन करेगा ? सुरक्षाकर्मियों के साथ यह हरकत स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरेगा। ऐसे में जनता की, कानून की एवं राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होगी? पुलिस को अस्त्र-शस्त्र तो थमा दिए जाते हैं, किंतु उनको चलाने की अनुमति उनके पास नहीं होती। प्रदेश में पुलिस कर्मियों की कमी है, उस पर भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नेताओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। भूखे-प्यासे लंबे समय तक ड्यूटी करते रहते हैं। ऐसे में मुट्ठी भर पुलिस कर्मी नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बचते हैं। असामाजिक तत्त्वों एवं भीड़ तंत्र को किसी भी दशा में राजनीतिक आश्रय नहीं मिलना चाहिए। पुलिस पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पर हमला मतलब कानून व्यवस्था पर हमला है।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

कर्ज का बोझ

बैंकों द्वारा पिछले दस वित्त वर्षों में 16.35 लाख करोड़ के कर्ज की भारी-भरकम गैर निष्पादित रकम (एनपीए) को बट्टे खाते में डालने की खबर चिंता पैदा करती है। हैरत है कि सरकार और रिजर्व बैंक ने इसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसके अलावा, देश से पिछले वर्षों में सरकारी-गैर सरकारी बैंकों से कर्जा लेकर फरार हुए व्यापारियों को भारत लाकर कानून के तहत दंडित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। सारे मामले आश्वासनों तक सीमित हैं। एक तरफ हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं। काले धन की वापसी का दावा करते हैं, वहीं राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ असीमित सीमा तक बढ़ रहा है। डालर के मुकाबले हमारी मुद्रा की कीमत निरंतर घट रही है। शेयर बाजार में निवेशकों को पिछले दिनों भारी नुकसान हुआ। ये स्थितियां मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत नहीं देती हैं।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

महाराष्ट्र में हिंसा

खतरनाक प्रवृत्ति

महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार को लेकर हुई झड़पों से देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है जो हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत में सांप्रदायिकता कुछ नेताओं के लिए सुविधाजनक 'वोटबैंक राजनीति' का काम करती है। जहां बहुसंख्यक समाज के अनेक नेता गुलामी की निशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहीं कुछ कट्टरपंथी राजनेता तुष्टीकरण नीतियों के आधार पर ऐसे प्रतीकों पर यथास्थिति बनाए रखने की पैरवी करते हुए उनको टकराव का माध्यम बना रहे हैं। वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे प्रतीकों का महिमामंडन भी करते हैं। हाल ही में कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर प्रदर्शन किया था क्योंकि इसे वे गुलामी का प्रतीक तथा महाराष्ट्र के नायक शिवाजी का अपमान मानते हैं। उनके इस शांतिपूर्ण आंदोलन को टकराव का बहाना बना कर आपराधिक व समाज-विरोधी तत्वों ने सुनियोजित ढंग से नागपुर में आगजनी, पत्थरबाजी व उपद्रव किया जिससे कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस मुद्दे पर आत्मावलोकन की जरूरत है, लेकिन इसे केवल महाराष्ट्र तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इसे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भों के साथ ही समकालीन संदर्भों, भारत की प्रगति तथा सांस्कृतिक भावनाओं के उभार के साथ रख कर देखा जाना चाहिए। छठा मुगल शासक औरंगजेब भारतीय इतिहास का एक काला धब्बा है। उसका कार्यकाल निर्मम क्षेत्र विस्तार के साथ ही ऐसी कट्टरपंथी व उत्पीड़क नीतियों का समय था जब हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हुए। उसने हिंदुओं पर उत्पीड़क 'जजिया टैक्स' लगाया, शाही आदेशों से अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया या उनको अपवित्र किया, मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करवाई, अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को कुचल दिया तथा अपने द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में उठ रहे हर हाथ को काट दिया। औरंगजेब ने उलेमाओं से संभाजी महाराज पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के फर्जी आरोप लगवाये थे। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विदेशी मुस्लिम आक्रांता भारत के मूल निवासियों को नीचा दिखाने वाली विरासत छोड़ना चाहते थे। महाराष्ट्र की हालिया हिंसा को अतीत के साथ ही वर्तमान संदर्भों में भी देखा जाना चाहिए। कुछ हिंदू समूह लंबे समय से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसे वे ऐतिहासिक दमन का प्रतीक मानते हैं।

हाल ही में आई फिल्म 'छावा' में औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज पर किए निर्मम अत्याचारों को दिखाया गया है। कुछ विश्लेषक इसे मुगल साम्राज्य के खिलाफ फिर से भड़के गुस्से का कारण बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान विवाद को कुछ राजनेताओं ने हवा दी है जिनमें खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की औरंगजेब शासन के बारे में की गई टिप्पणी है जिसे रक्तरंजित इतिहास पर लीपापोती के प्रयास की तरह देखा जा रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करने वालों का प्रदर्शन समाप्त होने तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों समुदायों के लोगों को समझाने-बुझाने के बाद तनाव लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद सुनियोजित तरीके से भारी मात्रा में पत्थर लाए गए, पत्थरबाजों को बुलाया गया तथा हिंदुओं के घरों, दूकानों और वाहनों को निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने पेट्रोल बमों के साथ घातक धारदार हथियारों का प्रयोग कर पुलिस अधिकारियों पर हमले किए जिसमें एक डीसीपी पर जानलेवा हमला शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा है कि सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा देगी, लेकिन इसके साथ ही वह किसी को उसका महिमामंडन करने की अनुमति भी नहीं देगी। महाराष्ट्र में हुई हिंसा में देश के कुछ भागों में पहले हुए दंगों का पैटर्न दिखाई देता है। ऐसे दंगाइयों तथा उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन देने वाले राजनेताओं पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत की सर्वांगीण आर्थिक-सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति को कुछ अतीतजीवी व तुष्टीकरण समर्थक नेताओं का बंधक बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वैसे भी देश की बहुसंख्य जनता ऐसे तत्वों की असलियत पहचान कर उनको राजनीतिक व चुनावी रूप से हाशिए पर धकेल रही है। महाराष्ट्र सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

व्यापार युद्ध का सामना

अमेरिका द्वारा समान टैरिफ माडल लागू करने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था उथलपुथल की शिकार है। इससे विश्व व्यापार संगठन-डब्लूटीओ सिद्धान्तों का उल्लंघन कर भारत समेत विकासशील देशों को खतरा पैदा कर दिया है।

मृगांक एम. भौमिक
(लेखक, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं)

अमेरिका द्वारा विभाजनकारी तथा विश्व व्यापार के मूलाधार को चुनौती देने वाला समान टैरिफ माडल लागू करने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था उथलपुथल की शिकार है। इससे विश्व व्यापार संगठन-डब्लूटीओ सिद्धान्तों का उल्लंघन कर भारत समेत विकासशील देशों को खतरा पैदा कर दिया है। दुनिया इस समय अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रही है। अमेरिका में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लागू समान टैरिफ माडल और उसकी आर्थिक नीतियों ने विश्व व्यापार और वाणिज्य के सहज प्रवाह को बाधित किया है।

इस प्रक्रिया से विकासशील देशों को बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे विश्व व्यापार संगठन-डब्लूटीओ का वह माडल ध्वस्त हो गया है जो विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों से होने वाले आयातों पर उच्च टैरिफ लगाने की अनुमति देता था ताकि वे अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा कर सकें। इसके तत्काल प्रभावों में ये उद्योग पंगु हो जाएंगे तथा असमान प्रतियोगिता की स्थिति बनेगी। बढ़ती बेरोजगारी और निर्यात-संचालित वृद्धि का धीमा होना लगभग निश्चित है। भारत इस व्यापार युद्ध से अछूता नहीं रहेगा क्योंकि वैश्विक सहयोग के स्थान पर अब मजबूत पक्ष के लिए हितकर व्यापार समझौतों के लिए दबाव पड़ेगा। एक नई विश्व व्यवस्था स्वरूप ले रही है और भारत को इस परिदृश्य में सावधानी से, पर उत्साह से उतरना होगा।

अप्रैल, 2024 तथा नवंबर, 2024 के बीच भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी रहा है। उसने 52.89 बिलियन डालर के निर्यात तथा 29.63 बिलियन डालर के आयात किए, इस प्रकार 13.26 बिलियन डालर व्यापार भारत के पक्ष में था। यह व्यापार असंतुलन मुद्दे के केन्द्र में है। भारत के प्रमुख निर्यातों में हीरे, चिकित्सा उपकरण व उनके पुर्जे, जेवर, कृषि उत्पाद, शोधित पेट्रोलियम, चावल, टेक्सटाइल व वस्त्र, आटोमोबाइल पुर्जे, रसायन एवं पेट्रोरसायन तथा मशीनरी शामिल हैं। भारत अमेरिका से मुख्यत: खनिज ईंधन और तेल, मोती, कीमती पत्थर, नाभिकीय रिएक्टर, ब्वायलर, मशीनरी, बिजली के उपकरण, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, एलेक्ट्रानिक उपकरण तथा सोना आयात करता है। इन उत्पादों पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि लागत घटाने और गुणवत्ता बढ़ाने के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों में अपना बाजार हिस्सा और बढ़ा सकता है।

इसके विपरीत अमेरिका के पास भारत में अपना निर्यात बढ़ाने के सीमित विकल्प हैं, हालांकि वह कच्चे तेल और रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित कर सकता है जिनको अमेरिकन सरकार भारी सहायता देती है। इसका कारण भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं की लागत से उपभोग सीमित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम करने के प्रयास में अमेरिका आटोमोबाइल जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश का प्रयास करेगा जिन पर भारतीय घरेलू उद्योगों का प्रभुत्व है। यह केवल व्यापार वार्ता न होकर पूर्ण रूप से व्यापार युद्ध है जिसमें वैश्विक सहयोग या राजनयिक विचार पर जरा भी ध्यान दिए बिना बाजारों पर कब्जा करना ही उद्देश्य है। समान टैरिफ नीत टैरिफ कम करने तथा अमेरिका के लिए नए बाजार खोलने का परोक्ष प्रयास है। इसके पीछे का सच्चा एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है।

ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू समान टैरिफ की अवधारणा 'न्यायोचित एवं समानुपाती योजना' नहीं है, बल्कि यह व्यापार घाटा कम करने के लिए अपने व्यापार सहयोगियों पर ज्यादा आयात कर लगाने का प्रयास है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि निर्यातक देश अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। लेकिन यह उत्पाद से उत्पाद की तुलना के बजाय राष्ट्र से राष्ट्र की तुलना करने वाली नीति है। ऐसे में 'समान' अवधारणा अपने आप में भ्रामक है क्योंकि इसके प्रयोग पर नियंत्रण करने वाला कोई परिभाषित ढांचा नहीं है।

इसके बजाय यह अमेरिका सरकार को मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने का अवसर देता है जिससे निर्यातक देश उनके संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने तथा स्वयं को पहले से लगे टैरिफ पर प्रतिक्रिया के लिए मजबूर होते हैं। असमान संपदा वितरण, आर्थिक विकास तथा तकनीकी प्रगति से परिभाषित दुनिया में ये टैरिफ समान होने के बजाय दंडात्मक हैं तथा असमान रूप से विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। डब्लूटीओ द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समान टैरिफ का सच्चा अर्थ अमेरिकी प्रशासन द्वारा पैरवी किए जाने वाले अर्थ से एकदम अलग है। विवाद समाधान समझदारी के डब्लूटीओ के अनुच्छेद 22.4 के अनुसार समानता का अर्थ जवाबी टैरिफ है जब कोई देश डब्लूटीओ का आदेश मानने से इनकार कर दे। इसके साथ ही जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एंड ट्रेड-गैट का अनुच्छेद 28 व्यापार समझौतों को पुन: परिभाषित करने तथा मुआवजे की गणना के बारे में है। अमेरिका वर्तमान समय में इन सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रहा है।

चूंकि विश्व व्यापार नीतियां लगातार प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्थाओं द्वारा परिभाषित होती हैं, इसलिए अमेरिका की समान टैरिफ रणनीति से काफी उथलपुथल पैदा होने की उम्मीद है बशर्ते कि जवाबी कदमों से स्थिति में स्थिरता न आ जाए। लेकिन यह मुख्य सवाल बना रहेगा कि क्या यह जवाबी टैरिफ नीति अमेरिका का लक्षित उद्देश्य पूरा कर सकेगी? इसकी संभावना कम है। गहरे विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका का व्यापार-जीडीपी अनुपात वर्तमान समय में केवल 26.9 प्रतिशत है, जबकि यह चीन में 38.4 प्रतिशत, जापान में 46.8 प्रतिशत और भारत में 50 प्रतिशत है। इसके साथ ही अमेरिका में आयात की गहनता निर्यात की गहनता से लगभग तीन गुना अधिक है। ऐसे में अमेरिका के व्यापार घाटे के पीछे असली मुद्दा उच्च विदेशी टैरिफ के बजाय अमेरिकी व्यापार का खराब प्रदर्शन है जो वैश्विक निर्यातों का केवल 8.3 प्रतिशत है।

इसके उलट सेवा क्षेत्र में अमेरिका को 200 बिलियन डालर का लाभ प्राप्त है जिससे वह सेवाओं के आयात और निर्यात में सारी दुनिया में अग्रणी है। अमेरिकन निर्यात के समक्ष प्रमुख बाधा अनुचित टैरिफ ढांचों के बजाय सप्लाई की बाधायें तथा सस्ती अर्थव्यवस्था स्थापित करना है। अमेरिकन सेवा निर्यातों की भारी मांग को देखते हुए अमेरिका के व्यापार को इससे प्रतियोगिता पर विचार करना चाहिए।

1.4 बिलियन जनसंख्या वाले भारत को बजट प्राविधानों से वित्तपोषित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से अपने नागरिकों की सहायता करनी चाहिए। ये खर्च व्यापार और वाणिज्य पर अत्यधिक निर्भर हैं जिसमें निर्यात-संचालित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत कम खर्च वाली वस्तुओं के उत्पादन से अपनी अर्थव्यवस्था संचालित कर करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। इन उद्योगों को सुरक्षा देना जरूरी है। नए बाजार क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों की अनुमति देने से अल्पकालीन रूप से घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकते हैं तथा यदि अमेरिकन निर्माता सस्ती चीजें बनाने में विफल रहे तो इनसे दीर्घकालीन रूप से सप्लाई श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। हालांकि, भारत अमेरिका को अपना हीरों का निर्यात घटा सकता है, पर वे अपने घरेलू उद्योगों को अस्थिर करने का जोखिम नहीं मोल ले सकता है।

समय आ गया है कि दबाव में व्यापार घाटे को कम करने के प्रयासों का सामना करने के लिए भारत कठोरता से डब्लूटीओ निर्देशों का पालन करते हुए वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य व्यापार नीति का समर्थन करे। घरेलू उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन-पीएलआइ योजना के साथ वैकल्पिक व्यापार साझीदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

इससे 'समान टैरिफ' का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। भारत को सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि यह चरण अस्थाई है, पर इससे पैदा होने वाला दीर्घकालीन स्थायित्व रणनीतिक दृढ़ता पर निर्भर होगा।

आत्मविश्वास के अभाव से प्रभावित होती प्रतिभा

> “जमैका के उद्यमी और राजनीतिज्ञ मार्कस गर्वे ने लिखा है, यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप जीवन की दौड़ में दो बार हार चुके हैं।”

रवि बलूरी
(लेखक, लेखक छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के सीईओ हैं)

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में अपार प्रतिभा है और वे खेल के विभिन्न प्रारूपों में सफल चैंपियन हैं। हालांकि, अभेद्य कारणों से वे आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान कुछ चौंकाने वाला प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों होता है? जमैका के उद्यमी और राजनीतिज्ञ मार्कस गर्वे ने लिखा है, यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप जीवन की दौड़ में दो बार हार चुके हैं। कई साल पहले, मीजी युग में ग्रेट वेव्स के नाम से मशहूर एक पहलवान रहता था, जिसके पास अपने शिक्षक को भी हराने की अद्भुत क्षमता थी।

हालांकि, आधिकारिक टूर्नामेंट में, वह अपने से कहीं कमतर प्रतिद्वंद्वियों से हार जाता था, जिससे हर मुकाबले के बाद उसकी अनुमानित प्रतिष्ठा धूमिल होती जाती थी। ऐसा लगता था कि कोई मनोवैज्ञानिक समस्या थी। इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए, वह एक जेन मास्टर के पास गया। गुरु ने अपने नए शिष्य को उस रात समुद्र तट पर स्थित एक बौद्ध मंदिर में ध्यान करने का निर्देश दिया और उसे केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और समुद्र की गहराई से उठने वाली सबसे बड़ी लहरों को भी निगलने का निर्देश दिया।

जैसे-जैसे रात ढलती गई, समुद्र में ज्वार-भाटा आने लगा और लहरों ने विशाल आकार ले लिया और अपने प्रक्षेप पथ में सब कुछ समाहित कर लिया। यहां तक कि लेटे हुए बुद्ध भी नहीं बच पाए और ज्वार की लहरों के मार्ग का अनुसरण करने वाले भूत ने उन्हें भी घेर लिया। लहरें बेकाबू हो गई थीं और रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर रही थीं। लेकिन महान लहरों ने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित किया और पूरी लगन और एकाग्रता के साथ ध्यान किया। अगली सुबह जेन गुरु ने अपने स्थिर शिष्य द्वारा बनाए गए विनाश और संतुलन दोनों को देखा। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने अस्थिर मन पर विजय प्राप्त करने के बाद, सभी कुश्ती मुकाबलों और मुकाबलों में निरंतर सफलता के प्रति आश्वस्त रहें। आत्मविश्वासी होने के लिए, व्यक्तियों, उद्यमियों, कॉरपोरेट्स, आध्यात्मिक साधकों, राजनीतिक नेताओं और पार्टियों, खिलाड़ियों और टीमों सभी को अपनी सोच के पैटर्न को यह संभव नहीं है से बदलकर यह पूरी तरह से संभव है जैसी मानसिक स्थिति में लाना होगा। सफलता की नींव एक ऐसे पैटर्न पर आधारित है जो आशावाद, आत्म-विश्वास और आत्म-प्रेरणा पर आधारित है, जो आत्मविश्वास की ओर ले जाता है।

केवल प्रतिभा और धीरज ही आत्मविश्वास और शुद्ध सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह बहुत संभव है कि ये केवल क्षणिक हों। किसी व्यक्ति या संगठन के लिए आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की विशेषता का उपयोग करना बहुत जरूरी है। विरोधाभासी रूप से, जबकि अकेले कड़ी मेहनत आत्मविश्वास के स्तर को नहीं बढ़ाती है, यह व्यक्ति को शॉर्टकट का सहारा न लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह अंदर से हीन भावना की ओर ले जाती है और व्यक्ति तकनीकी रूप से अनुकूलन करने या चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। एक नेता में 3 सी - आत्मविश्वास, विश्वसनीयता और दृढ़ विश्वास, छिपी हुई क्षमता को बढ़ाने और उलझी हुई स्थितियों को समग्र रूप से देखने के लिए व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अपराधबोध, संदेह, खुद और सहकर्मियों की अत्यधिक आलोचना, आत्म-दया, शर्म, विनम्रता की कमी, बिना किसी ठोस परिणाम के व्यक्तियों को आदर्श मानना, अत्यधिक आलस्य, मन की उदास स्थिति, टीम के सदस्यों का एक-दूसरे पर भरोसा न करना या अत्यधिक अभिमान जैसी नकारात्मक भावनाएँ किसी व्यक्ति या संगठन की प्रगति में बाधा बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्मविश्वास और उपलब्धि का स्तर कम हो जाता है। ऐसे आलसी व्यक्तियों के लिए बुद्ध का नुस्खा है कि वे मन की शुद्धि पर ध्यान लगाएँ, अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति पर ध्यान लगाएँ, अपने चारों ओर मौजूद विशाल शून्यता पर ध्यान लगाएँ और साथ ही आत्म-सम्मान विकसित करने की शपथ लें। ऋषियों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा सार्वभौमिक रूप से यह माना जाता है कि जीवन उतार-चढ़ाव और चुनौतियों से भरा है। सुदर्शन क्रिया जैसी श्वास तकनीक का अभ्यास करके, प्राणायाम का अभ्यास करके, ध्यान लगाकर और स्वयं का अवलोकन करके आशावाद और आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। आईसीसी टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का संघर्ष प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि अटूट आत्मविश्वास की कमी से उपजा है। जिस तरह पहलवान ग्रेट वेव्स को जीत हासिल करने से पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करने की जरूरत थी, उसी तरह टीमों और व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं में गहरा विश्वास पैदा करना चाहिए। आत्मविश्वास केवल कौशल या धीरज का उपोत्पाद नहीं है, बल्कि आशावाद, आत्म-प्रेरणा और दृढ़ विश्वास से आकार लेने वाली मानसिक स्थिति है। 3 सी- आत्मविश्वास, विश्वसनीयता और दृढ़ विश्वास-नेताओं, एथलीटों और संगठनों को स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। आत्म-संदेह, अत्यधिक गर्व और टीम के भीतर विश्वास की कमी जैसी नकारात्मक भावनाएँ आत्मविश्वास को खत्म कर सकती हैं, जिससे सफलता में बाधा आ सकती है। बुद्ध का ज्ञान व्यक्तियों को मन को शुद्ध करने, अनित्यता को अपनाने और आत्म-सम्मान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

दक्षिण अफ्रीकी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में मिली हार से बाहर निकलने के लिए अपनी मानसिकता को संदेह से निश्चितता और झिझक से लचीलेपन की ओर बदलना होगा।

ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आत्म-जागरूकता दबाव में कामयाब होने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता पैदा करने में मदद कर सकती है। सच्चे चैंपियन न केवल कुशल होते हैं बल्कि उनमें अटूट आत्मविश्वास भी होता है। सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, दक्षिण अफ्रीका अपनी अपार क्षमता का दोहन कर सकता है और विश्व मंच पर जीत की संभावनाओं को जीत में बदल सकता है।

आप की बात

गर्मी के तेवर

मार्च में अभी ठंड की ही ठीक से बिदाई नहीं हो पाई है कि गर्मी के तीखे तेवरों ने चिंता पैदा कर दी है जबकि इसे मौसम की संधि वेला और गुलाबी ठंड के साथ गर्मी की आहट का महीना माना जाता है। गंभीर चिंता और चुनौतियां तब पैदा होती दिख रही है जब मौसम विभाग ने तेज लू चलने की आशंकाएं जताई हैं। इसके पीछे काफी हद तक मानवीय गलतियां और आधुनिक बदलाव नजर आ रहे है जो हर हाल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। इस समय प्राकृतिक हालात भी बड़े अजीब है। बर्फबारी के साथ ही बारिश के साथ ही कुछ राज्यों के गर्म हवाओं की चपेट के हालात से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है? इस मौसम में नागरिकों को बड़ी सजगता रखनी होगी क्योंकि खान-पान और रहन-सहन में जरा सी भी ढिलाई स्वास्थ्य के लिए मुसीबत बन सकती है? भारतीय मौसम विभाग के साथ ही दुनिया भर में दर्ज मौसम रिकार्ड के अनुसार अब तक फरवरी सबसे गरम महीना रहा है। वैसे तो सारी दुनिया के नेताओं को ग्लोबल वार्मिंग से युद्धस्तर पर निपटने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन अमेरिका में नई सरकार द्वारा पर्यावरण की चिन्ता छोड़ने तथा व्यापार युद्ध छेड़ने के बाद अब भरत समेत सारी दुनिया के नागरिकों को मौसम से निपटने के प्रयास स्वयं करने होंगे।

– **अमृतलाल मारू**, इन्दौर

रूस-यूक्रेन युद्ध

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक माह के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं जो कि शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन दोनों देशों की ओर से जो कठोर शर्तें रखी गई है उन्हें देखते हुए लगता नहीं कि यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अमेरिका ने रूस पर दबाव हटा लिया है और युद्धविराम भी उसके शर्तों पर करने के प्रयास में लग गया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि युद्धविराम को लागू करने और संभावित रूप से इसके विस्तार करने पर चर्चा करने के लिए आने वाले दिनों में सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी और रूसी तकनीकी दलों की मुलाकात होगी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेनी अधिकारी इस वार्ता का हिस्सा होंगे या नहीं। इस युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों ही महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक देश हैं और इसके कारण खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। इसमें न केवल सैनिकों की जान जा रही है, बल्कि आम नागरिकों को भी भारी कठिनाइयों झेलनी पड़ रही हैं।

– **विभूति बुपक्या**, खाचरोद

वक्फ कानून का विरोध

वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर जंतर मंतर पर किया गया आयोजन विफल रहा। मुस्लिम उलेमा और नेताओं ने अपने भाषणों में कई तरह के अनर्गल आरोप लगाए और लोगों को डराने और भड़काने के प्रयास किए। वे वक्फसंशोधन विधेयक, 2024 के विरोध में आंदोलन र रहे थे जिसे लोकसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाना और उसके कार्यों में पारदर्शिता लाना है। वक्फ का घोषित उद्देश्य वक्फ की गई संपत्तियों से समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करना है, लेकिन यह उद्देश्य शायद ही कहीं पूरा होता हो। आमतौर से यही दिखाई देता है कि वक्फ संपत्तियों पर कुछ माफिया व निहित स्वार्थी तत्वों ने कब्जा कर रखा है और वे अपनी कब्जेदारी छिनने के भय से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। विडंबना है कि अधिकांश गरीब मुस्लिम नौजवान ऐसे तत्वों के भड़कावे में आकर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को तटस्थ दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। मुस्लिम समाज की असली समस्याओं के समाधान के बजाय उनको भावनात्मक मुद्दों पर भड़काने के प्रयास से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन जंतर मंतर पर एकत्र नेताओं ने ठीक यही काम किया है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

किसानों पर कार्रवाई

पंजाब सरकार ने पिछले 13 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर और उससे जुड़े मार्ग को खुलवाने का निर्णय करते हुए आन्दोलनकारी किसानों को यहां से खदेड़ दिया है। उनके अस्थाई तम्बूओं आदि को हटा कर अब फेंक दिया गया है एवं 250 से भी अधिक आन्दोलनरत किसानों की गिरफ्तारी भी की गई है। भगवत मान सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार का यह निर्णय काफी सराहनीय कहा जा सकता है क्योंकि नेशनल हाईवे को घेरा डालकर साल भर से किसान यहां स्थाई टेंट लगाकर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर बैठे हुए थे। इस रोड के बन्द होने के कारण यहां से निकलने वाले अधिकांश यात्री काफी परेशान थे। अत: मार्ग खुल जाने से अब उन सभी में काफी उत्साह है। शंभू बॉर्डर पर यातायात खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका था। इससे किसान आंदोलन के नाम पर किसानों की जिद की सीमा भी सामने आ गई है। यह आम आदमी पार्टी-आप की रणनीति का भी नमूना है जो पहले केन्द्र सरकार को परेशान करने के लिए किसानों को भड़काने पर लगी थी, पर अव्यवस्था बढ़ने पर उसे कार्रवाई करनी पड़ी।

– **एमएम राजावत**, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते है।

सम्पादकीय

कैंसर इलाज एक चुनौती

वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक जिला अस्पताल के साथ 'कैंसर केयर केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक प्रत्येक कैंसर केंद्र में एक विशेषज्ञ डॉक्टर, 2 नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक बहुपयोगी कर्मचारी जरूर होने चाहिए। भारत में कितने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यह संख्या विभिन्न सर्वेक्षणों में अलग-अलग रही है। यह आश्चर्यजनक है कि देश में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निश्चित गणना नहीं है। अलबत्ता यह अनुमान जरूर है कि देश में कमोबेश 2000 कैंसर विशेषज्ञों की कमी है। जो चिकित्सक सेवारत और उपलब्ध हैं, उनमें से करीब 50 फीसदी शहरों में ही काम कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैंसर का विस्तार और संभावनाएं एक बेहद गंभीर समस्या है। तो 'कैंसर केयर केंद्र' की बजटीय व्यवस्था पर शुरू से ही सवाल उठने लगते हैं। हम ऐसे मुद्दे को सवालिया बनाने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन यथार्थ बेहद डरावना है कि औसतन एक लाख में से मात्र 100 लोगों में ही कैंसर की पहचान हो पाती है। कैंसर के प्रति जन-जागृति नगण्य है, लिहाजा भारत में जन-स्वास्थ्य की यह अहम चुनौती है कि कैंसर का रोग तब पता चल पाता है, जब रोग आखिरी चरण में पहुंच जाता है, लिहाजा कैंसर लाइलाज हो जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अभी कुछ डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक, 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख से अधिक मरीज थे। विशेषज्ञ इससे भी ज्यादा संख्या मानते हैं। दरअसल यह संख्या दर्ज मरीजों से 1.5 से 3 गुना अधिक हो सकती है। बेशक यह संख्या डरावनी है। हालांकि देश में गर्भाशय, मुंह और स्तन कैंसर की जांच के कार्यक्रम चलते रहे हैं। कैंसर के एक-तिहाई से ज्यादा मामले शरीर के इन्हीं अंगों में होते हैं, लेकिन रोग के पता लगाने की दर विश्व में सबसे कम है। कैंसर केयर के जो केंद्र राजधानी दिल्ली में भी कार्यरत हैं, उनमें या तो डॉक्टर गायब हैं अथवा जांच के उपकरण खराब हैं या इलाज की बारी लंबे-लंबे वक्त के बाद आती है। स्वाभाविक है कि रोग फैलता ही जाता है। जब तक इन केंद्रों पर कोई सख्त प्रशासनिक लगाम नहीं होगी, तब तक बजट के 'कैंसर केयर केंद्र' भी सफल प्रयोग साबित नहीं हो सकते। पूर्वोत्तर और केरल में कुछ जिला अस्पतालों में 'कैंसर केयर केंद्र' काम कर रहे हैं, लेकिन वे कितने कारगर हैं, इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। बहरहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती साबित होगी। सरकार प्रस्तावित कार्यक्रम की शुरुआत में मोबाइल क्लीनिकों को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसे क्लीनिक एक विशेषज्ञ चिकित्सक का विकल्प नहीं हो सकते और कैंसर विशेषज्ञों का अभाव है। कैंसर के संभावित मरीजों में बहुधा ऐसे हैं, जो जांच कराने ही नहीं आते। इस तबके में महिलाएं अधिकतर हैं। अस्पतालों के साथ कैंसर केयर केंद्र जोड़ने का प्रयास तब कारगर हो सकता है।

नफरत, असमानता एवं नस्लीय भेदभाव से लड़ें

समस्या

ललित गर्ग
दिल्ली-92

इजरायल के इस फैसले के साथ गाजा से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग अपनों के शवों को खोजने के लिए एक बार फिर मलबों को उलट-पलट रहे हैं। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा सिटी में कंक्रीट के ढेर से एक बच्चे के शव को निकालने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति ने कहा, हम अपने नंगे हाथों से खुदाई कर रहे हैं।

नस्लवाद मानवता के माथे पर एक बदनुमा दाग है, यह सिर्फ उन लोगों के जीवन को ही नुकसान नहीं पहुंचाता जो इसे झेलते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। हम सभी भेदभाव, विभाजन, अविश्वास, असहिष्णुता, घृणा और नजरत से भरे समाज में जीतते नहीं, बल्कि हारते हैं। नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई हर किसी की लड़ाई है। नस्लवाद से परे एक दुनिया बनाने में हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य से जनजागृति का माहौल बनाने के लिये प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व स्तर पर नस्लवाद के खिलाफ उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में 1960 के शार्पविले नरसंहार के पीड़ितों को याद करते हैं। हम उन लोगों की आवाज एवं दर्द सुनते हैं जो नस्लवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे। यह दिवस नस्लीय भेदभाव को खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और नस्लवादी विचारों और प्रथाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई को रेखांकित करता है, ताकि नस्लीय अलगाव से मुक्त वैश्विक समझ और एकता को बढ़ावा देते हुए नस्लमुक्त आदर्श एवं समानतामूलक दुनिया का निर्माण किया जा सके।

किसी व्यक्ति के साथ उसकी त्वचा के रंग, नस्ल, जातीय मूल या जन्म के देश के आधार पर भेदभाव करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है। नस्लीय भेदभाव के जरिए लोगों को समान अवसरों से वंचित किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है। नस्लवाद, विदेशी लोगों के प्रति घृणा और उससे संबंधित भेदभाव और असहिष्णुता सभी समाजों में, हर जगह मौजूद हैं। 21 दिसंबर, 1965 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 2106 (एक्सएक्स) के माध्यम से सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया, जो नस्लवाद को मिटाने के वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस वर्ष सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में से पहली के रूप में, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने भविष्य के मानवाधिकारों की उन्नति के लिए मंच तैयार किया। 60वीं वर्षगांठ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ की गई प्रगति पर चिंतन करने और मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालने का आह्वान करती है। यह समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और नस्लवाद को खत्म करने के प्रयासों को जारी रखने का समय है, ताकि सभी व्यक्तियों, समाजों के लिए समान व्यवहार एवं समानतामूलक विश्व की संरचना सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत में नस्लीय भेदभावमुक्त समाज को निर्मित करने के लिये प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार चाहती है कि नस्लवाद किसी भी स्थिति में और अवश्य ही समाप्त होना चाहिए। और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर नस्ल, जाति, रंग, लिंग, पंथ में रुचि रखने वाले लोग एक-दुसरे से सुरक्षित और आपस में संबंधित है, जिससे कि हमारा आने वाला कल सौहार्दपूर्ण तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला हो। बावजूद इसके पूर्वोत्तर राज्यों एवं अन्य समाजों में नस्लीय भेदभाव पसरा है। नस्ल प्रभावित लोगों के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये घटनाएं न सिर्फ राजधानी में इन राज्यों के लोगों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता की स्थिति को दर्शाती हैं, बल्कि यहां कानून-व्यवस्था के हालात पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। विगत एक वर्ष में दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें जहां हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले बड़ी संख्या में हैं, वहीं महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़, फोन पर फब्तियां कसने व घूरने जैसी घटनाओं को लेकर दर्ज किए गए, मामलों की संख्या भी कम नहीं है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नस्लीय टिप्पणियां किए जाने संबंधी मामले भी आ रहे हैं। इस तरह तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाएं राजधानी में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा कर रही हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। ये स्थितियां भारत के नस्लीय भेदभाव के विरोध और अश्वेतों को समान अधिकार और प्रतिष्ठा दिए जाने की वकालत को भी धुंधलाती है। क्या कारण है कि देश के भीतर के सामाजिक विभाजन एवं नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद उसे मिटा नहीं रहे हैं। भले ही ऐसी वारदातें पुलिस की नजर में छोटी हों लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरवपूर्ण संस्कृति के लिये चिन्ताजनक है। तेजी से बढ़ता नस्लीय हिंसक दौर किसी एक प्रान्त का दर्द नहीं रहा। इसने हर भारतीय दिल एवं भारत की आत्मा को जख्मी बनाया है। अब इन हिंसक होती स्थितियों को रोकने के लिये प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। देश में कई विसंगतिपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण धाराएं बलशाली हो रही हैं, जिन्होंने जोड़ने की जगह तोड़ने को महिमामंडित किया हैं, प्रेम, आपसी भाईचारे और सौहार्द की जगह नफरत, द्वेष एवं विघटन को हवा दी। शायद यही वजह है कि भारत में अब भी लोग हर तरह के वर्ग और समुदाय के साथ घुल-मिलकर रहना सीख नहीं पाए हैं। उनके अचेतन में बिठा दिए गए पूर्वाग्रह समय-समय पर खतरनाक ढंग से सामने आते रहते हैं।

डिजिटल लत और नशे की चुनौतियां-समाधान

आज हम देखते हैं कि कई अभिनेता और खिलाड़ी शराब और गुटखे के विज्ञापन करते हैं, जो युवाओं को गलत संदेश देते हैं। इसके अलावा, ड्रीम इलेवन और ऑनलाइन गेमिंग को भी इन लोगों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो युवाओं को रातोंरात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। यदि हमें युवाओं में मानवीय मूल्यों को बचाना है, तो पहले स्वयं को बदलना होगा। तभी हम दूसरों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने आचरण और विचारों में सुधार करना होगा

समाज में अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले लोग समाज के स्तंभ होते हैं। ये लोग समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सुसंस्कृत समाज की कल्पना उसके सदस्यों के आचरण और मूल्यों पर निर्भर करती है। समाज में सुख-शांति और एकता बनाए रखने के लिए सहयोग और एकजुटता आवश्यक है। यही वह धागा है जो मानव समाज को बांधे रखता है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। मनुष्य के स्वभाव में दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, कृतज्ञता और मानवीय हास्य-मजाक जैसे गुण होने चाहिएं। ये गुण ही मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। मित्रता, विनम्रता, शिष्टाचार और दूसरों की परेशानियों के प्रति चिंता जैसे गुण सकारात्मकता और अपनेपन का संदेश देते हैं। ये अच्छाइयां ही समाज को रहने योग्य एक सुंदर स्थान बनाती हैं। लेकिन आज के समय में, विशेषकर युवाओं में, इन मानवीय गुणों का ह्रास होता जा रहा है। आज का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। चाहे वह ड्रग्स का नशा हो या मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत, यह समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है।हम सभी इस समस्या से चिंतित तो हैं, लेकिन इसका समाधान ढूंढने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। अधिक धन कमाने के लालच में कुछ लोग युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं, जो न केवल उनके भविष्य के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती भी है। नशीली दवाओं की समस्या बहुआयामी है। यह केवल कानून और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करती है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केवल सरकार या पुलिस प्रशासन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस, समाज, परिवार और शिक्षण संस्थानों की समान भागीदारी हो। यदि सामाजिक स्तर पर सहयोग, अनुशासन और सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो नशे की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सकता है। खेलकूद और प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही, सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भी नशे की ओर प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारक है। दूसरी गंभीर समस्या मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का नशा है। आज का युवा वर्ग इस लत से बुरी तरह प्रभावित है। मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी खतरों में आंखों पर दबाव बढ़ना, एकाग्रता में कमी, तनाव और चिंता बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और अकेलेपन की भावना शामिल हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मोबाइल फोन के माध्यम से हैकिंग, निजी जानकारियों का लीक होना और अन्य साइबर अपराधों का खतरा बढ़ गया है। बच्चों के मस्तिष्क पर मोबाइल फोन का अधिक उपयोग और भी हानिकारक प्रभाव डालता है।

इसलिए, मोबाइल फोन के सावधानीपूर्वक उपयोग और निगरानी की आवश्यकता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को डिजिटल साक्षरता के बारे में शिक्षित करें और उनके स्क्रीन टाइम को सीमित करें। अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया और चीन ने बच्चों की स्क्रीन टाइम को सीमित करने के संबध में कानून बनाए हैं! भारत सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए! युवा वर्ग में मोबाइल की लत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वे अपनी पढ़ाई-लिखाई को छोड़कर घंटों सोशल मीडिया पर रील्स देखने और बनाने में व्यस्त रहते हैं। यह न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। हाल ही में एक समाचारपत्र में पढ़ा कि एक छात्रा ने मोबाइल फोन के उपयोग से रोके जाने के कारण आत्महत्या कर ली। यह घटना हमें समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने युवाओं को सही दिशा दे पा रहे हैं? यह समय है कि हम इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से विचार करें और युवाओं को डिजिटल दुनिया के सही और गलत के बीच अंतर समझाने का प्रयास करें।

हमारे समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सतर्कता, जागरूकता, अनुशासन, संयम और अच्छी संगत ही हमें इनसे बचा सकती है। समाज में कुछ पेशेवर लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि अध्यापक, नेता, खिलाड़ी और अभिनेता। यदि ये लोग अपनी आचार संहिता को भूल जाएं, तो समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम देखते हैं कि कई अभिनेता और खिलाड़ी शराब और गुटखे के विज्ञापन करते हैं, जो युवाओं को गलत संदेश देते हैं। इसके अलावा, ड्रीम इलेवन और ऑनलाइन गेमिंग को भी इन लोगों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो युवाओं को रातोंरात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की बढ़ती समस्या

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष कीटनाशकों की छोटी मात्रा होती है जो फसलों पर इस्तेमाल किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों पर या उनके भीतर रह जाती है। ये अवशेष संभावित रूप से स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जो विशिष्ट कीटनाशक और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है।

भारत में जाँचे गए 50 प्रतिशत से अधिक खाद्य नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे सब्जियाँ, फल, अनाज, दालें और मसाले, विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक पाए गए हैं। कीटनाशकों का उपयोग फसलों पर कीटों, कवक और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उन्हें पानी, मिट्टी और हवा के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिससे आस-पास की फसलें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, भंडारण और परिवहन के दौरान खराब होने से बचाने के लिए कुछ कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक, टमाटर और आलू जैसे आम फलों और सब्जियों में अक्सर कीटनाशकों के महत्वपूर्ण अवशेष होते हैं। चावल, गेहूँ, दाल और छोले जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में भी हानिकारक कीटनाशक हो सकते हैं।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष कीटनाशकों की छोटी मात्रा होती है जो फसलों पर इस्तेमाल किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों पर या उनके भीतर रह जाती है। ये अवशेष संभावित रूप से स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जो विशिष्ट कीटनाशक और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। भारत वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों के शीर्ष उपभोक्ताओं में से एक है, जो फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए कृषि में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। हालाँकि, भोजन में कीटनाशक अवशेषों का पता लगाना एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। शोध से पता चलता है कि भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों में ये अवशेष मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक है। यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य चिंताएँ पैदा करती है और बेहतर खाद्य सुरक्षा विनियमों और अधिक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा हाल ही में की गई अपील भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। कीटनाशकों से खाद्य पदार्थों का संदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जो आधुनिक खेती प्रथाओं और रसायनों के लापरवाह उपयोग से और भी बदतर हो जाता है। हालाँकि कई नियम उपाय मौजूद हैं, फिर भी निगरानी, प्रवर्तन और सार्वजनिक शिक्षा में कमियाँ हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक मजबूत सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में जाँचे गए 50 प्रतिशत से अधिक खाद्य नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे सब्जियाँ, फल, अनाज, दालें और मसाले, विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक पाए गए हैं। कीटनाशकों का उपयोग फसलों पर कीटों, कवक और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उन्हें पानी, मिट्टी और हवा के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिससे आस-पास की फसलें प्रभावित होती हैं।

समाचार पत्र और पत्रिका के बीच अंतर

समाचार पत्र और पत्रिका के बीच अंतर उनके स्वरूप, आकार, पठनीयता, विषय-वस्तु और पाठकों पर आधारित है। हालाँकि, मुख्य अंतर यह है कि पत्रिकाएँ मासिक आधार पर उपलब्ध होती हैं और समाचार पत्र दैनिक आधार पर उपलब्ध होते हैं। समाचार पत्रों का निर्माण जूलियस सीज़र के समय से होता है। उस समय, ये किताबें थीं जिनका उपयोग जनता को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता था। फिर, 59 ई.पू. में. 1911 में एटा दिनारा नामक पहला समाचार पत्र बनाया गया। दूसरी ओर, यह 18वीं शताब्दी में पत्रिकाओं में लोकप्रिय हो गया। इन्हें पहली बार अवकाश विशेष के रूप में प्रकाशित किया गया था और प्रकाशन के समय ये सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। अब, उनके आकार से यह स्पष्ट है कि समाचार पत्र आकार में पत्रिकाओं से बड़े होते हैं। आमतौर पर, पत्रिकाओं का आकार पुस्तक-प्रकार का होता है, जबकि समाचार-पत्रों का उद्देश्य पाठक को उनकी विषय-वस्तु को पूरी तरह समझने के लिए उन्हें हाथों की लंबाई के अनुसार फैलाना होता है। उनके स्वरूप, पत्रिका और समाचार पत्र के आधार पर अन्य अंतर उनके रंग, पाठ और आकर्षण पर होंगे। यहां, पत्रिकाएं समाचार पत्रों की तुलना में अधिक रंगीन होती हैं, क्योंकि रंग पत्रिका को विशेष जीवन देते हैं, जबकि समाचार पत्रों में चित्रों का न होना कोई बकवास नहीं है। एक और अंतर यह है कि सामग्री को पत्रिकाओं और समाचार पत्रों दोनों में विभाजित किया गया है। यह बहुत स्पष्ट है कि समाचार पत्रों की विषय-वस्तु पत्रिकाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और सीधी होती है। इसके अलावा, समाचार पत्र विविध विषयों जैसे व्यापार, अपराध, मनोरंजन, राजनीति और खेल को कवर करते हैं, जबकि पत्रिकाएं किसी विशिष्ट विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। विभाजन की दृष्टि से, आकार में अंतर के कारण, समाचार पत्रों के लिए अपनी सूचना को प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तुत करना अधिक आसान होता है, जबकि पत्रिकाओं में पाठक को आरंभ से अंत तक पलटना पड़ता है तथा किसी विशिष्ट वक्तव्य पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। व्यवसाय की दृष्टि से, दोनों ही विज्ञापन के आधार पर अपना मुनाफा कमाते हैं; समाचार पत्रों की तुलना में पत्रिकाओं के कुछ मजबूत फायदे हैं। हालांकि, पत्रिकाएँ अपने चमकदार पन्नों के कारण अपने पाठकों के बीच रिकॉल वैल्यू को आकर्षित करती हैं, जो अंततः समाचार पत्रों की उपलब्धता के कारण होता है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि समाचार पत्र दैनिक आधार पर जारी किए जाते हैं, वे साप्ताहिक पत्रिकाओं की तुलना में अधिक बिकते हैं।

इसके अतिरिक्त, पत्रिका का उत्पादन समाचार-पत्रों की तुलना में अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रिका को छापना एक बहुत ही सावधानीपूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है जो पृष्ठों के सटीक रंग और बनावट को प्रभावित करती है, जबकि समाचार पत्रों के लिए केवल एक प्रिंटिंग प्रेस और काली और नीली स्याही की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, इसका प्रभाव पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों की कीमत पर पड़ता है, क्योंकि पत्रिकाएं पत्रिकाओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं।

साहित्यिक लेखन की स्वतंत्रता समाचार पत्र और पत्रिका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। सामान्यतः, पत्रिका लेखकों के पास रचनात्मक ढंग से चीजों को अभिव्यक्त करने की लचीलापन और स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उनका काम रचनात्मक और मनोरंजक होना होता है, जबकि समाचार पत्र लेखक कुछ हद तक कठोर, मजबूत, औपचारिक होते हैं, और सीधे दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं, क्योंकि उनका लेखन ज्यादातर तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है।

चूंकि समाचार पत्र समाचार और सूचना का व्यापक दायरा प्रदान करते हैं, इसलिए उनका लक्षित पाठक वर्ग औपचारिक पत्रिकाओं की तुलना में अधिक व्यापक होता है, जिसमें युवा, वयस्क, पुरुष और महिलाएं शामिल होते हैं, जो उनकी विषय-वस्तु में रुचि रखते हैं। हालाँकि, पत्रिकाएँ विशिष्ट रुचियों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अर्थात यह केवल एक निश्चित लिंग या आयु वर्ग को लक्षित करती हैं, जिससे इसे खरीदने में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है